विशेष डिजिटल अंक

सच को समर्पित समाचार पत्रिका

4 मई 2020, मूल्य ₹ 25

आउटलुक

www.outlookhindi.com

- महा कोरोना सदमा
- शिव विश्वनाथन का नजरिया
- बेरोजगारी पर महेश व्यास

लॉकडाउन अर्थव्यवस्था

देश को भूख से बचाने वाली खेती-किसानी पर सबसे अधिक मार, राहत की दरकार

RNI NO. DELHIN/2009/26981

facebook.com/outlookhindi

twitter.com/outlookhindi

20 कोरोना संकट के बीच किसान

26 **डॉ. टी. हक:** किसानों को चाहिए मदद

27 **विजय सरदाना:** अफवाहों की मार

30 **इंटरव्यू:** आर.एस. सोढ़ी, एमडी, अमूल

31 **वी.एम. सिंह:** कुछ कदम अनिवार्य

06 **अमेरिका:** क्यों हटे बर्नी सैंडर्स

08 **जम्मू-कश्मीर:** दबाव में बदला फैसला

10 **शिव विश्वनाथन:** प्रवासी मजदूरों को भूल गए

47 **फिल्म:** बॉलीवुड की विदेशी टेंशन

बेरोजगारी और कारोबारी संकट

33 उद्योग के सामने श्रमिकों का संकट

36 नौकरियों पर खतरा वास्तविक

39 रोजगार संकट पर महेश व्यास से बातचीत

लॉकडाउन 2

12 लॉकडॉउन सबसे बड़ा सहारा

16 कोरोना पर एम्स डायरेक्टर से बातचीत

17 **पंजाब:** मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की रणनीति

18 **दिल्ली:** लॉकडाउन ही सहारा- सत्येंद्र जैन

19 **छत्तीसगढ़:** लड़ाई के साधन पर्याप्त- टीएस सिंहदेव

40 कोरोना संकट में अवसाद का साया घना

कवर फोटो: **त्रिभुवन तिवारी**

आउटलुक

संपादक: हरवीर सिंह
डिप्टी एडिटर: सुनील कुमार सिंह
एसोसिएट संपादक: प्रशांत श्रीवास्तव
वरिष्ठ सहायक संपादक: हरीश मानव
सहायक संपादक: के. के. कुलश्रेष्ठ, आकांक्षा पारे काशिव
वरिष्ठ कॉपी संपादक: सत्येन्द्र प्रकाश
विशेष संवाददाता: रवि भोई, कुमार भवेश चंद्र
संवाददाता: प्रतीक वर्मा
वेब टीम: आर.एस. राणा, शशिकांत वत्स, उपासना पांडेय, अक्षय दुबे
एडिटोरियल कंसल्टेंट: हरिमोहन मिश्र
डिजाइन: विमल सरकार (सीनियर आर्ट डायरेक्टर) रोहित कुमार राय (डिजाइनर), रंजीत सिंह (विजुअलाइजर)
फोटो सेक्शन: जितेंद्र गुप्ता (फोटो एडिटर), त्रिभुवन तिवारी (चीफ फोटोग्राफर), संदीपन चटर्जी, अपूर्व सलकड़े (सीनियर फोटोग्राफर) सुरेश कुमार पांडे (स्टाफ फोटोग्राफर) एस. रक्षित (चीफ फोटो कोऑर्डिनेटर), जे.एस. अधिकारी (सीनियर फोटो रिसर्चर)
संदर्भ: अलका गुप्ता

बिजनेस कार्यालय:
चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर: इंद्रनील रॉय
प्रकाशक: संदीप कुमार घोष
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट: मीनाक्षी आकाश
सीनियर जनरल मैनेजर: देववाणी टैगोर, शैलेन्द्र वोहरा
डिजिटल टीम: अमित मिश्रा
मार्केटिंग:
वाइस प्रेसिडेंट: श्रुतिका दीवान
सर्कुलेशन एंड सब्सक्रिप्शन: अनिंद्य बैनर्जी, गगन कोहली, जी. रमेश (साउथ), विनोद कुमार (नार्थ), अरुण कुमार झा (ईस्ट), शेखर सुवर्राना

प्रोडक्शन:
जनरल मैनेजर: शशांक दीक्षित
मैनेजर: सुधा शर्मा, गणेश साह (डिप्टी मैनेजर), गौरव श्रीवास (एसोसिएट मैनेजर)
अकाउंट:
वाइस प्रेसिडेंट: दीवान सिंह बिष्ट
कंपनी सेक्रेटरी एवं लॉ ऑफिसर: अंकित मंगल
प्रधान कार्यालय: ए.बी.-10 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
संपादकीय कार्यालय: ए.बी.-5 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-110029
टेलीफोन: 011-71280400, फैक्स: 26191420

संपादकीय ईमेल
edithindi@outlookindia.com
ग्राहकों के लिए संपर्क: 011-71280433, 71280462, 71280307
yourhelpline@outlookindia.com
अन्य कार्यालय:
मुंबई: 022-50990990
कोलकाता: 46004506, **फैक्स:** 46004506
चेन्नई: 42615224, 42615225 **फैक्स:** 42615095
बेंगलूरू: 43715021
संपादक हरवीर सिंह
आउटलुक पब्लिशिंग (इंडिया) प्रा.लि. की तरफ से इंद्रनील रॉय द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित। ए.बी.-10 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली से प्रकाशित।

कुल पृष्ठ संख्या 52 कवर सहित

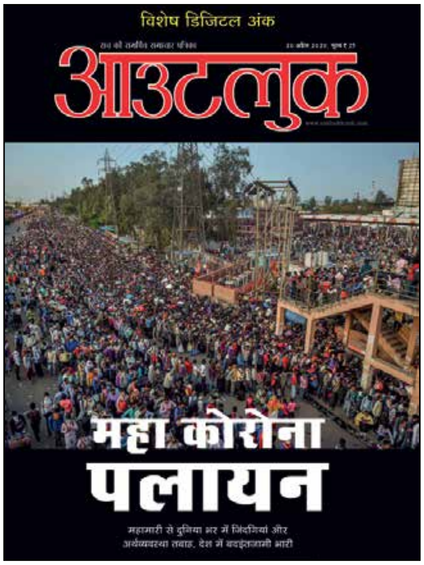

घर में रहें, सुरक्षित रहें

सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को समझना चाहिए कि सरकार हमारी भलाई के लिए ही घर में रहने को कह रही है। जो भी इस नियम को तोड़ कर बाहर निकल रहे हैं वे समाज के दूसरे लोगों को भी परेशानी में डाल सकते हैं। कोरोनावायरस से लड़ाई की डगर कठिन है। यह सच है कि लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं लेकिन फिर भी बेहतर हो कि हम सावधानी बरतें। जब तक देश में कोविड-19 का प्रकोप है, घर में रहना चाहिए।

राधेश्याम ताम्रकर | ठीकरी, मध्य प्रदेश

परीक्षा की घड़ी

आउटलुक के 6 अप्रैल 2020 के अंक में हरवीर सिंह की बात सही है कि पूरी दुनिया ऐसे दुष्चक्र में फंसी है जिससे निकलने के लिए असाधारण कदमों और उपायों की जरूरत है। कोविड-19 महामारी से निपटना चिकित्सकों और सरकार के साथ ही आम आदमी के लिए भी परीक्षा की घड़ी है। 'मंदिर के बाद एक और भूमि विवाद' रपट से यह जानकर दुख हुआ कि श्रीराम की मूर्ति लगाने के लिए ढाई सौ परिवारों को उजाड़ा जा रहा है। कुलदीप कुमार ने ठीक लिखा है कि आज के दौर में सभी पार्टियों ने तात्कालिक स्वार्थों के लिए मूल्यों और आदर्शों को तिलांजलि दे दी है। दलबदल के कारण लोकतंत्र का मखौल बन रहा है।

केशव राम सिंघल | अजमेर, राजस्थान

कठोरता से इलाज

लॉकडाउन में गरीबों को भोजन न मिलने पर प्रशांत भूषण ने जनहित याचिका दायर की है। अच्छा होता कि वे कोर्ट जाने के बजाय भूखों को भोजन कराते। इससे उन्हें भी पौष्टिक आहार नसीब होता। गरीब वैसे भी क्वारंटाइन और आइसोलेशन जैसे भारी-भरकम शब्दों से डरा हुआ है। इन लोगों को भोजन के साथ अच्छे व्यवहार की भी जरूरत है। जबकि कुछ लोग अस्पतालों से भाग-भाग कर समस्या को और बढ़ा रहे हैं। इससे संक्रमण बढ़ रहा है। सरकार को इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार सख्त नहीं होगी, तो लॉकडाउन का सौ फीसदी फायदा नहीं मिलेगा।

पार्थ सुनील कासार | धुले, महाराष्ट्र

पुरस्कृत पत्र

समाज का नुकसान

आउटलुक के 23 मार्च के अंक में पेश देश की राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों भड़के दंगे की भयावह और दर्दनाक तसवीर मानवता को शर्मशार करती है। लगातार दो दिनों तक जारी आगजनी, मार-काट, गोलीबारी और हिंसा में लगभग पचास बेकसूर लोगों की जानें गईं। सैकड़ों लोग घायल हुए। यह सब तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली आ रहे थे। ऐसे समय में तो व्यवस्था और चाक-चौबंद होनी चाहिए थी। पुलिस और प्रशासन में सक्रियता की कमी थी। जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर आपसी लड़ाई और वैमनस्य गहरे जख्म छोड़ जाते हैं। यह देश और समाज के लिए नुकसानदायक साबित होता है। 'धू धूकर जली जिंदगियां' और 'नफरत के शोलों का नया मंजर' शीर्षकों के लेख अच्छे लगे। अब डगमगाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की चुनौती हमारे सामने है।

युगल किशोर | रांची, झारखंड

अब आप अपने पत्र इस मेल पर भी भेज सकते हैं:
hindioutlook@outlookindia.com

श्रेष्ठ पत्र को उपहार स्वरूप 1000 रुपये मूल्य की पुस्तकें

सामयिक प्रकाशन
दरियागंज, नई दिल्ली-110002
samayikprakashan@gmail.com
www.samayikprakashan.com

तकनीकी विकास ने पत्र लेखन की विधा को हाशिए पर जरूर धकेला है, लेकिन यह विधा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पत्र लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए आउटलुक हिंदी पत्रिका अपने पाठकों के लिए एक योजना ला रही है। किसी भी पत्रिका के लिए प्रतिक्रिया स्वरूप मिलने वाले पाठकों के पत्र महत्वपूर्ण होते हैं। आउटलुक हिंदी पत्रिका में प्रकाशित लेखों पर 150 शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया भेजें और पाएं हिंदी के प्रतिष्ठित सामयिक प्रकाशन की ओर से एक हजार रुपये मूल्य की पुस्तकें। हर अंक में छपने वाले पत्रों में से एक सर्वश्रेष्ठ पत्र चुना जाएगा।

ध्यान रखें कि पत्र साफ लिखे गए हों और लंबे न हों। संबंधित लेख का उल्लेख जरूर करें और अपनी टिप्पणी सटीक रखें। चुने गए पत्र पत्रिका में प्रकाशित किए जाएंगे। अपना नाम एवं पिन कोड सहित पूरा पता जरूर लिखें। संपादकीय निर्णय सर्वोपरि होगा।

आउटलुक पत्रिका प्राप्त करने के स्थान

दक्षिणः **हैदराबाद** यादगिरी बुक स्टॉल, 040-66764498, **सिकंदराबाद** उस्मान बुक स्टॉल, 9912850566

उत्तरः **दिल्ली** - आईबीएच बुक्स एंड मैग्जीन डिस्ट्रिब्यूटर्स, 011-43717798,011-43717799, **लखनऊ** - सुभाष पुस्तक भंडार प्रा. लिमिटेड, 9839022871, **चंडीगढ़** - पुरी न्यूज एजेंसी, 9888057364, **देहरादून**- आदित्य न्यूज एजेंसी, 9412349259, **भोपाल**- इंडियन न्यूज एजेंसी, 9826313349, **रायपुर**- मुकुंद पारेख न्यूज एजेंसी, 9827145302, **जयपुर**-नवरत्न बुक सेलर, 9829373912, **जम्मू**- प्रीमियर न्यूज एजेंसी, 9419109550, **श्रीनगर**- जेपी न्यूज एजेंसी, 9419066192, **दुर्ग (छत्तीसगढ़)** - खेमका न्यूज एजेंसी, 9329023923

पूर्वः **पटना**- ईस्टर्न न्यूज एजेंसी, 9334115121, **बरौनी** -ज्योति कुमार दत्ता न्यूजपेपर एजेंट, 9431211440, **मुजफ्फरपुर**-अन्नू मैग्जीन सेंटर, 9386012097, **मोतीहारी**- अंकित मैग्जीन सेंटर, 9572423057, **कोलकाता**- विशाल बुक सेंटर, 22523709/22523564, **रांची**- मॉडर्न न्यूज एजेंसी, 9835329939, रवि कुमार सोनी, 9431564687, **जमशेदपुर**-प्रसाद मैग्जीन सेंटर, 2420086, **बोकारो**-त्रिलोकी सिंह, 9334911785,**भुवनेश्वर**-ए. के. नायक, 9861046179, **गुवाहाटी**- दुर्गा न्यूज एजेंसीज, 9435049511

पश्चिमः **नागपुर**-नेशनल बुक सेंटर, 8007290786, पाठक ब्रदर्स, 9823125806, **नासिक**- पाठक ब्रदर्स, 0253-2506898, **पुणे**- संदेश एन एस एजेंसी, 020-66021340,**अहमदाबाद**-के वी अजमेरा एंड संस, 079-25510360/25503836, **मुंबई**- दंगत न्यूज एजेंसी, 22017494

हकीकत तो कुछ और

हरवीर सिंह

इस समय समूची दुनिया और हमारा देश कोविड-19 महामारी से जीतने की जंग लड़ रहा है। इसके लिए सबसे प्रभावी कदम के रूप में 25 मार्च से लागू 21 दिन के लॉकडाउन को अब सरकार ने 3 मई तक बढ़ा दिया है। अब लॉकडाउन 40 दिन का हो गया है। कुछ राज्यों में इसकी अवधि अधिक होगी, क्योंकि वहां 22 मार्च के 'जनता कर्फ्यू' या उसके एकाध दिन पहले से ही लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। यह लॉकडाउन दुनिया में सबसे बड़ा और सख्त माना जा रहा है, इसलिए इसकी कीमत भी हमें दूसरों से ज्यादा चुकानी पड़ रही है। भविष्य में भी कीमत चुकाने का यह दौर जारी रहेगा, क्योंकि देश में चुनिंदा क्षेत्रों को छोड़कर तमाम आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई हैं।

पहले लॉकडाउन की अवधि के बीच में ही प्रधानमंत्री ने अपना नारा 'जान है तो जहान है' से बदलकर 'जान भी जहान भी' कर दिया। देश के लोगों, खासकर सबसे गरीब और कमजोर वर्ग पर बेरोजगारी और भुखमरी की मार कुछ हद तक दिखने लगी थी। कामकाजी आबादी के इस 90 फीसदी वर्ग के पास न कोई सामाजिक सुरक्षा है, न आर्थिक सुरक्षा। इसलिए प्रशासनिक मशीनरी और नेताओं को समझना चाहिए था कि लॉकडाउन के मायने देश की सारी जनता के लिए एक से नहीं होते। किसी संपन्न शहरी इलाके और हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले मध्य वर्ग और बेहतर आय स्रोत वाले लोगों के मुकाबले गरीबों, प्रवासी मजदूरों और कामगारों के लिए लॉकडाउन के मायने अलग हैं। यही वजह है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के साथ ही मुंबई और सूरत जैसे शहरों में प्रवासी मजदूरों के धैर्य ने जवाब दे दिया। वे अपने गांव-घर जाने की मांग के साथ सड़क पर उतर आए। इस तरह के वाकये केंद्र और राज्य सरकारों के देश के हर आदमी का खयाल रखने के दावों की भी पोल खोलते हैं। लगभग भुखमरी और पैसे की तंगी झेल रहे गरीब तबके से जुड़ी खबरें लगातार बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल के संबोधन में कहा कि यह तबका उनका परिवार है और उनका उन्हें सबसे अधिक खयाल है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है।

सोशल डिस्टेंसिंग या लोगों के मेलजोल या आवाजाही रोकने की रणनीति इसलिए भी सही कही जा सकती है क्योंकि हमारे पास चिकित्सा संसाधन और ढांचागत सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। पहले 21 दिन के लॉकडाउन ने केंद्र और राज्य सरकारों को बीमारी के किसी बड़े खतरे में तब्दील होने के पहले तैयारियां करने और इसके हॉटस्पॉट चिह्नित करने का मौका दिया है। लेकिन सही स्थिति का आकलन करने के लिए देश के अधिकांश राज्यों में टेस्ट की संख्या बहुत सीमित है। अभी तक हम प्रति दस लाख लोगों में केवल 176 टेस्ट के औसत पर ही आ पाए हैं जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 8,900 टेस्ट का है।

दूसरी ओर, महामारी और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था भीषण संकट में फंस गई है। अभी तक सरकार की तरफ से तो कोई आधिकारिक आकलन नहीं आया है लेकिन वैश्विक संस्थाओं के आकलन चिंता बढ़ाने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का कहना है कि चालू साल में भारत की जीडीपी वृद्धि दर गिरकर 1.9 फीसदी रह जाएगी, विश्व बैंक ने इसके 1.6 से 2.8 फीसदी के बीच रहने का अनुमान लगाया है। आइएमएफ के मुताबिक, 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था तीन फीसदी सिकुड़ जाएगी। बार्कलेज रिसर्च का कहना है कि 2020 में भारत की विकास दर शून्य हो जाएगी तो 'नोमुरा' ने शून्य से भी आधा फीसदी नीचे जाने का अनुमान जारी किया है। एक रिसर्च संस्थान का आकलन है कि एक सप्ताह के लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था का नुकसान करीब 26 अरब डॉलर का है। सरकार ने 15 अप्रैल को जो गाइडलाइन जारी की हैं, उनमें शर्तों के साथ 20 अप्रैल से चुनिंदा आर्थिक गतिविधियां खोलने की बात है। विशेषज्ञों का मानना है कि आम आदमी के साथ ही कृषि और इकोनॉमी के दूसरे क्षेत्रों के लिए आठ से दस लाख करोड़ रुपये के पैकेज की फौरन जरूरत है। दुनिया के अधिकांश देशों ने काफी बड़े और समग्र पैकेज घोषित किए हैं, लेकिन हमारी सरकार ने कोई खास पैकेज का ऐलान नहीं किया है। राज्यों को जीएसटी और अन्य मदों में देय राशि भी पूरी तरह मुहैया नहीं करा पा रही है, ताकि वे महामारी से जंग में कुछ सबल हो सकें।

जिस हाल में हमारी अर्थव्यवस्था पहले से ही पहुंच गई थी, इस झटके के बाद उसे मंदी से बचाना काफी मुश्किल है। कुछ विशेषज्ञ इसे 1979-80 के दौर जैसी बता रहे हैं, तो दुनिया में 1930 की महामंदी का हवाला दिया जा रहा है। इससे पहले कि हम इस पर गौर करते, एक दूसरी ही कोशिश शुरू हो गई। जिस तरह से कई जगहों पर अल्पसंख्यकों पर हमले, उनके कारोबारी हितों पर चोट और एक अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों को धर्म के आधार पर बंटे वार्ड में रखने की खबरें आई हैं, वह महामारी से लड़ने में देश की एकजुटता को कमजोर करने वाली हैं। इस मोर्चे पर सरकार को सख्ती अपनानी चाहिए और इस तरह के विभाजन पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए।

मुंबई और सूरत जैसे वाकये देश के हर आदमी का खयाल रखने के केंद्र और राज्य सरकारों के दावों की पोल खोलते हैं, प्रधानमंत्री ने भी गरीब तबके को अपना परिवार बताया पर हकीकत अलग

@harvirpanwar

कोरोना संकट अभूतपूर्व है, लोगों के जीवन और आजीविका पर प्रभाव को लेकर अनिश्चितता है। ग्रेट लॉकडाउन 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद की सबसे बड़ी मंदी लाएगा। आर्थिक हालात 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से भी ज्यादा खराब होंगे

गीता गोपीनाथ, चीफ इकोनॉमिस्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

समय का खेल

शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के मुख्यमंत्री की कमान संभालते ही अफसरों पर तलवार चलानी शुरू कर दी। सबसे पहले मुख्य सचिव को बदल दिया और अपनी पसंद के अफसर को ले आए। अफसरों का आना-जाना लगा रहता है, पर कमलनाथ के नियुक्त अफसर को एक हफ्ते में मुख्य सचिव की कुर्सी छोड़नी पड़ी, यह एक रिकॉर्ड है। पिछली सरकार में खास रहीं दो महिला अफसरों को भी शिवराज ने किनारे कर दिया। बड़े पुलिस अधिकारी भी हटा दिए। अब कांग्रेस शिवराज पर तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगा रही है। कमलनाथ के राज में यही आरोप भाजपा नेता लगाया करते थे। यह तो समय का खेल है।

कोरोना की सियासत

दिल्ली सरकार ने आजादपुर फल और सब्जी मंडी में आने वाले लोगों के लिए नियम बदल दिए हैं। इसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारी खफा हैं। उनका कहना है कि सुबह का समय सब्जी के लिए और शाम का समय फलों के लिए रखा गया है। अब दिल्ली सरकार को इतनी सी बात समझ नहीं आती कि अधिकांश करोबारी और रिटेल नेटवर्क फल और सब्जी दोनों का काम करते हैं लॉकडाउन और महामारी के दौर में वह दो बार मंडी कैसे आएंगे। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वैसे मंत्रालय के कॉरीडार में तो कहा जा रहा है कि सब्जी वाले राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी के करीबी माने जाते हैं, इसलिए उनके हित पहले जबकि फल वालों को भाजपा का करीबी माना जाता है। अब इस तरह के माहौल में भी राजनीति करना ठीक तो नहीं है। लेकिन राजनीति करने वाले कोई मौका नहीं छोड़ते हैं।

संकट में भी उनकी बल्ले-बल्ले

कोरोना संक्रमण से कई लोगों पर पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनकी किस्मत चमक गई। छत्तीसगढ़ में ऐसे ही एक आइएएस अधिकारी हैं, जो पिछले 15 महीने से परिदृश्य से गायब थे और लोग उनके सस्पेंड होने का कयास लगा रहे थे। ये अधिकारी पिछली सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में थे। भूपेश सरकार ने उन्हें याद करना ही छोड़ दिया था। लेकिन सरकार को अचानक कोरोना संकट में उनकी याद आ गई और उन्हें कोरोनावायरस से निपटने वाले विभाग में ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। कहते हैं कि बुरा समय भी किसी-किसी के लिए शुभ समाचार लेकर आता है।

हेल्थ मंत्री की सेहत

कोरोना ने यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह को ऐसा जकड़ा कि वे अपने स्वास्थ्य की चर्चा छोड़कर कहीं भी नजर ही नहीं आ रहे हैं। कोरोना की आशंका से घिरे मंत्री जी अब स्वस्थ बताए जा रहे हैं पर लगता है कि महकमे पर उनकी डोर कमजोर हो गई है। उनकी कमी पूरी कर रहे हैं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना। उन्हें न केवल मुख्यमंत्री के साथ बैठकों में देखा जा रहा है बल्कि मेडिकल कालेज अस्पतालों में भी दौरे कर रहे हैं। सिंगर कनिका कपूर की पार्टी में शिरकत से चर्चित हुए मंत्री के सियासी भविष्य पर अब मीडिया की पैनी नजर है।

कोरोना काल में योगी का परहेज

क्या कोरोना संक्रमण काल में काम करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कुछ मंत्रियों से दूरी रख रहे हैं? पॉवर कॉरीडोर में चर्चा तेज है। कोरोना को यूपी में हराने के लिए सीएम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे सुबह अफसरों की बैठक लेते हैं तो शाम को फील्ड में समीक्षा करते हैं। कई जिलों के दौरे करके भी सीएम ने अफसरों को कसकर रखा है। लेकिन चर्चा जोरों पर है कि सीएम ने एकाध मंत्री को छोड़कर किसी को इस काम में लगाने की जरूरत ही नहीं समझी।

आखिर क्यों कटे-कटे हैं मंत्री जी

देश और प्रदेश में कोरोना संकट मंडरा रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ के एक मंत्री जी मुंबई चले गए। मुंबई से ही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। इस पर हल्ला मचा तो वे आए, पर हाथ में क्वारंटाइन की सील लगवाकर। कोरोना के रोकथाम अभियान में मंत्री जी को अहम भूमिका निभानी थी, लेकिन पहली बैठक में ही मंत्री जी को नहीं बुलाया गया। अब बैठक में बुलाया भी जाएगा, तो क्वारंटाइन के नाते नहीं जाएंगे। चर्चा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

क्रांतिकारी विचारक: बर्नी सैंडर्स चुनाव में पीछे हटे पर असर बदस्तूर कायम

सैंडर्स के पीछे हटने के मायने

डेमोक्रेटिक पार्टी के ओहदेदारों में बहुत कम सैंडर्स की वामपंथी राजनीति के प्रशंसक, मगर कोरोना के बाद के दौर में उनके विचार प्रासंगिक रहेंगे

प्रणय शर्मा

अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं का दायरा अमेरिका से बाहर भी होता तो शायद बर्नी सैंडर्स को अगला राष्ट्रपति बनने से रोकना मुश्किल हो जाता। लेकिन 78 साल के इस डेमोक्रेट उम्मीदवार ने 8 अप्रैल को चुनावी दौड़ से अपना नाम वापस ले लिया। इससे यह बात एक बार फिर साबित हुई कि डेमोक्रेटिक पार्टी के ओहदेदारों में बहुत कम लोग हैं जो बर्नी सैंडर्स की राजनीति को पसंद करते हैं। दरअसल, उनकी राजनीति अमेरिकी नागरिकों के नजरिए में आमूलचूल बदलाव लाने वाली है।

अमेरिकी प्रांत वरमोंट के सीनेटर सैंडर्स दुनिया के इस सबसे अमीर देश में अमीर-गरीब के बीच बढ़ती खाई के घोर आलोचक हैं। उन्होंने अमीरों पर ज्यादा कर का बोझ डालने और सबके लिए बेसिक यूनिवर्सल हेल्थकेयर के पक्ष में लगातार प्रचार किया है। सैंडर्स लाखों करोड़ डॉलर के एजुकेशन और मेडिकल लोन माफ करने की मांग करते रहे हैं। उनकी इन मांगों ने न सिर्फ उनकी अपनी पार्टी में, बल्कि दूसरों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन जो बात सबसे अधिक असर पैदा कर रही थी, वह थी गैर-बराबरी के पुराने और शाश्वत मुद्दे को बार-बार उठाना। सभी चुनावी रैलियों में चुनिंदा अमीरों और बड़ी तादाद में गरीब अमेरिकियों के बीच संपत्ति के अंतर को वे प्रमुखता से उठाते रहे हैं। ऐसे समय जब लोग पूंजीवादी व्यवस्था के फायदे पर सवाल उठा रहे हैं और ज्यादा समानता वाले विश्व की मांग कर रहे हैं, उनके वामपंथी विचारों से लोगों का आकर्षित होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। सर्वेक्षण के नतीजे बताते हैं कि 20 साल से कम उम्र के जो मौजूदा मतदाता हैं, वे अपनी पिछली पीढ़ी की

तुलना में समाजवाद को ज्यादा पसंद करते हैं।

सैंडर्स बड़ी अमेरिकी कंपनियों, अरबपतियों और वॉल स्ट्रीट की आलोचना करते रहे हैं। बड़ी संख्या में अमेरिकी मतदाता, खासकर युवा, उनके विचारों से प्रभावित हैं। यही नहीं, अमेरिका से बाहर भी उनके प्रशंसक काफी हैं। यहां तक कि बहुत से युवा भारतीय भी चाहते थे कि अगर अनुमति मिले तो वे अमेरिका जाकर बर्नी सैंडर्स के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे।

इसमें कोई संदेह नहीं कि बराक ओबामा के बाद अमेरिका का कोई अन्य नेता दुनिया के दूसरे देशों में उतना नहीं पसंद किया गया, जितना बर्नी सैंडर्स को लोगों ने पसंद किया। लेकिन सैंडर्स और ओबामा के बीच काफी अंतर है। ओबामा अफ्रीकी-अमेरिकी मूल के, अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। वे युवा, स्पष्टवादी और बेहतरीन वक्ता थे। हर मौके पर अपने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। तुलनात्मक रूप से देखें तो सैंडर्स बिलकुल विपरीत प्रकृति वाले व्यक्ति हैं। वे वृद्ध हैं, 78 साल के सैंडर्स सभी प्रत्याशियों से ज्यादा उम्र के और श्वेत हैं, ओबामा की तरह वे मध्यमार्गी भी नहीं हैं। वे ऐसे क्रांतिकारी हैं जो अपनी वामपंथी विचारधारा को व्यक्त करने से डरता नहीं। किसी प्रोफेसर की तरह भाषणों में उनका लहजा उपदेशात्मक रहता है, ओबामा की तरह वे मनमोहक वक्ता नहीं हैं। दोनों के बीच एक और बड़ा अंतर यह है कि बर्नी सैंडर्स अफ्रीकी-अमेरिकी मतदाताओं को अपनी तरफ खींचने में विफल रहे। हालांकि उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं और अधेड़ उम्र के कामकाजी वर्ग को प्रभावित किया। वास्तव में देखा जाए तो अश्वेत लोगों का समर्थन नहीं मिलना, उनके पीछे हटने की एक बड़ी वजह हो सकती है, बावजूद इसके कि वे लंबे समय तक डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशियों में सबसे आगे रहे।

नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बर्नी सैंडर्स को राज्यों में काफी प्राइमरी वोट मिले थे। आयोवा, न्यू हैंपशायर और नेवादा में फरवरी में हुई वोटिंग में उन्होंने काफी दमदार प्रदर्शन किया था, लेकिन साउथ कैरोलिना में राजनीतिक माहौल उनके खिलाफ बनने लगा, जिसका फायदा उन्हीं की पार्टी के दूसरे प्रत्याशी जो बिडेन को मिला। एक समय था जब एमी क्लोबूचर, पीट बुटिगिएग, माइक ब्लूमबर्ग और एलिजाबेथ वारेन भी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से अपनी-अपनी उम्मीदवारी जता रही थीं, लेकिन अंततः यह रेस दो श्वेत पुरुषों के बीच रह गई। वॉशिंगटन, फ्लोरिडा, मिशिगन और टेक्सास जैसे कई राज्यों के सेंटर-राइट डेमोक्रेटिक नेता अचानक जो बिडेन के पक्ष में आ गए। तर्क दिया गया कि जब प्रत्याशियों की संख्या अधिक थी तब सैंडर्स का प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन जब रेस उनके और बिडेन के बीच रह गई, तब उनका प्रदर्शन उतना बढ़िया नहीं रह गया।

जो बिडेन के सामने बर्नी सैंडर्स के हार मानने की एक और प्रमुख वजह यह मानी जाती है कि राज्यों में हुए महत्वपूर्ण प्रिलिमिनरी चुनाव में युवा डेमोक्रेट समर्थक बहुत कम आए। चुनावी नतीजों से पता चलता है कि 18 से 38 साल के आयु वर्ग वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के प्राइमरी मतदाताओं में 50 फीसदी से अधिक की पहली पसंद सैंडर्स थे। प्रत्येक राज्य में उन्हें युवाओं का वोट हासिल हुआ था। लेकिन सुपर ट्यूजडे को हुए मतदान में युवा मतदाताओं ने कम भाग लिया और बिडेन ने 14 में से 10 राज्यों में जीत हासिल कर ली।

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी चुनाव में युवा मतदाता हमेशा कम संख्या में भाग लेते रहे हैं।

सैंडर्स बड़ी अमेरिकी कंपनियों, अरबपतियों और वॉल स्ट्रीट के आलोचक रहे हैं। अमेरिकी युवा तो उनके विचारों से प्रभावित हैं ही, अमेरिका से बाहर भी उनके प्रशंसक काफी हैं

उनका कहना है कि अमेरिका के किसी भी चुनाव में देखें तो युवा मतदाता, बुजुर्गों की तुलना में कम संख्या में वोट देते हैं। ऐसा 1972 में भी हुआ था, जब 26वें संशोधन के जरिए वोट डालने की न्यूनतम उम्र सीमा घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। युवा मतदाताओं के कम संख्या में वोट देने का एक बड़ा कारण पार्टी के प्रिलिमिनरी चुनाव की जटिल प्रक्रिया को माना जाता है। अभी तक बहुत कम नेताओं ने इस जटिलता के बारे में युवा मतदाताओं को समझाने का प्रयास किया है। इसी का नतीजा रहा कि जो युवा सैंडर्स की रैली में पहले पहुंचते थे और उनके क्रांतिकारी विचारों पर प्रफुल्लित होते थे, ऐन चुनाव के दिन उनमें से बहुत थोड़े ही मतदान के लिए निकले।

बर्नी सैंडर्स डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं। वे एकमात्र अमेरिकी नेता हैं जिन्होंने अपना हनीमून सोवियत संघ में मनाया। सैंडर्स के साथ ऐसा दूसरी बार हुआ है जब डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन हासिल करने में उनका जबरदस्त विरोध हुआ हो। चार साल पहले भी जब हिलेरी क्लिंटन पार्टी की पसंदीदा उम्मीदवार थीं, तब पार्टी ने इस बात की हर मुमकिन कोशिश की थी कि सैंडर्स राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार न बनें। डेमोक्रेटिक पार्टी की इस आपसी लड़ाई से रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत की राह आसान हो गई। पिछले चुनाव में बर्नी सैंडर्स के हर आठ में से एक समर्थक ने ट्रंप के पक्ष में मतदान किया। कुछ लोगों को डर है कि इस वर्ष नवंबर में होने वाले चुनाव में भी ऐसा हो सकता है। शायद इसी को रोकने के लिए जो बिडेन ने बर्नी सैंडर्स और उनके समर्थकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सैंडर्स ने एक राजनीतिक प्रचार ही नहीं चलाया, बल्कि उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। ईमानदार और न्यायोचित अमेरिका की शक्तिशाली आवाज बनने के लिए उन्होंने सैंडर्स का धन्यवाद भी किया।

अब सवाल है कि जो बर्नी सैंडर्स अपनी राजनीतिक विचारधारा को कभी व्यक्त करने से डरते नहीं थे, वे अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं। जाने-माने टिप्पणीकार एड ल्यूस ने पिछले महीने *फाइनेंशियल टाइम्स* में लिखा था, "सैंडर्स चाहे जिस बात पर बिडेन के खिलाफ लड़ाई में पीछे हटें, अमेरिका के वामपंथियों में एक कसक रह जाएगी।"

पिछली शताब्दी की शुरुआत में समाजवाद अमेरिका में एक लोकप्रिय विचारधारा थी, लेकिन बाद के वर्षों में धीरे-धीरे यह खत्म होती गई। बोलशेविक क्रांति के बाद जब मॉस्को में पहली समाजवादी सरकार बनी तब अमेरिका में समाजवादी विचारधारा को देशद्रोह जैसा समझा जाने लगा। लेकिन क्या अब यह विचारधारा दुनिया के सबसे बड़े पूंजीवादी देश में लौट रही है? पर्यवेक्षकों का मानना है कि सैंडर्स भले ही चुनावी रेस से बाहर हो गए हों, उनके बहुत से विचार अलग-अलग रूपों में डेमोक्रेटिक पार्टी के एजेंडे का हिस्सा बन चुके हैं।

कोविड-19 वैश्विक महामारी का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, इस पर संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट कहती है, "इससे दुनिया भर में करीब एक सौ करोड़ नौकरियां जा सकती हैं।" बिलाशक, यह देखने लायक होगा कि इस उभरते परिदृश्य में वरमोंट के सीनेटर के क्रांतिकारी विचार कोविड-19 के घाव से दागदार समाज के बीच संतुलन बनाने में अमेरिकी नीति-निर्माताओं को कितना परेशान करेंगे?

जम्मू ने जीती पहली लड़ाई

आक्रोश देखकर भाजपा सरकार को नौकरियों में आरक्षण पर नई नीति बनानी पड़ी

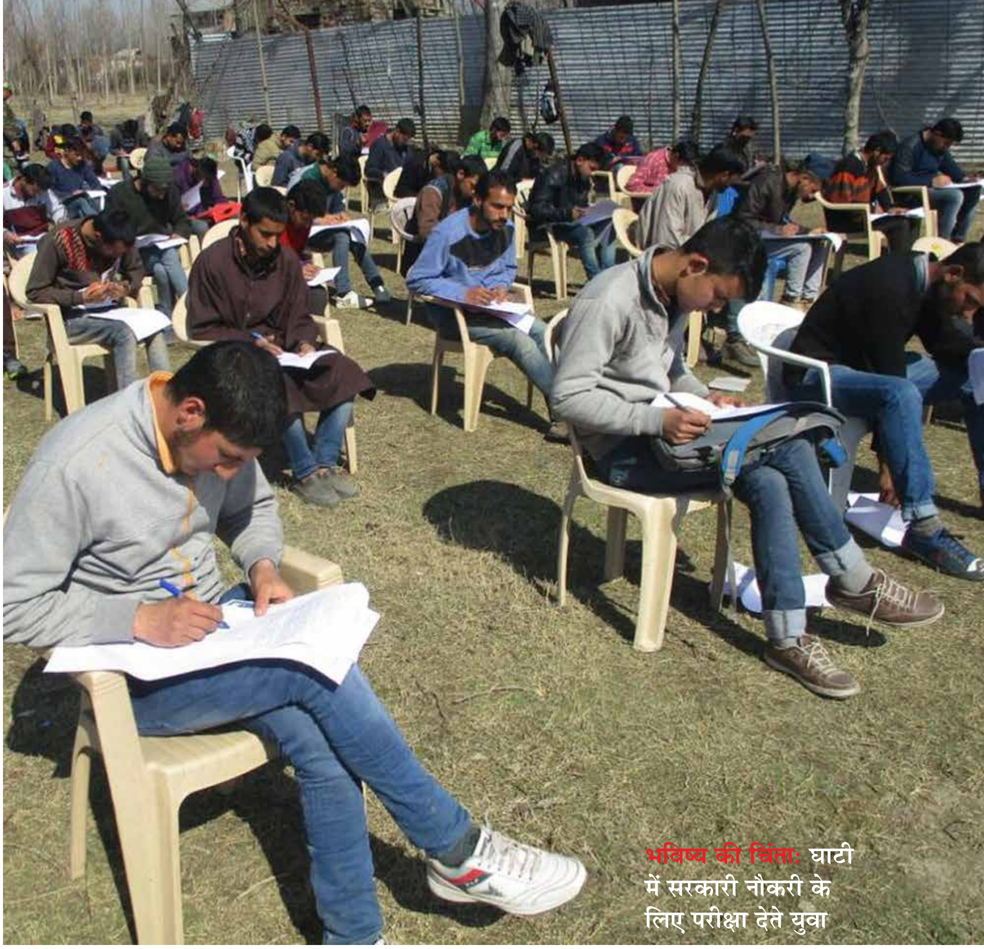

भविष्य की चिंताः घाटी में सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा देते युवा

श्रीनगर से **नसीर गनई**

अनुच्छेद 370 और 35ए को निष्क्रिय करने के आठ महीने बाद कोविड-19 महामारी के बीच 31 मार्च की रात को केंद्र सरकार ने प्रशासनिक आदेश के जरिए एक कानून को अधिसूचित किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर के निवासी होने और सरकारी नौकरियों में पात्रता की परिभाषा तय की गई। इससे कश्मीर में भारी निराशा फैल गई और जम्मू क्षेत्र में गुस्सा भड़क गया। इस आदेश में तय किया गया कि जो लोग जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में पिछले 15 साल से रह रहे हैं या फिर जिन्होंने जम्मू-कश्मीर में स्थित किसी शिक्षण संस्थान से 10वीं या 12वीं की परीक्षा दी है और सात साल तक यहां अध्ययन किया है, उन्हें स्थानीय निवासी माना जाएगा। लेकिन इस कानून में ग्रुप 4 यानी चपरासी जैसी नौकरियां ही स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित की गईं और बाकी नौकरियां देश भर के उम्मीदवारों के लिए खोल दी गईं।

कभी राज्य रहे और बाद में दर्जा घटाकर केंद्रशासित क्षेत्र बनाए गए जम्मू-कश्मीर के कानूनों के स्थान पर यह आदेश जारी हुआ है। केंद्र ने राज्य के 109 कानूनों में संशोधन और 29 कानूनों को खत्म किया है। सरकार ने 'जेऐंडके के स्थायी निवासी' के स्थान पर 'जेऐंडके यूनियन टेरीटरी के निवासी' कर दिया। इस संशोधन के दूरगामी नतीजे होंगे।

समूचे जम्मू में लोग इससे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। जम्मू के युवाओं ने असंतोष जताने के लिए सोशल मीडिया अभियान शुरू कर दिया। जम्मू की एक युवती अंकिता शर्मा ने फेसबुक पर अपने पांच मिनट के वीडियो में इस आदेश को लोगों का अपमान बताया। अंकिता ने कहा, "हमारा बार-बार अपमान किया जा रहा है। सबसे बड़ा अपमान तब किया गया जब कभी भी ब्रिटिशराज के अधीन नहीं रहे जम्मू-कश्मीर का दर्जा घटाकर यूटी बना दिया गया और हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हम चुप रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्षेत्र में तेज विकास होगा। डोमिसाइल कानून जेऐंडके के युवाओं के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। आप सोचते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे, तो आप गलत हैं।" उसने कहा कि भाजपा जेऐंडके को इस क्षेत्र से बाहर वोट मशीन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अब लोग चुप नहीं रहेंगे। वह कहती है, "यह हिंदू-मुस्लिम का मामला नहीं है। यह हमारे सामूहिक भविष्य और हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है। हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे।"

इस वीडियो और इसी तरह के दूसरे पोस्ट को जम्मू-कश्मीर में भारी समर्थन मिला, जिसके कारण भाजपा के स्थानीय नेतृत्व को उन लोगों को चुप कराना पड़ा, जो केंद्रीय नेतृत्व को गुपचुप तरीके से गुस्सा शांत करने के लिए कदम उठाने की सलाह दे रहे थे। सोशल मीडिया पोस्ट में जम्मू के युवक मांग कर रहे हैं कि जेऐंडके में सिर्फ उन लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया जाए, जो 25 साल या इससे अधिक समय से यहां रह रहे हैं।

भारी दबाव के चलते केंद्र सरकार को तीन अप्रैल की शाम को संशोधन लाना पड़ा, जिसके अनुसार सरकारी नौकरियां जेऐंडके के निवासियों के लिए आरक्षित कर दी गईं। पिछले साल पांच अगस्त से पहले जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए प्रभावी थे, उस समय तत्कालीन राज्य की सभी नौकरियां जेऐंडके के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित थीं। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान था, जो जम्मू-कश्मीर का संविधान कहलाता था जबकि अनुच्छेद 35ए बाहर के लोगों को जम्मू-कश्मीर में संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित करता था और स्थायी निवासियों के लिए नौकरियों में आरक्षण सुनिश्चित करता था। अनुच्छेद 35ए जेऐंडके सरकार को तत्कालीन राज्य के स्थायी निवासी का दर्जा देने के लिए लोगों का वर्गीकरण करने और सरकारी नौकरियों और अचल संपत्ति

कोरोना के बहाने पेड़ों पर निशाना

कोरोनावायरस का नवीनतम वाहक कौन है? अगर कश्मीर घाटी के अधिकारियों की मानें तो विदेशी प्रजाति के पॉपलर के पेड़ कोरोना फैला सकते हैं। दक्षिणी कश्मीर में अनंतनाग जिले के जिलाधिकारी ने सभी मादा 'रशियन पॉपलर ट्री' की कटाई करने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी के अनुसार, बसंत ऋतु आने वाली है। पेड़ से रोएंदार पराग कण गिरकर हवा में तैरने लगते हैं। किसी भी सतह को छूकर हल्की सी हवा में वे दोबारा उड़ने लगते हैं। इस तरह उनसे कोरोना का संक्रमण एक से दूसरे स्थान पर फैलने का खतरा है।

पेड़ मालिकों को कटाई करने के लिए कहा गया है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने पुलिस और वन विभाग को आदेश लागू करवाने का निर्देश दिया है।

कश्मीर घाटी में ये पेड़ उगाने की शुरुआत 1982 में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत हुई थी। रशियन पॉपलर नाम का यह पेड़ पश्चिमी अमेरिका की प्रजाति का है जिसे अमेरिका में ईस्टर्न कॉटनवुड कहते हैं। कश्मीर में लोग देसी के प्रजाति के बजाय इसे उगाना पसंद करते हैं क्योंकि इसका विकास तेजी से होता है। तीन साल में पेड़ 20 से 30 फुट लंबा हो जाता है और इसकी आयु 40 साल होती है। इसका इस्तेमाल मुख्य तौर पर फलों की पैकेजिंग के लिए बॉक्स बनाने में किया जाता है। क्षेत्र में 1.5 करोड़ पेड़ होने का अनुमान है।

पहली बार नहीं है, जब इस पेड़ को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया है। 2014 में हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में इन पेड़ों को काटने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा, "कश्मीर में इन पेड़ों के पराग कणों से सांस की बीमारियां होती हैं जो जानलेवा हो सकती हैं।" इसके बाद श्रीनगर और अन्य जिलों में लाखों पेड़ काटे गए। हालांकि कई विशेषज्ञ कहते हैं कि अप्रैल-मई में पॉपलरों पेड़ों से एलर्जी होने के कोई सबूत नहीं हैं। इस आशंका का भी कोई सबूत नहीं है कि इससे कोरोनावायरस फैल सकता है।

खरीद में लोगों को विशेषाधिकार देने के लिए सरकार को अधिकार देता था।

राजौरी के कांग्रेस नेता शाफीक मीर कहते हैं, "डोमिसाइल कानून में संशोधन कर दिया गया है। अब नौकरियां जेऐंडके के निवासियों के लिए आरक्षित होंगी, न कि यहां के स्थायी निवासियों के लिए। जेएंडके की नौकरियां सभी के लिए उपलब्ध हो गई हैं।" मीर, जो जेऐंडके पंचायत एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, कहते हैं, "हमने जम्मू के युवाओं में गुस्सा देखा है। हर कोई ठगा हुआ महसूस कर रहा है।" भाजपा खुद को मुश्किल में देख रही है और वह केंद्रीय नेतृत्व से नियम बदलने का अनुरोध कर रही है। कठुआ में एक वर्ग के लोगों ने भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया।

अपने दक्षिणपंथी विचार के लिए मशहूर जम्मू के वकील अंकुर शर्मा भाजपा पर धोखा देने और तीन दिन के भीतर ही डोमिसाइल कानून बदलकर अलगाववादी ताकतों के आगे झुकने का आरोप लगाते है। शर्मा ने *आउटलुक* को बताया, "जम्मू जेऐंडके के बाकी भारत में पूरी तरह शामिल होने का पक्षधर था। डोमिसाइल कानून विस्तृत रणनीति का हिस्सा था। लेकिन भाजपा अलगाववादियों और पाकिस्तान के सामने झुक गई।" पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने डोमिसाइल कानून की आलोचना की है। पाक पीएम इसे जेऐंडके में अवैध रूप से आबादी का स्वरूप बदलने के प्रयास के तौर पर "हिंदूवादी मोदी सरकार" का कदम बताया।

अंदेशा: वायरस के नाम पर पॉपलर पर कुल्हाड़ी

जम्मू के लेखक जफर चौधरी कहते हैं, "ऐसे मुद्दों पर पाकिस्तान का चिंता जताना समस्याएं पैदा करता है और दक्षिणपंथी ताकतें विरोध प्रदर्शन करने के लोगों के अधिकार का उल्लंघन करने लगती हैं। इस बार हम सब एक साथ हैं। यह जेऐंडके के लोगों और केंद्र सरकार के बीच लड़ाई है।" उनका कहना है, "समस्या तब पैदा होने लगती है जब पाकिस्तान ऐसे मुद्दों पर बोलने लगता है। इधर अतिवादी सोच वाले लोग हम पर पाकिस्तान की भाषा बोलने के आरोप लगाने लगते हैं।" इस बार सरकार ने सामूहिक आकांक्षा और इच्छा के अनुसार रुख बदला है।

अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी कानून की आलोचना करने वाले पहले नेता थे। उन्होंने सरकार से समीक्षा करने की मांग की। तीन अप्रैल को बुखारी ने कहा कि कानून में बदलाव होगा। उसी शाम सरकार ने नियम बदल दिए। वह कहते हैं कि जम्मू-कश्मीर का हर मुद्दा केंद्र से जुड़ा है। 15 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने बुखारी के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि क्षेत्र में आबादी का स्वरूप बदलने की सरकार की मंशा नहीं है। जेऐंडके की डोमिसाइल पॉलिसी दूसरे राज्यों से बेहतर होगी।

कश्मीर में यह संशोधन कोई खुशी नहीं ला सका, बल्कि इससे आशंकाएं और बढ़ गईं कि भाजपा घाटी में आबादी का स्वरूप बदलेगी। पिछले आठ महीनों में पहली बार अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आबादी का स्वरूप बदलने की प्रक्रिया अगस्त 2019 में शुरू हुई थी। अब इसे नियोजित तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। डोमिसाइल कानून इसी का हिस्सा है। कानून की खिलाफत करने वालों को गिरफ्तारी की कश्मीर के पुलिस प्रमुख की चेतावनी के बावजूद कश्मीरियों ने विरोध करना बंद नहीं किया। शिक्षाविद अतहर जिया ने लिखा, "नौकरशाहों और बड़े नेताओं के रूप में उपनिवेशवादी राक्षस स्वच्छंद हैं। पर्यवेक्षक कहते हैं कि डोमिसाइल कानून में बदलाव भी हजारों अप्रवासी कश्मीरी मुस्लिमों और 1947 से ही पाकिस्तान और अन्य देशों में निर्वासित हजारों लोगों का मताधिकार छीन सकता है। लोग इस कानून को इजरायल की तरह का "गेम प्लान" मान रहे हैं, जिसके तहत श्रीनगर और दूसरे जिलों में बस्तियां बन सकती हैं।

पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू कहते हैं कि इसका अहम पहलू यह है कि डोमिसाइल कानून की अधिसूचना जारी होने के दो दिन के भीतर ही संशोधन कर दिया गया। उन्होंने कहा, "संवैधानिक व्यवस्था की जगह अस्थायी और एकतरफा कानून लागू किया गया है। इसका दुष्परिणाम यह होगा कि इन पर अनौपचारिक रूप से सौदेबाजी भी हो सकती है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज इस कानून को लोगों को अधिकारविहीन और वंचित करने के प्रयासों के तौर पर देखते हैं। वह कहते हैं, "अनुच्छेद 370 और 35ए को समाप्त करने के बाद कश्मीर में अब कोई भ्रम नहीं है कि भाजपा की और केंद्र की असली मंशा क्या है। लेकिन जम्मू के लोगों के लिए यह बड़ा झटका है, जिन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी।" फिलहाल जम्मू के लोगों ने लड़ने का फैसला किया है। इससे पता चलेगा कि यह क्षेत्र भाजपा को कहां तक झुका पाता है।

वायरस के वक्त सदमा

महामारी हमारी जिंदगी में उथल-पुथल मचाने के साथ ऐसे जख्म दे रही है जिसे ठीक होने में वर्षों लगेंगे

शिव विश्वनाथन

सदमा वह घाव है जो देह से आत्मा में जख्म उतार देता है। उसके साथ कलंक और लांछन की छायाएं डोलती आती हैं। अमूमन वह ज्यादातर आपदाओं के पीछे-पीछे आता है और उसे बाद का असर समझा जाता है। कोरोना वायरस महामारी का सदमा भी ऐसा ही है।

आज भारत खुद को एक मध्यवर्गीय समाज के रूप में देखता है, इसलिए वह मध्यवर्गीय नजरिए से ही कदम बढ़ाता है। लॉकडाउन की पूरी अवधारणा एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की तरह अपनाई गई, जैसे जिंदगी को एक टाइमटेबल में ढालने की कोशिश हो। यह एक मानसिकता और जीवन-ढर्रा है। टाइमटेबल ठहर जाए तो मध्यवर्ग अपनी कैद में सिमट जाता है और उसके तय रोजनामचे थम जाते हैं। लॉकडाउन में उच्च मध्यवर्ग को बोरियत, तन्हाई, बेचैनी, खालीपन और हां, घर से काम का एहसास हुआ। फिर भी, मध्यवर्गीय मानसिकता हाशिए पर गुजर-बसर करने वालों, प्रवासी मजदूरों, बंजारों के प्रति पूरी तरह बेरुखी दिखाती रही, जिन्हें कोरोना वायरस के नतीजे से आया सदमा सबसे पहले लगा।

इस अनौपचारिक समाज का सदमा देशव्यापी लॉकडाउन के ऐलान के पल ही गहरा हो गया, जब मजदूरों को अपनी नागरिकता और वजूद बेगाना लगने लगा। प्रवासी मजदूरों ने पाया कि वे हाशिए पर बैठे संदिग्ध और बेकार हैं। इस बेगानेपन के झटके से वे भूख और अपमान सहने को अभिशप्त हो गए। उनके साथ जीवाणुओं के झुंड जैसा बर्ताव किया गया और सरहदों पर उन पर केमिकल का छिड़काव किया गया। अलबत्ता, जिंदगी के इस स्याह पक्ष से मध्यवर्गीय सैलानी भी मुकाबिल हुए, जब वे सरहद की ओर भागे तो वह बंद हो चुकी थी, सामने खड़ी पुलिस प्रवासी और अप्रवासी के फर्क से नावाकिफ थी। अचानक भारत का आम आदमी दुश्चिंता और अकेलेपन के खौफ में घिर गया, उसे लगा कि घर वापसी के कोई मायने नहीं हैं। प्रवासी किसी अजीबोगरीब जीव की तरह चौखटे पर घिरा था, जिसे अफसरशाही पहचानने से ही इनकार कर रही थी। अपना राशन कार्ड घर छोड़ आए बिहारी प्रवासी मजदूरों ने खुद को भूख से लाचार पाया। अफसोस! बड़े अफसाने में उनकी बेचैनी और डर का कहीं जिक्र तक नहीं है, इससे मानसिक संताप और बढ़ने लगा है। इस बेआबरू बर्ताव में उन्होंने यह भी पाया कि देश के अफसाने में उनकी कोई जगह नहीं। वे कोरोना कथा के ब्लैकहोल और ब्लैकबॉक्स थे। प्रवासियों को एहसास हुआ कि कुछ आपदाएं दूसरों से कुछ ज्यादा ही अलग हैं। मसलन, चक्रवात और बाढ़ की विभीषिकाओं में कमोवेश एक जैसी प्रतिक्रिया और अफसाने उभर कर आते हैं लेकिन कोरोना वायरस में जिंदगी को राहत पहुंचाने वाले मिथक बेहद थोड़े हैं।

पीटीआइ

घर वापसी: काम-धंधे बंद होने पर गांव लौटने को मजबूर श्रमिक

देश के अफसाने में प्रवासी मजदूरों के दुख-दर्द और खौफ का कहीं जिक्र तक नहीं है, इससे मानसिक संताप और बढ़ जाता है

अमूमन जिंदगी और चहल-पहल से भरी-पूरी झुग्गी बस्तियां पूरी तरह वीरान हो गईं। लॉकडाउन शुरू हुआ तो छोटी-छोटी दुकानों, खोमचों और ढाबों पर पुलिस की दबिश पड़ी। रोजाना कमाने-खाने वालों के हाथ कोई रोजगार नहीं था। उन्हें बस रोज-ब-रोज नए नजारे खुलने का इंतजार था। बेरोजगारी, भूख और अनिश्चय ही अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का खौफ बन गया। चेन्नै की एक झुग्गी बस्ती में एक औरत ने मुझे बताया, "घरों में बर्तन-भाड़े के काम में लगी कुछेक औरतों का काम तो चालू है लेकिन हमारे मर्दों का क्या, जिनके पास इधर-उधर मंडराने और इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं है।" इंतजार वह सदमा है जिसे अमीर-उमरा समझ ही नहीं सकते। इंतजार आपकी पहचान, भरोसे को तोड़ देता है और काबिलियत पर सवाल खड़ा कर देता है। इंतजार चुपचाप खालीपन लाता है क्योंकि वह बेवजूद बनाता चलता है। झुग्गी बस्तियां इंतजार और अनिश्चय के सदमे में फंसी हैं, मगर मीडिया में उनकी जगह नामालूम-सी है। वह तो कॉरपोरेट अफसरान के घर से काम करने के जश्न में मस्त है।

जिसे आज नागरिक जीवन कहा जाता है, वह डरावने अनिश्चय के दुश्चक्र में फंस गया है। लॉकडाउन हाब्स नीति (16वीं सदी के ब्रिटिश दार्शनिक थॉमस हाब्स मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था के हिमायती थे, जिसमें हर कोई अपने वजूद के लिए दूसरे से लड़ता-भिड़ता है) जमीन पर उतार लाता है, कुछ निरंकुश सत्ता के दायरे खींचता है, जिनमें पुलिस और क्लर्क गश्त लगाते हैं। पुलिस तमाम चुनौतियों से ऐसे निपटती है, गोया सभी कानून-व्यवस्था की समस्याएं हों, जिसमें हर कोई सिद्धांतत: संदिग्ध होता है। वह बिना सोचे-समझे लाठी भांज देती है, उन पर भी,

त्रिभुवन तिवारी

सन्नाटा: दिल्ली के कनॉट प्लेस का नजारा

जो सरकारी जिम्मेदारियां निभाकर लौट रहे होते हैं। पुलिसवालों के इस डरावने अजनबीपन से बचा-खुचा मकान मालिकों ने मरीजों, डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए एक अस्पृश्यता का ताना-बाना बुनकर पूरा कर दिया है। मकान मालिकों को पूरा यकीन हो गया कि ये संक्रमण के वाहक हैं और उन्हें दूर रखना चाहिए। लिहाजा, डॉक्टरों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने अजीब विडंबना पैदा हो गई है। दुखद यह है कि शहर में ये त्रासदियां और निरंकुशता के तौर-तरीके सुर्खियों से गायब हैं।

सही कहें तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का जो सदमा सुर्खियों से गायब और अनकहा है, उसके झटके अब मध्यवर्ग को भी लगने लगे हैं। इसमें वक्त एक अहम किरदार है क्योंकि वक्त की पाबंदी का रोजनामचा या टाइमटेबल ही तो मध्यवर्ग को पहचान और स्थायित्व देता है।

एक गृहिणी का दर्द है कि लोगों के पास उसके डर को सुनने की फुर्सत ही नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें यह दुख साल रहा है कि कोई उनसे अनजाने में संक्रमण का शिकार न हो जाए। उन्होंने यह भी बताया कि उनका यह खौफ अफवाहों और सड़क से आ रही खबरों से कई गुना बढ़ गया है। एक तो यही कि एक शख्स को भीड़ सिर्फ इसलिए बुरी तरह धराशायी कर देती है क्योंकि वह लगातार खांस रहा था। सामान्य खांसी कभी रोजाना की आई-गई हुआ करती थी, लेकिन अब वह डरावनी और मनहूस बन गई है। गृहिणी ने यह भी बताया कि बुजुर्ग लोग बेहद घबराए-से हैं क्योंकि उन्हें चुन-चुनकर अलग किया जा रहा है। एक 70 साल के बुजुर्ग ने कहा, "मैं चट्टान की तरह मजबूत महसूस किया करता था लेकिन अब लोग मुझे संदेह की नजर से देखते हैं।" बदतर तो यह कि खासकर कमजोर याददाश्त के शिकार बुजुर्ग अब खुद को लुप्तप्राय जैसे पा रहे हैं। वे दूसरों की मौजूदगी में शर्मिंदा महसूस करने लगे हैं, गोया वक्त अब उनके साथ नहीं है।

हालांकि जिसमें सब शामिल हैं, वह हकीकत यह है कि कोरोना वायरस ने मौत, देश के शहरों में मौत के सिलसिले का एक वातावरण तैयार कर दिया है। किसी एक की मौत तो चलती है मगर मौत का सिलसिला एक अलग तरह का खौफ और लाचारी पैदा करता है। यह महामारी का ऐसा सबब है जिससे सामान्य जीवन थम गया है। रोज-ब-रोज मौत के सिलसिले को मौसम की खबरों जैसा बेरुखी से परोसा जा रहा है, अखबार उस दिन के आंकड़े चस्पा भर कर देते हैं। घातक शब्द नियतिवाद में एक जादुई अर्थ पा जाता है। लोग लाचार, असहाय-से महसूस करने लगे हैं कि वायरस एक-एक कर सभी को निगल जा सकता है। मौत का सिलसिला गहरा सदमा पैदा करता है और हमारे समाज में इसे समझने के अफसाने या मिथक मामूली ही हैं।

बेगानापन, हिंसा, वजूद न होना, बेरुखी का माहौल और अनिश्चितता ऐसे जख्म देती है, जो दिखता तो नहीं मगर निपट वास्तविक होता है, जिसकी टीस आदमी को कुछ कमतर आदमी जैसा महसूस कराती है। हमारे देश में मानसिक सदमे और संताप पर गंभीर रुख अख्तियार करने की व्यवस्था की दरकार है। हम सदमे को चिकित्सा शास्त्र और मनोविज्ञान के नजरिए से देखते हैं, जैसे वह हमारी जिंदगी में हिंसा का हिस्सा हो और उसके प्रति प्रोफेशनल रुख अपनाते हैं। सदमा अकेलेपन और तन्हाई से ज्यादा घातक है। उसके टीसते घाव को समाज के मरहम की दरकार है। सहानुभूति रखने वाले समाज और मेल-मुलाकात, बातचीत से ही उसका इलाज संभव है। हमारा समाज उनका दर्द सुनना फिर शुरू करे। त्रासदी यह है कि सदमा अभी भी वर्जित, छुपाने-दबाने जैसा माना जाता है। आशा यही है कि वायरस इन सारे अफसानों को बेपरदा कर देगा। लोकतंत्र में मजदूरों, गृहिणियों, मरीजों के दुख-दर्द पर मरहम रखने की दरकार है, जैसे वोटरों और उपभोक्ताओं को तवज्जो दी जाती है।

(लेखक प्रखर समाज-विज्ञानी, वैकल्पिक विचारों और परिकल्पना से संबंधित प्रतिष्ठित बौद्धिक समूह कंपोस्ट हीप (उर्वर टोली) के सदस्य हैं)

जान भी, जहान भी: लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की घोषणा करते प्रधानमंत्री

लॉकडाउन के सहारे लड़ाई जारी

केंद्र सरकार ने कुछ ढील के साथ लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया है, प्रधानमंत्री मोदी के सामने अर्थव्यवस्था को बचाना अब बड़ी चुनौती

प्रशांत श्रीवास्तव और कुमार भवेश चंद्र

कोरोना से लड़ाई अब लॉकडाउन-2 में पहुंच गई है। देशवासी अब 3 मई तक लॉकडाउन में ही रहेंगे। यानी लॉकडाउन 40 दिनों का हो गया है। स्थिति की गंभीरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल के बयान से साफ होती है, जिसमें उन्होंने 'जान भी और जहान भी' की बात की। प्रधानमंत्री का डर इन आंकड़ों से साफ हो जाता है कि भारत में महज 14 दिनों में कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या पांच गुनी होकर 11 हजार के पार कर गई है। एक अप्रैल को देश में 1998 लोग संक्रमित थे, जो 14 अप्रैल को 11,487 हो गए। एक मार्च को तो देश में महज तीन लोग कोरोना संक्रमित थे। इसमें भी चिंता की बात यह है कि 13 और 14 अप्रैल को ऐसा पहली बार हुआ जब एक दिन में एक हजार से ज्यादा मामले आए। संक्रमण के साथ मृत्यु दर भी बढ़ रही है। एक अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 11 गुना तक बढ़ी और अब तक 393 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण देश के 354 जिलों तक पहुंच गया है।

बढ़ते हुए आंकड़ों पर कोविड-19 के लिए बनी टॉस्कफोर्स के सदस्य और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली के डायरेक्टर डॉ. रणदीप गुलेरिया ने *आउटलुक* से कहा, "आंकड़े बढ़ने की प्रमुख वजह ज्यादा टेस्टिंग न होना है, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम स्टेज 3 में नहीं पहुंचे हैं। यानी कम्युनिटी संक्रमण का खतरा नहीं है। अच्छी बात है कि देश में हॉटस्पॉट की पहचान हो गई है। इन इलाकों को संक्रमण मुक्त कर चेन को तोड़ सकते हैं।" भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) से मिली जानकारी के अनुसार, 14 अप्रैल तक देश में 2,29,426 लोगों के टेस्ट किए गए। इसके अलावा अब एंटीबॉडी टेस्ट भी कराने की तैयारी है। इसके जरिए हर्ड इम्युनिटी का आकलन किया जा सकेगा। आइसीएमआर में सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन वायरोलॉजी के प्रमुख डॉ. टी.जैकब. जॉन का कहना है, "भारत का मौजूदा हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर इटली-अमेरिका जैसी स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल

एहतियातः संक्रमण है या नहीं, यह देखने के लिए मुंबई में लोगों की जांच करते स्वास्थ्यकर्मी

तैयार नहीं है। लॉकडाउन अवधि का इस्तेमाल स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार करने पर होना चाहिए। सरकार को प्राइवेट सेक्टर को साथ लाना चाहिए, जिससे निचले स्तर तक सेंट्रल कमांडिंग सिस्टम तैयार किया जा सके।"

अभी तक सरकार की तैयारी भी पर्याप्त नहीं नजर आती है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 11 अप्रैल तक देश में 586 अस्पतालों को कोविड-19 के मरीजों के लिए खास तौर से तैयार किया गया था। इनमें एक लाख आइसोलेशन बेड और 11,500 आइसीयू बेड हैं। हालांकि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के अनुसार, देश में कुल 7.10 लाख बेड हैं। अगर 40 दिन के लॉकडाउन के बाद स्थिति नहीं सुधरती है तो लचर स्वास्थ्य सुविधाएं गंभीर स्थिति खड़ी कर सकती हैं।

लॉकडाउन के 21 दिनों के पहले चरण में कुछ ऐसे भी अनुभव रहे जो उम्मीद जगाते हैं। मसलन, राजस्थान के भीलवाड़ा में जिस तरह से संक्रमण को रोका गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा और केरल के पत्थनमिट्टा मॉडल की भी चर्चा है। राज्य भी इन मॉडलों को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। गुलेरिया कहते हैं, "जहां भी संक्रमण को सफलतापूर्वक रोका गया, उसका अध्ययन करने की जरूरत है। दूसरे संक्रमित जगहों पर उन तरीकों को अपनाना चाहिए। इससे हम संक्रमण की चेन को तोड़ पाएंगे।"

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी मानना है कि एक समय दिल्ली का दिलशाद गार्डन हॉटस्पॉट बन गया था, लेकिन तुरंत एक्शन से आज वहां संक्रमण के मामले रुक गए हैं। इसके लिए पूरे इलाके को सील करके घर-घर जाकर लागों की टेस्टिंग की गई। जिनमें जरा भी लक्षण मिले, उन्हें क्वारंटाइन किया गया और आइसोलेशन में रखा गया। इसका फायदा यह हुआ कि संक्रमण की चेन टूट गई और स्थिति नियंत्रण में आ गई। जैन के अनुसार इसी तरह दिल्ली के दूसरे इलाकों में कदम उठाए जा रहे हैं जिसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही दूसरे क्षेत्रों में भी संक्रमण रुक जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में 14 अप्रैल तक चार राज्यों में संक्रमित लोगों की संख्या एक हजार से अधिक थी- महाराष्ट्र में 2,801, दिल्ली में 1,561, तमिलनाडु में 1,204 और राजस्थान में 1,046। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी संक्रमण तेजी से बढ़ा है। इन दोनों राज्यों में क्रमशः 741 और 695 मामले सामने आए हैं। करीब 21 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में भी नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ संक्रमण के बड़े क्षेत्र बन गए हैं। 14 अप्रैल तक राज्य में 660 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश के 75 जिलों में से 35 जिले कोरोना के संक्रमण से बचे हुए हैं। लेकिन लॉकडाउन के पहले चरण में जिस तरह से प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर की वजह

कोरोना विजेता

निष्ठा अग्रवाल

रायपुर, छत्तीसगढ़

मैं राज्य की पहली कोरोना मरीज हूं। 15 मार्च को मै लंदन से रायपुर पहुंची थी। एयरपोर्ट पर मेरी स्क्रीनिंग भी की गई थी। लेकिन मेरे अंदर कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे। फिर भी एहतियातन मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। बुजुर्ग दादा-दादी और माता-पिता को देखते हुए यह जरूरी था। मैं 17 मार्च को खुद ही टेस्ट कराने एम्स पहुंची, लेकिन लक्षण न होने की वजह से कोई टेस्ट करने को तैयार नहीं था। काफी कोशिश के बाद मेरा टेस्ट हुआ। दो दिन बाद रिपोर्ट पॉजिटिव निकली और मुझे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मुझे काफी तकलीफ दी।

सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की बाढ़ आ गई। हर जगह मुझे दोषी ठहराया जाने लगा। कहा जाने लगा कि मैंने कोरोना संक्रमण की बात छुपाई। यह बातें ऐसे समय में हो रही थीं, जब मैं खुद तकलीफ में थी और मौत से लड़ रही थी। मेरी गुजारिश है कि मरीजों के प्रति संवेदनशील बनें। न बन सकें, तो कम से कम उन्हें बदनाम न करें। संक्रमण होने पर घबराएं नहीं, डॉक्टर पर भरोसा करें। किसी भी हालत में इसे छिपाएं नहीं। सरकार, डॉक्टर, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज जब मैं ठीक हो गई हूं तो लोग विजेता जैसा मेरा स्वागत कर रहे हैं।

रवि भोई

मध्य प्रदेश में रक्षक हुए लापरवाह

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के 45 अधिकारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसकी बड़ी वजह आला अधिकारियों की लापरवाही है। कई अधिकारियों ने अपने संक्रमण की जानकारी छुपाई, साथ ही, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन किया।

स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की कमान संभाल रही पल्लवी जैन गोविल ने बताया कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन दावा किया कि उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं हैं। वह सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर बैठकें करती रहीं। उनके इस रवैए पर भोपाल के सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे कहते हैं, "पल्लवी जैन का बेटा अमेरिका से लौटा था, वह होम क्वारंटाइन था, लेकिन उसकी ट्रेवल हिस्ट्री प्रशासन को नहीं बताई गई। उनके बेटे की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई, लेकिन पल्लवी जैन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पल्लवी जैन के अलावा हेल्थ कॉर्पोरेशन के एमडी और आयुष्मान योजना के सीईओ जे. विजय कुमार की रिपोर्ट भी दो बार पॉजिटिव आई है। विजय कुमार ने भी अपनी कांटेक्ट लिस्ट सार्वजनिक नहीं की। राज्य में कोरोना को हराने के लिए दोनों आइएएस अधिकारियों के पास अहम जिम्मेदारी थी। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कोर ग्रुप में जे. विजयकुमार के अलावा 12 आइएएस अफसर भी शामिल हैं। अब सभी होम क्वारंटाइन हैं। अजय का कहना है जानकारी छुपाने और दूसरे लोगों की जान जोखिम में डालने के आरोप में दोनों अफसरों के खिलाफ एफआइआर दर्ज होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोनों अधिकारियों को विभाग से हटा दिया है। लेकिन इस लापरवाही की भरपाई आसान नहीं।

पल्लवी जैन गोविल
पूर्व प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग

रवि भोई

कोरोना विजेता

23 वर्षीय युवक
चंडीगढ़, पंजाब

मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूं। आत्म शक्ति और स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग की बदौलत मैं कोविड-19 को मात देने में कामयाब रहा। मैं 15 मार्च से 17 मार्च के बीच, विदेश से आए अपने एक मित्र के परिवार वालों के संपर्क में आया था। 19 मार्च की रात मुझे तेज बुखार आया। मैं अपने नजदीक के एक डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया। वहां से मुझे पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर परिवार में चिंता स्वाभाविक थी। मैं उन सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देता हूं, जिनकी बदौलत मैं स्वस्थ हुआ। नियमित रूप से मेरी दिन में दो बार जांच की जाती थी। देखने में आया कि कुछ लोग इस स्थिति में मानसिक संतुलन खोने लगते हैं। मेरे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं आई। मुझे भरोसा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 अप्रैल को मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया।

(पहचान जाहिर नहीं करना चाहते)

नीरज झा

सड़क पर उतरे: सूरत में घर जाने की मांग करते प्रवासी मजदूर

से राज्य सरकार के मंत्रियों पर संक्रमण का खतरा बढ़ा और नोएडा के डीएम का विवादों के साथ तबादला हुआ, वह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए लॉकडाउन-2 में नई चुनौती बन सकता है। इन सबके बीच केरल में बेहतर रणनीति का असर दिखा है। देश में सबसे पहले जिन राज्यों में मामले आए थे, उनमें केरल भी था, लेकिन डेढ़ महीने में इनकी संख्या 386 तक ही पहुंची है।

लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ केंद्र सरकार यह भी समझ चुकी है कि देश पूरी तरह से लॉकडाउन में रहा, तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बैठ जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 20 अप्रैल से कई स्तर पर छूट देने की कोशिश की गई है, ताकि जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया फिर से घूमने लगे। गृह मंत्रालय ने जो दिशानिर्देश जारी किए हैं, उसके मुताबिक खेती से जुड़ी गतिविधियों, किराना, राशन की दुकानें, फल-सब्जी, डेयरी, पोल्ट्री, मीट, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, बढ़ई आदि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़े व्यवसाय को शुरू किया जा सकेगा। ई-कॉमर्स कंपनियों, कूरियर सर्विसेज, आइटी कंपनियों और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी शर्तों के साथ काम शुरू करने की अनुमति दी गई है। निर्यात करने वाली इकाइयां भी काम शुरू कर सकेंगी। सरकार के इस फैसले से साफ है कि वह लॉकडाउन को लंबा नहीं खींचना चाहती है। हालांकि, उसकी पहली प्राथमिकता कोरोना के संक्रमण को रोकने की है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि अगर हॉटस्पॉट के मामले बढ़े तो यह ढील वापस ली जा सकती है।

कोविड-19 की चपेट में अब लगभग पूरी दुनिया है। पूरे विश्व में 14 अप्रैल तक 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे और एक लाख 30 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी थी। अमेरिका इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां अब तक छह लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 30 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, 15 मार्च तक दुनिया में सिर्फ 1.5 लाख मामले थे।

कोरोना विजेता

फतेह सिंह
नवांशहर, पंजाब

अपने दो दोस्तों के साथ सात मार्च को मेरे पिता रागी बाबा बलदेव सिंह जर्मनी से इटली होते हुए अपने गांव पठलावा पहुंचे थे। घर लौटने पर तेज-बुखार था 12 मार्च को उन्हें जालंधर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन वहां हालत में सुधार नहीं हुआ और 18 मार्च को 72 साल की उम्र में वह हमें छोड़कर चले गए। इस बीच पीजीआइ चंडीगढ़ की रिपोर्ट में मौत का असल कारण कोरोना संक्रमण पाया गया। पिता जी इस बीच जिन लोगों से मिले थे, उनमें से 27 लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। जिसमें मैं, मेरी मां, मेरे भाई, बहन, रिश्तेदार और दोस्त शामिल थे। गांव के सरपंच भी इसकी चपेट

में आ गए। पिता के अंतिम संस्कार के समय परिवार के छह सदस्य नवांशहर के सिविल अस्पताल में भर्ती थे। संस्कार भी सफाई कर्मियों ने ही किया। दो साल का मेरा भतीजा भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। 2 अप्रैल को अस्पताल में मना भतीजे का जन्मदिन मेरे लिए मुबारक दिन था, क्योंकि उसी दिन मेरी पहली रिपोर्ट निगेटिव आई और 5 अप्रैल को आई दूसरी रिपोर्ट भी निगेटिव निकली। मुझे भतीजे और मेरे दो भाइयों हरिंदर और सुखविंदर को अस्पताल से छुट्टी मिलने की बहुत खुशी है। अब मैं अस्पताल से छुट्टी मिलते ही सबसे पहले पिता जी के अस्थि विसर्जन के लिए कीरतपुर साहिब जाऊंगा।

हरीश मानव

नीतीश की कोरोना परीक्षा

पटना से गिरिधर झा

विधानसभा चुनाव के मात्र कुछ महीने पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक अप्रत्याशित समस्या से जूझना पड़ रहा है। कोरोनावायरस जैसी वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थिति से लड़ना एक पिछड़े राज्य के मुखिया के लिए कांटों भरा हो सकता है। विगत पंद्रह वर्षों में नीतीश मुख्यत: बिहार के चतुर्मुखी विकास के मुद्दे पर ही चुनाव जीतते आए हैं और इस बार भी उनके गठबंधन का मुद्दा कुछ अलग न होगा, लेकिन क्या चुनावी समर में कोरोना संकट के दौरान उनकी सरकार द्वारा किए गए राहत कार्य की तुलना में पूर्व में उनके द्वारा किए गए विकासोन्मुखी कार्य गौण हो जाएंगे?

नीतीश कुमार शुरू से इस बात से अवगत थे कि कोरोना संक्रमण के फैलने का सबसे अधिक प्रभाव प्रदेश में और प्रदेश से बाहर रह रहे गरीब लोगों, विशेषकर प्रवासी बिहारी मजदूरों की जिंदगियों पर पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने उनकी मदद के लिए सरकार द्वारा तत्काल 100 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की घोषणा की। उन्होंने भारत सरकार को ट्रेनों और वायुयानों के परिचालन बंद करने की भी सलाह दी, ताकि प्रवासी लोगों के आवागमन से संक्रमण के फैलने का खतरा कम किया जा सके लेकिन इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचने के पूर्व ही मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में रह रहे बिहारी मजदूर ट्रेनों से अपने गांव लौटने लगे।

नीतीश आने वाले खतरे को भांप चुके थे। लॉकडाउन शुरू होने के पहले दो दिनों में ही हजारों बिहारी मजदूर पटना वापस लौट आए थे लेकिन तब तक उनकी जांच के लिए दानापुर स्टेशन पर मेडिकल कैंप लग चुके थे। इसी बीच दिल्ली और अन्य बड़े शहरों से ऐसी खबरें भी आने लगीं कि हजारों की संख्या में वहां रहने वाले बिहारी और अन्य मजदूर लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार होने के कारण अपने-अपने गृह राज्यों के लिए पैदल ही परिवार सहित कूच कर गए हैं। यह नीतीश सरकार के लिए खतरे की घंटी थी। परिस्थिति का आकलन करते हुए नीतीश ने विभिन्न राज्यों की सीमाओं को बंद करने की अपील की लेकिन तब तक बाहर रहने वालों की बड़ी तादाद बिहार पहुंचने लगी। ऐसा लगने लगा कि राज्य भर में कोरोना संक्रमण का विस्फोट अब होने ही वाला है। उन्हें राज्य में न सिर्फ कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकना था बल्कि बिहार के उन लाखों दिहाड़ी मजदूरों के भरण-पोषण का ख्याल भी रखना था। उन्होंने उनकी तत्काल राहत के लिए कई घोषणाएं कीं। सरकार ने सभी राशन कार्डधारियों को एक महीने की मुफ्त राशन देने और उनके बैंक खातों में एक हजार रुपये हस्तांतरित करने की घोषणा की। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पेंशनधारियों के खाते में तीन महीने के अग्रिम पेंशन डालने तथा सभी चिकित्सकों और

अन्य स्वास्थ्यकर्मियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन देने की भी पहल की। नीतीश ने वैसे मजदूरों के लिए जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे प्रति व्यक्ति एक हजार रुपये उनके बैंक खाते में स्थानांतरित करने का निर्णय किया। इसमें दो मत नहीं है कि ऐसे प्रवासी बिहारियों की वापसी से राज्य में संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया है।

मार्च महीने में मुंगेर के एक युवक की दुबई से लौटने के बाद कोरोनावायरस संक्रमण से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ गया था। 13 अप्रैल तक राज्य भर में कोरोना मरीजों की संख्या मात्र 64 थी जिसमें सिर्फ एक ही मृत्यु हुई है। उनमें से 22 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। राहत की बात है कि अब तक किसी संक्रमित व्यक्ति को आइसीयू की जरूरत नहीं पड़ी है। जानकारों का मानना है कि राज्य में कोरोना मरीजों के कम होने का मूल कारण अपेक्षाकृत स्तर पर जांच होने का अभाव है। लगभग 11 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में फिलहाल सिर्फ चार स्थानों पर जांच की सुविधा है।

इटली-अमेरिका जैसी स्थिति हुई तो हम तैयार नहीं

भारत में कोविड-19 से 339 लोगों (14अप्रैल तक) की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस बात का खतरा है कि कहीं हमारी इटली-अमेरिका जैसी स्थिति न हो जाए। मौजूदा तैयारियां किस स्तर पर हैं, संक्रमण की क्या स्थिति है, इस पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक **डॉ. रणदीप गुलेरिया** *से आउटलुक के* **नीरज झा** *ने बातचीत की है। प्रमुख अंश:*

लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, यह कितनी चिंता की बात है?

टेस्ट की संख्या में इजाफा हुआ है, कई हॉटस्पॉट इलाकों की पहचान करके वहां बड़े पैमाने पर टेस्ट किए जा रहे हैं। इस वजह से संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा दिख रहा है। अभी पूरे देश में वायरस का संक्रमण नहीं फैला है। जहां भी मामले आ रहे हैं, उन इलाकों को सील करके तुरंत टेस्ट, होम क्वारंटाइन और आइसोलेट करने की क्षमता बढ़ाकर वायरस को फैलने से रोका जा रहा है।

नेशनल टास्क फोर्स की तरफ से सरकार को क्या सुझाव दिए गए हैं? क्या लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है?

कोविड-19 को रोकने में अस्पताल से ज्यादा सामुदायिक भागीदारी की अहम भूमिका है। इसलिए लोगों को लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। यह वायरस एक से दूसरे में फैलता है। इसलिए हमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन की चेन तोड़ना होगा, ताकि हम इस जंग को जीत सकें। लगातार टॉस्क फोर्स की तरफ से सरकार को सुझाव दिए जा रहे हैं। सरकार उन सुझावों पर अमल भी कर रही है।

क्या आपको ऐसा लगता है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत हो चुकी है?

देखिए मेरा मानना है, देश में जो हॉटस्पॉट इलाके हैं, अगर वहां क्लोज मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, होम क्वारंटाइन की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं की जाती है तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की शुरुआत हो सकती है। देश के बड़े हिस्से में अभी उतने मामले नहीं पाए गए हैं। इसलिए, हमें हॉटस्पॉट वाले इलाके में फैले वायरस को सख्ती से रोकने की जरूरत है। अगर वायरस दूसरे इलाकों में फैलता है तो फिर हमारे लिए उसके प्रसार को रोकना मुश्किल हो जाएगा। जो बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी।

क्या हम स्टेज-3 में पहुंच चुके हैं?

अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। हम ग्रे जोन में हैं। इसलिए हर नागरिक लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और होम क्वारंटाइन का ईमानदारी से पालन करता है तब हम इस चेन को तोड़ पाएंगे। इसमें कहीं से भी कोताही होती है तो फिर हम स्टेज-3 और कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में पहुंच जाएंगे।

सोरोलॉजिकल टेस्ट को लेकर हमारी क्या स्थिति है?

एंटीबॉडी किट, टेस्ट का दूसरा माध्यम है। उससे यह पता चलता है कि वायरस कितना फैला है। इस किट को खास तौर से चीन, जापान और कोरिया की कुछ कंपनियां ही बना रही हैं। हर देश इस प्रयास में है कि सबसे ज्यादा किट उसे मिले। इसको लेकर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) और केंद्र सरकार दोनों प्रमुखता से काम कर रही हैं। हमारे पास कुछ किट आज की तारीख में आ चुके हैं, पर यह अभी एक चुनौती है।

पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट (पीपीई) की भी किल्लत है, कई जगहों पर डॉक्टरों ने इस्तीफे भी दिए हैं?

इलाज के दौरान जितनी भी चीजें होनी चाहिए, वो सारी पीपीई के तहत आती हैं। कोविड-19 के इलाज में जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन्हें पीपीई की आवश्यकता है और यह अनिवार्य है। जो डॉक्टर किसी और इलाज में भी पीपीई की मांग करते हैं, वह उपयुक्त नहीं है। डिमांड न होने की वजह से पहले पीपीई विदेशों से मंगाए जाते थे। लेकिन अब देश में भी निजी और सरकारी कंपनियां बना रही हैं। हमारे पास अब पीपीई की कोई कमी नहीं है। हमलोगों ने रिसर्च कर ऐसी प्रणाली तैयार की है जिससे पीपीई का दोबारा इस्तेमाल हो सके।

क्या कोविड-19 के उपचार के लिए हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन उपयुक्त है?

अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं। इस पर स्टडी सीमित दायरे में चीन और फ्रांस में हुई है। अभी और शोध की जरूरत है। हमें यह समझना होगा कि अभी कोई भी पूर्ण इलाज इस वायरस को लेकर विकसित नहीं हुआ है। इस दवा से थोड़ी राहत मिली है जिसके बाद माना गया कि इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन, डॉक्टरों की सलाह से ही लेना चाहिए।

क्या हम अमेरिका और इटली जैसे देशों की स्थिति में पहुंच गए हैं?

नहीं, इटली, स्पेन और अमेरिका जैसी स्थिति हमारे यहां नहीं है। मैं समझता हूं कि मामले तो बढ़ेंगे, लेकिन जो बढ़ने की रफ्तार है, उसे रोके रखना है। जितने मामले आते हैं, उन्हें हम उपयुक्त इलाज दे पाते हैं तब कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोरोना के मामले बिलकुल शून्य हो जाएं। अगर इटली और अमेरिका जैसे देशों की तरह मामलों में एकाएक इजाफा होता है, तब हमारा स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर इसे नहीं संभाल पाएगा।

क्या भीलवाड़ा मॉडल को देश के सभी हॉटस्पॉट इलाकों पर लागू किया जाना चाहिए?

बिलकुल, भीलवाड़ा मॉडल काफी उपयुक्त है। जिस तरह से वहां बिना देरी किए फौरन लॉकडाउन किए जाने के बाद बड़े पैमाने पर टेस्ट किए गए, उससे मामला पूरी तरह से नियंत्रण में आ गया है। मेरा मानना है कि इस मॉडल को अच्छे से समझ कर लागू किया जाए।

“केंद्र से मिली मदद नाकाफी”

पंजाब के मुख्यमंत्री **कैप्टन अमरिंदर सिंह** *का कहना है कि राज्य में हालात दूसरे प्रदेशों से बेहतर हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के लिए राज्य में मेडिकल उपकरणों की भी कमी नहीं है। हालांकि केंद्र से मिली मदद को वे नाकाफी मानते हैं।* आउटलुक *के* **हरीश मानव** *से बातचीत में उन्होंने महामारी से निपटने की सरकार की तैयारियों के बारे में भी बताया। बातचीत के प्रमुख अंश:*

पंजाब में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे आप कैसे निपट रहे हैं?

बाकी राज्यों की तुलना में पंजाब के हालात बेहतर हैं। इस समय राज्य के 22 जिलों में से 17 प्रभावित हैं। 15 जिलों में तीन से अधिक संक्रमित हैं। हमारी तैयारी दो स्तर पर है– पहला, स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर और दूसरा, महामारी से बचाव। बचाव के लिहाज से देखें, तो केरल के बाद पंजाब दूसरा राज्य है जिसने पूरी तरह से कर्फ्यू लगाया है। स्वास्थ्य सेवाएं देखें, तो हम प्रतिदिन 800 से अधिक टेस्ट कर रहे हैं। दो प्राइवेट लैब को भी अनुमित दी गई है। हमने केंद्र से लुधियाना के दो सरकारी अस्पतालों को भी सूची में शामिल करने की अनुमति मांगी है। रैपिड टेस्टिंग किट्स मिलने पर बड़े पैमाने पर टेस्ट कर सकेंगे।

पहले कहा गया कि 95,000 एनआरआइ जनवरी के बाद पंजाब में आए, पर बाद में संख्या 55,000 बताई गई। वास्तविक स्थिति क्या है?

दो तरह की संख्या हैं। 95,000 एनआरआइ सीधे पंजाब के मोहाली, अमृतसर एयरपोर्ट और वाघा तथा करतारपुर लैंड पोर्ट के रास्ते लॉकडाउन की घोषणा से पहले आए। उन्हें घरों में क्वारंटाइन किया गया। इनमें से पांच कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिन्हें अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। ज्यादातर लोग क्वारंटाइन अवधि भी पूरी कर चुके हैं। दूसरे 55,000 वे एनआरआइ हैं जो दिल्ली के रास्ते पहुंचे। उन सबके टेस्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर किए गए। उनकी तलाश भी हमने पूरी कर ली है। संभव है कि कुछ लोग अपनी विदेश यात्रा का ब्योरा छुपा रहे हैं। उनसे निवेदन है कि वे स्वेच्छा से जानकारी दें, अन्यथा उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे।

पहले नवांशहर कोरोना पॉजिटिव मामलों का हब था, अब मोहाली पहले स्थान पर है।

नवांशहर अब भी हॉटस्पॉट है। वहां संक्रमण के ज्यादातर मामले एक दूसरे से जुड़े थे। वहां आठ मरीज ठीक हो चुके हैं। किसी इलाके में पॉजिटिव मामलों की संख्या तेजी से इसलिए भी बढ़ती है कि वहां टेस्ट ज्यादा हुए। मोहाली में यही हुआ।

खबरें हैं कि बहुत से अस्पतालों में मास्क और पीपीई किट की किल्लत है। सच क्या है?

मेडिकल उपकरणों की कोई कमी नहीं है। हमने जरूरी उपकरण खरीदने के ऑर्डर दे रखे हैं। कोरोना मरीजों के लिए हमारे पास 5,000 बेड हैं। 52 सरकारी और 195 प्राइवेट आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में 76 और प्राइवेट में 358 वेंटिलेटर हैं। सरकार ने और 93 वेंटिलेटर खरीदने के ऑर्डर दिए हैं। 66,490 एन-95 मास्क उपलब्ध हैं और 27 लाख के आर्डर दिए गए हैं। 16,000 पीपीई किट हैं और दो लाख के ऑर्डर दिए गए हैं।

हॉटस्पॉट से कैसे निपट रहे हैं?

हॉटस्पॉट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहां आवाजाही पर काफी सख्ती है। हमने जांच की क्षमता 10 गुना तक बढ़ा दी है। 10 लाख रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर आइसीएमआर को दिया है। खुले बाजार से भी 10,000 किट खरीद रहे हैं। घरों में जाकर सैंपल लेने के लिए नवांशहर, होशियारपुर और मोहाली में मोबाइल वैन चलाई गई हैं।

केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही सहायता से संतुष्ट हैं?

केंद्र से हमें अभी तक जो मिला है, वह पर्याप्त नहीं है। जीएसटी का बकाया जारी करने के अलावा हमने विशेष पैकेज मांगा है। आपदा राहत कोष से हमें केंद्र से सिर्फ 225 करोड़ रुपये मिले हैं। मनरेगा खाते में कुल 928 करोड़ की ग्रांट मिली है। इतनी रकम से हम कैसे विपदा से निपट सकते हैं? हमें चिकित्सा उपकरण खरीदने और लाखों लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए काफी धन की जरूरत है। कर्मचारियों का वेतन और अन्य रूटीन खर्चों के अलावा गेहूं की खरीद के लिए भी धन चाहिए।

गेहूं की बंपर फसल की संभावना है। कटाई और मंडियों में काम करने के लिए इस बार प्रवासी श्रमिक नहीं हैं। कैसे करेंगे प्रबंध?

श्रमिकों की किल्लत नहीं है। लॉकडाउन के बावजूद हमने करीब 7.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को रोका है। उनके वेतन, रहने और खाने का ध्यान रखा जा रहा है। मनरेगा श्रमिकों को भी लगाया जाएगा। किसानों और श्रमिकों को विशेष कर्फ्यू पास जारी किए गए हैं। करीब 4,000 अस्थायी कच्ची मंडियां खेतों के निकट स्थापित की गई हैं। 15 जून तक 30 सदस्यों का कंट्रोल रूम पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगा।

इस बार कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की कटाई पर जोर रहेगा। इससे पशु चारे का संकट पैदा होने के आसार हैं।

कंबाइन हार्वेस्टर से चारे के नुकसान की धारणा गलत है। पीएयू द्वारा विकसित स्ट्रा-रीपर की मदद से 90 फीसदी तुड़ी प्राप्त की जा सकती है।

लॉकडाउन के बाद के हालात से निपटने के लिए क्या कोई टॉस्कफोर्स बनाने की तैयारी है?

हम टॉस्कफोर्स बना रहे हैं, जो 10 दिन में रिपोर्ट देगी। इसमें उद्योग, व्यापार, कृषि, स्वास्थ्य और सिविल सोसायटी से जुड़े 15 विशेषज्ञ सदस्य होंगे। कोरोना का कहर खत्म होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन करेंगे।

लॉकडाउन नहीं होता तो एक लाख लोग होते संक्रमित

देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर है। करीब 1.5 करोड़ आबादी पर गहरा संकट है। वह संक्रमण के खतरे के साथ आर्थिक गतिविधियां ठप होने से भी परेशान है। ऐसे में दिल्ली सरकार कोविड-19 से लड़ने के लिए कितनी तैयार है, इस पर स्वास्थ्य मंत्री **सत्येंद्र जैन** *ने* **प्रशांत श्रीवास्तव** *से बातचीत की। पेश हैं प्रमुख अंश:*

महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। यह कितनी बड़ी चुनौती है?

यह बहुत बड़ा संकट है, आज तक ऐसे संकट का सामना किसी ने नहीं किया है। जहां तक दिल्ली में ज्यादा मामले की बात है, दिल्ली की स्थिति को समझना होगा। यहां पर देश-विदेश से लोग आते हैं। प्रवासी लोग भी काफी रहते हैं। ऐसे में स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अभी तक नियंत्रण में है। हमने 2,400 (12 अप्रैल तक) से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है।

दिल्ली में तेजी से हॉटस्पॉट बढ़ रहे हैं, क्या स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है?

अभी (12 अप्रैल) तक 43 हॉटस्पॉट की पहचान हुई है। हमने 20 से शुरुआत की थी। क्राइटेरिया सख्त करने की वजह से हॉटस्पॉट की संख्या बढ़ी है। पहले हम एक क्षेत्र में छह संक्रमित पाए जाने पर, उसे हॉटस्पॉट घोषित करते थे, अब इसे घटाकर तीन कर दिया गया है। संभव है, आने वाले दिनों में हॉटस्पॉट और बढ़ें। फिलहाल मकसद संक्रमण रोकना है।

दिल्ली सरकार ने फिलहाल कितने संक्रमित लोगों के इलाज के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है?

दिल्ली इस समय तक 30 हजार तक संक्रमित लोगों के लिए तैयार हो चुकी है। इसके लिए हमने अस्पतालों और दूसरी व्यवस्थाओं के जरिए तैयारी कर ली है। साथ ही लगातार हम अपनी क्षमता बढ़ाते जा रहे हैं।

पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (पीपीई) की काफी किल्लत है, क्या दिल्ली के पास पर्याप्त उपलब्धता है?

हमने केंद्र सरकार से दो लाख पीपीई की मांग की थी, लेकिन 13 अप्रैल तक 12 हजार ही मिल पाई है। सरकार ने 37 हजार देने की बात कही थी, उम्मीद है कि जल्द ही ये हमें मिल जाएंगी। हम दूसरे संसाधनों के जरिए पीपीई की उपलब्धता बढ़ा रहे हैं।

दिलशाद गार्डन को लेकर दावा है कि अब वहां संक्रमण नहीं है, क्या दूसरे जगहों पर स्थिति सुधरी है?

वहां पिछले 14 दिनों में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया है। हमने वहां पर एक-एक घर में लोगों की जांच की, लोगों को क्वारंटाइन किया। इसकी वजह से संक्रमण की चेन को रोक पाएं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वहां संक्रमण रुक गया है। जहां तक दूसरे हॉटस्पॉट की बात है तो कई जगहों पर स्थिति सुधरी है, लेकिन हमें कम से कम दो हफ्ते इंतजार करना होगा। उसके बाद ही संक्रमण पर कुछ कह पाने की स्थिति में होंगे।

दिल्ली में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में संक्रमण बढ़ा है, क्या कम्युनिटी संक्रमण की स्थिति है?

अभी तक कम्युनिटी संक्रमण की स्थिति नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी क्षेत्र से एक दो मामले नहीं आते। एक ही क्षेत्र से 100-200 मामले सामने आते। हमने टेस्टिंग भी बढ़ा दी है। ऐसे में, कम्युनिटी संक्रमण के निष्कर्ष तक पहुंचने की जरूरत नहीं है।

लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है, दूसरे विकल्प भी तलाशने चाहिए?

कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के लिए अभी लॉकडाउन ही सबसे बेहतर विकल्प है। जैसा कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट है, उसके आधार पर दिल्ली में लॉकडाउन नहीं होता, तो एक लाख लोग संक्रमित होते। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो इस स्थिति में कौन सी अर्थव्यवस्था चला पाते। इससे बेहतर है पहले लोगों की जान बचाई जाए।

पीपीई, मास्क और दवा पर्याप्त

छत्तीसगढ़ में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है और 18 पॉजिटिव में से 10 मरीज ठीक होकर घर चले गए हैं। अब तक किसी को वेंटिलेटर में रखने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक होने वालों में उम्रदराज और युवा दोनों मरीज हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का कहना है कि यहां संक्रमित लोग इलाज के लिए समय पर आए, इस कारण वे स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, लेकिन यह नहीं मानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में इसका फैलाव नहीं होगा। यहां विदेश से आए लोगों के अलावा जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, उनका भी टेस्ट पॉजिटिव निकला। कोरोना से जंग के लिए छत्तीसगढ़ कितना तैयार है और अब तक उठाए कदम समेत कई मुद्दों पर आउटलुक के विशेष संवाददाता **रवि भोई** *ने* **सिंहदेव** *से बातचीत की। प्रमुख अंश:*

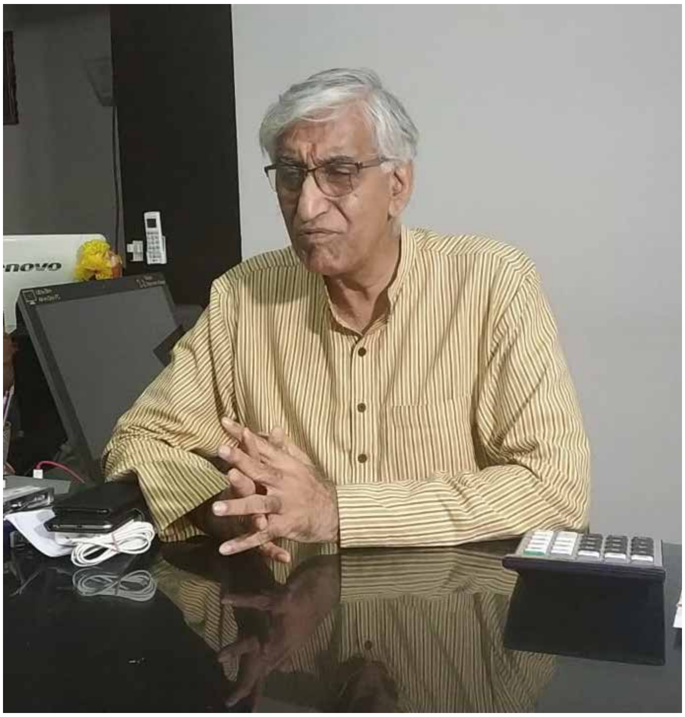

संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

यहां पर केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक 27 जनवरी से तैयारी शुरू हो गई थी। विदेशों से आने वालों को क्वारंटाइन करने के स्थान चयन से लेकर बेड की व्यवस्था, कलेक्टरों की अध्यक्षता में रैपिड एक्शन टीम का गठन तक कर लिया गया था। 28 जनवरी से एयरपोर्ट पर विदेशों से आने वालों की स्क्रीनिंग और बुखार मापना शुरू किया गया, लेकिन बुखार मापने के अलावा उन्हें क्वारंटाइन किया जाता तो स्प्रेड का खतरा कम होता। पहले तो केवल चीन से आने वालों का ही बुखार जांचने के निर्देश थे, बाद में दूसरे देशों से आने वालों का भी मापा गया। एक मार्च के बाद 2,300 से अधिक लोग विदेश से आए।

छत्तीसगढ़ में कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन का आधार क्या है?

10 अप्रैल तक राज्य में 85,485 लोग होम क्वारंटाइन में थे। इनमें बाहर से आए लोग भी हैं जो संक्रमित हो सकते हैं। प्रशासन इन पर नजर रखे हुए है। 87 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए। इनमें 1,530 लोगों को रखने की व्यवस्था है, लेकिन अभी 177 लोग हैं।

कितने लोगों का सैंपल लिया गया है। क्या जांच की गति धीमी है। इसके क्या कारण हैं?

10 अप्रैल तक 3,159 लोगों का सैंपल लिया गया, जिसमें से 3,053 की रिपोर्ट आई, जिसमें 18 पॉजिटिव मिले। 18 में से 10 स्वस्थ होकर घर चले गए। आठ की स्थिति स्थिर है। 88 सैंपल की रिपोर्ट बाकी है। छत्तीसगढ़ में एम्स रायपुर और मेडिकल कालेज जगदलपुर में जांच की सुविधा है। जो रोजाना 400-500 लोगों की जांच कर पा रहे हैं। केंद्र ने ही टेस्टिंग सेंटर तय किए हैं। अगले हफ्ते तक 75 हजार किट मिलने की उम्मीद है। इससे जांच तेज होगी।

क्या आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी काफी अच्छी है?

मरीज प्रारंभिक चरण में ही आ रहे हैं। कोई गंभीर मरीज नहीं आया है। कोरोना की कोई दवा नहीं है, ऐसे में कह सकते हैं कि मरीज खुद ही ठीक हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में जिस तरह मरीज ठीक हो रहे थे, उससे कहा जा रहा था कि राज्य जल्द कोरोना मुक्त होगा, लेकिन तबलीगी जमात वालों के संक्रमित मिलने से स्थिति बदल गई, क्या सरकार को इसका एहसास था?

तबलीगी जमात वाले अलग-अलग राज्यों में गए। खुद संक्रमित हुए और दूसरों को भी संक्रमित किया। ये कैरियर के रूप में सामने आए।

क्या आप मानते हैं कि यह कम्युनिटी स्प्रेड है?

कम्युनिटी स्प्रेड पूरी दुनिया में है। छत्तीसगढ़ के 10 फीसदी लोग भी कम्युनिटी स्प्रेड में आते हैं तो बड़ी आबादी प्रभावित होगी। लॉकडाउन से इसे ही रोकने की कोशिश है। लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर और सतर्क रहकर बचना होगा।

छत्तीसगढ़ भविष्य में कोरोना से जंग के लिए कितना तैयार है और कैसी व्यवस्था है?

संक्रमण एक दायरे में आया तो सरकार निपटने के लिए तैयार है। एम्स, रायपुर मेडिकल कालेज के अलावा चार अन्य मेडिकल कालेजों और जिला अस्पतालों में व्यवस्था की जाएगी। अभी 4,200 बैड का इंतजाम है। जरूरत पड़ी तो निजी अस्पतालों में भी व्यवस्था होगी। कुछ अस्पताल के संचालकों ने स्वयं प्रस्ताव दिया है। सरकार के पास प्लान बी और सी है।

छत्तीसगढ़ में पीपीई, मास्क और दवाई की क्या स्थिति है?

अभी के लिए पर्याप्त है। टेस्ट बढ़ेंगे और अचानक मरीज बढ़ गए तो और ज्यादा आवश्यकता होगी। इसकी मांग की गई है।

कोरोना से लड़ाई में केंद्र सरकार का कैसे सहयोग मिल रहा है और क्या अपेक्षा रखते हैं?

केंद्र से अभी 29 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। टेस्टिंग किट और दूसरे सामान भी भेजे जा रहे हैं। एम्स से जांच और इलाज में मदद मिल रही है। केंद्र के दिशा-निर्देश पर ही काम कर रहे हैं।

अभी कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में एम्स में ही कोरोना के इलाज की सुविधा है?

ऐसा नहीं है। यह केंद्रीकृत व्यवस्था बनाई गई है। एम्स में 500 मरीजों के इलाज की सुविधा है। छत्तीसगढ़ में अभी एम्स में दस से ज्यादा मरीज नहीं आ रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था करके रखी गई है। जल्दी ही वैकल्पिक व्यवस्था का आकलन होगा।

लॉकडाउन के बाद का क्या प्लान है?

खेती के काम जारी रहेंगे। पंचायतों और रोजगार गारंटी और स्वरोजगार को प्रमोट किया जा सकता है। फैक्ट्री में ही कामगारों को रखकर उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

कोरोना के असली योद्धा लाचार

महामारी के दौर में देश के हर आदमी को भोजन जिन करोड़ों किसानों की बदौलत संभव हो रहा है, उनकी सुध लेने में सरकारी पहल बेहद नाकाफी

हरवीर सिंह

खड़े खेत का दर्दः अपनी फसल देखता किसान

त्रिभुवन तिवारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने के लिए 14 अप्रैल को जब देश को संबोधित किया, तो उन्होंने आश्वस्त किया, "किसी को भी भोजन की किल्लत नहीं होगी। 21 दिन के लॉकडाउन में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी।" असल में उनके इस भरोसे के पीछे देश में खाद्य पदार्थों की बेहतर पैदावार और केंद्रीय पूल में 550 लाख टन का खाद्यान्न भंडार है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी बड़ी महामारी के दौरान कोई भी भूखा नहीं रहा है। व्यवस्थागत कमियों को छोड़ दें तो यह बड़े सुकून की बात है। लेकिन यह उन करीब 14 करोड़ किसान परिवारों के चलते संभव हो पाया, जो इस महामारी से दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। खुद के जीवन को बचाने की लड़ाई और खेतों में खड़ी अपनी

पीटीआइ

बर्बादी: आगरा में किसानों को दूध के खरीदार नहीं मिले तो रास्ते पर ही उड़ेल दिया

फसल को बचाकर बाजार तक पहुंचाने की लड़ाई। और जब पूरे देश में आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, तब भी खेती-किसानी का काम जोरों पर है। फसल की बुवाई और उसकी कटाई का एक समय होता है जिसे टाला नहीं जा सकता है और इसे किसान से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। खेती की इन गतिविधियों के चलते करोड़ों मजदूरों के घरों में चूल्हा जलने की व्यवस्था हो रही है। लेकिन संकट में देश के हित में काम कर रहे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान के बावजूद अभी तक सरकार ने कोई बड़ी वित्तीय मदद नहीं की है। इसके साथ ही कोरोना से लड़ाई लड़ रहे डाक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, सफाईकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और दूसरी आवश्यक सेवाएं दे रहे लोगों के लिए कई बार हमारे हाथ तालियां बजाने के लिए उठे, हौसला अफजाई में दीये और कैंडल जलाए गए। इस संकट में देश को खाद्य सुरक्षा का भरोसा कायम रखने वाले किसान के लिए किसी ने न थाली बजाई है और न ही दीये जलाये हैं। 14 अप्रैल के प्रधानमंत्री के संबोधन में भी उसे बाकियों की तरह जगह नहीं मिली।

22 मार्च के 'जनता कर्फ्यू' और कई राज्यों के लॉकडाउन के बाद 25 मार्च से देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन लागू कर दिया गया। प्रवासी मजदूरों के शहरों से पलायन की स्थिति पैदा हुई, लेकिन यह भी सच है कि देश के सामने खाने-पीने की वस्तुओं का कोई बड़ा संकट पैदा नहीं हुआ। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि केंद्रीय पूल में 550 लाख टन से अधिक गेहूं और चावल मौजूद था। इसकी उपलब्धता से ही कहीं कोई बड़ा संकट पैदा नहीं हुआ। कोरोना वायरस के चलते जहां दुनिया थम-सी गई है और देश में भी आर्थिक गतिविधियां लगभग बंद हैं, वहीं, किसानों को अपने खेत और फसल की चिंता सबसे अधिक है।

थमी कृषि गतिविधि

मार्च की शुरुआत में ही रबी फसलों की कटाई का दौर शुरू हो जाता है लेकिन लगभग उसी समय कोविड-19 महामारी के चलते कई तरह के प्रतिबंध लगने शुरू हो गए। इस सीजन में सबसे पहले सरसों की कटाई शुरू होती है और लगभग उसी के साथ आलू की खुदाई होती है। दोनों में बड़े पैमाने पर मजदूरों की जरूरत है। लेकिन एक के बाद एक प्रतिबंधों और लॉकडाउन ने इन दोनों फसलों के खेत से घर तक आने तथा उनकी मार्केटिंग में बाधा पैदा कर दी थी। उसी दौरान दलहन की फसलें भी तैयार हो गईं। सरकार के दावों के बावजूद इन फसलों की मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और गोदामों तक पहुंचने की दिक्कतें खत्म नहीं हो पा रही हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद की जाए। इसके लिए राज्यों से रिवाल्विंग फंड बनाने को कहा गया है। केंद्र सरकार के लिए सरकारी खरीद का जिम्मा उठाने वाली एजेंसी नेफेड को भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अभी तक खरीद नगण्य रही है। देश में 2019-20 में 230 लाख टन दालों के उत्पादन का अनुमान है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, राज्यों को कह तो दिया गया है लेकिन अभी सरकारी खरीद का काम शुरू नहीं हो सका है।

हर फसल के नुकसान अलग

असल में देश के अधिकांश हिस्सों में आलू किसानों को काफी नुकसान भुगतना पड़ रहा है और कई जगह किसानों को फसल खेतों में ही छोड़नी पड़ी है। दूसरी ओर खाद्यान्न और तिलहन फसलों पर सरकार का अधिक फोकस रहता है और इन फसलों को अधिक समय तक स्टोर करके भी रखा जा सकता है। जबकि फल और सब्जियों जैसे हार्टिकल्चर उत्पादों के मामले में स्थिति ऐसी नहीं है, और इनके किसानों को लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कर्नाटक में टमाटर किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में जल्दी खराब होने वाली फसलों के लिए स्टोरेज की सुविधा नहीं है। मंडियों में कामकाज में कमी और अंतरराज्यीय ट्रांसपोर्टेशन में पैदा हुई दिक्कतों से यह नुकसान काफी बढ़ा है। ताजा सब्जियों के मामले में पंजाब से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में किसानों को काफी नुकसान भुगतना पड़ा है। देश में हार्टिकल्चर उत्पादन का आकार खाद्यान्नों से अधिक हो गया है। साथ ही, इनकी कीमत भी काफी अधिक होती है। कई सब्जियों के बीज की कीमत चालीस हजार रुपये किलो तक किसान को चुकानी पड़ती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की किस्मों के लिए जरूरी केमिकल भी इन कंपनियों से ही खरीदने पड़ते हैं, जो काफी महंगे होते हैं।

फल-सब्जियों का संकट

कृषि और सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले एक सार्वजनिक संस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि देश में हार्टिकल्चर किसानों को नुकसान काफी ज्यादा है। सरकार का ज्यादा फोकस खाद्यान्न और गन्ना जैसी फसलों पर होता है। इस समय दक्षिणी राज्यों में तोतापुरी और बंगनपल्ली आम भी बाजार में आने लगे हैं और महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अल्फांसो

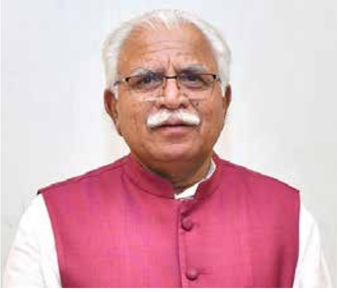

किसानों को निर्धारित तारीख और समय पर ही अपनी फसल लेकर मंडी में आना पड़ेगा, उन्हें इसकी सूचना फोन और एसएमएस के जरिए दी जाएगी

मनोहर लाल खट्टर

मुख्यमंत्री, हरियाणा

जरूरत से ज्यादा स्टॉक : एफसीआइ के गोदाम में रखा गेहूं, केंद्रीय पूल में 550 लाख टन खाद्यान्न से सरकार को राहत

किसानों के लिए संभावित पैकेज

- फसल ऋण पर सरकार दे सकती है ब्याज में राहत
- किसानों को टर्म लोन पर भी ब्याज में राहत संभव
- मेकैनाइज्ड हार्वेस्टिंग के लिए राहत पैकेज देने पर विचार
- चारे के लिए किसानों को मिल सकती है सब्सिडी
- बागवानी किसानों को भी कुछ सहूलियतें देने का प्रस्ताव

आम की फसल भी अब तैयार है लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह बाजार तक कैसे पहुंचेगा, इसको लेकर कोई साफ रणनीति नहीं है। अंगूर किसानों को घरेलू और निर्यात दोनों मोर्चों पर भारी घाटे का सामना करना पड़ा है। दक्षिणी राज्यों में मिर्च, गुजरात में जीरा, सौंफ और धनिया की फसल कट चुकी है लेकिन मार्केटिंग का संकट है। इनका निर्यात भी अटक गया है। वैसे, फल और सब्जियों की कीमत में भारी गिरावट रोकने के लिए एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। इसके लिए 2020-21 के बजट में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान भी है, लेकिन इसका उपयोग होता नहीं दिख रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस पर जल्दी ही काम शुरू होगा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण यानी पीएम आशा योजना है, जिसमें दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम जाने पर किसानों को बाजार मूल्य और एमएसपी के बीच के अंतर के भुगतान का प्रावधान है। इसके तहत 2020-21 में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने *आउटलुक* को बताया कि इस योजना के तहत दलहन और तिलहन की खरीद होती है। राज्यों को इसकी अनुमति दे दी गई है। नेफेड अधिकृत एजेंसी है और उसे सरकार ने 39 हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी दे रखी है। इसलिए पैसे की दिक्कत नहीं होगी। सरसों और दालों की खरीद शुरू तो हुई है लेकिन अभी यह कुछ हजार टन ही है। उम्मीद है इसमें अब तेजी आएगी।

डेयरी और पोल्ट्री की पीड़ा

कोरोना वायरस से फैलने वाली महामारी कोविड-19 को लेकर तमाम भ्रामक खबरों और भ्रांतियों के चलते पोल्ट्री किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पोल्ट्री उत्पादों की कीमतें गिरकर एक-तिहाई से भी कम रह गई हैं जिसके चलते करीब सवा लाख करोड़ रुपये का कारोबार बड़े संकट में फंस गया है। बाजार तक उत्पादन पहुंचाने की दिक्कतें, दुकानों के बंद होने और थोक मार्केट के आधे-अधूरे संचालन इन किसानों की कमर तोड़ने वाले साबित हुए हैं लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी कोई सुध नहीं ली है।

एक बड़ा पहलू दूध उत्पादक किसानों का भी है। देश में रोजाना करीब 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है जिसमें करीब 40 फीसदी किसान खुद उपयोग कर लेता है और 60 फीसदी बाजार में पहुंचता है। इसमें करीब एक-तिहाई यानी करीब नौ करोड़ लीटर दूध ही संगठित बाजार में आता है, जिसकी खरीद सहकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में होती है। बाकी 40 फीसदी यानी करीब 20 करोड़ लीटर दूध असंगठित क्षेत्र में जाता है। लॉकडाउन के चलते दूध और कुछ दुग्ध उत्पादों को छोड़ दें, तो ज्यादातर खोया, पनीर, घी, छेना, आइसक्रीम जैसे दुग्ध उत्पादों

विरोधाभास: बैतूल में खेत में टमाटर फेंकते किसान, जबकि शहरों में ये महंगे बिक रहे हैं

का उत्पादन और बिक्री लगभग बंद है। इससे किसानों के मद में दूध की कीमतें गिर गई हैं। ये कीमतें संगठित क्षेत्र में 10 फीसदी तक गिरी हैं, तो असंगठित क्षेत्र में ज्यादा गिरी हैं यानी किसानों को हर रोज सैकड़ों करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूध का उत्पादन रुक नहीं सकता है क्योंकि पशु से हर रोज दूध दुहना अनिवार्य है। यानी यह ऐसा उत्पाद नहीं जिसका भंडारण किसान कर पाए और सही कीमत होने पर उसे बेचे। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) यानी अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.एस. सोढ़ी ने *आउटलुक* को बताया कि सहकारी संस्थाओं की दूध खरीद 10 फीसदी तक बढ़ गई है। असल में मिल्क पाउडर, बटर, आइसक्रीम और चीज बनाने वाले तमाम छोटे कारोबारियों का उत्पादन बंद है और दूध का उपयोग करने वाले तमाम कारोबार, होटल और रेस्तरां बंद हैं। सोढ़ी के मुताबिक, यही वजह है कि हमारे पास अधिक दूध आ रहा है और हमने दूध की खरीद कीमतों में कोई कमी नहीं की है। उद्योग सूत्रों के मुताबिक निजी क्षेत्र ने दूध की खरीद कीमत में 15 रुपये प्रति लीटर तक की कमी कर दी है। एक अनुमान के मुताबिक दूध किसानों को हर रोज करीब 200 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। ऐसे में 40 दिन के लॉकडाउन का मतलब है करीब आठ हजार करोड़ रुपये का नुकसान। गरमी का सीजन शुरू हो गया है और दूध का उत्पादन घटने लगा है। इसलिए उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए तैयार रहना होगा। यह बात अलग है कि किसानों को तो घाटा सहना पड़ रहा है।

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने *आउटलुक* से कहा, "दूध, फल-सब्जी, फूल, मधुमक्खी पालक और पोल्ट्री किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। सरकार को जितनी जल्दी हो सके, उनके लिए आर्थिक मदद की घोषणा करनी चाहिए। समय रहते मदद नहीं मिली तो बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करने को मजबूर होंगे।"

गेहूं का गम

अब बात सीजन की मुख्य फसल गेहूं की। 2019-20 के रबी सीजन में देश में 10.62 करोड़ टन गेहूं के रिकार्ड उत्पादन का अनुमान है और इसकी खरीद अगर सरकार ठीक से कर पाती है तो यह 350 लाख टन तक पहुंच सकती है। लेकिन अभी लगभग पूरी फसल खेतों में खड़ी है और सरकारी खरीद भी शुरू नहीं हो सकी है। लॉकडाऊन तीन मई तक बढ़ गया है तो ऐसे में गेहूं की कटाई और मार्केटिंग बड़ी चुनौती लेकर आ रही है। देश के मध्य भाग में गेहूं की कटाई मार्च के अंत में शुरू हो जाती है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद भी सबसे पहले शुरू होती है लेकिन 25 मार्च से लॉकडाउन के चलते वहां भी फसल की कटाई में देरी आई है। हालांकि मध्य प्रदेश में कटाई तेजी से चल रही है लेकिन वहां अभी तक गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो सकी है। सरकार का कहना है कि 15 अप्रैल से शुरू की जाएगी। लेकिन यहां भी बड़ा सवाल यह है कि कोविड-19 महामारी के मौजूदा समय में यह कितना संभव हो सकेगा कि किसानों की बाजार में आने वाली पूरी फसल की खरीद की जा सके। पिछले कुछ बरसों का अनुभव मध्य प्रदेश में बेहतर रहा है और वहां की सरकार ने किसानों का डाटा बैंक तैयार कर एसएमएस भेजकर किसानों का मंडी आने का समय तय करने की प्रक्रिया अपनाई है, लेकिन इसके लिए किसानों का पंजीकृत होना भी जरूरी है। दूसरी ओर अभी कटाई के लिए मजदूरों का भारी संकट है, वहीं सरकारी खरीद के समय भी यह स्थिति बनी रही तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं।

जहां तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का सवाल है तो पंजाब ने कुछ तैयारियां की हैं। वहां करीब छह हजार सरकारी खरीद केंद्र बनाए जा रहे हैं ताकि हर दो गांव पर एक खरीद केंद्र होने से किसानों को दूर नहीं जाना पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त का भी पालन हो सके। पंजाब में सबसे पहले दौर में ही कोरोनावायरस के संक्रमण फैलने के मामले सामने आए थे और राज्य सरकार ने लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला ले लिया। ऐसे में जहां इस समय पंजाब में गेहूं की कटाई आधे से अधिक हो जानी चाहिए थी वह अभी शुरू हो रही है। राज्य सरकार का दावा है कि वहां करीब पांच हजार कंबाइन हार्वेस्टर होने के चलते मैकेनाइज्ड कटाई अधिक हो सकेगी। लेकिन राज्य में किसान करीब 70 से 80 फीसदी कटाई कंबाइन से करते हैं और बाकी कटाई हाथ से होती है। इसकी वजह पशुओं के लिए चारे की जरूरत है। कंबाइन हार्वेस्टर से कटाई में भूसा नहीं मिल पाता है। साथ ही जब यह फसल बिकने के लिए पहुंचेगी तो इसके लिए बड़े पैमाने पर मजदूरों की जरूरत होगी। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि हमारे पास करीब चार लाख पंजीकृत मनरेगा मजदूर हैं और हम

उन्हें इसके लिए उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हर काम की प्रकृति अलग होती है इसलिए मनरेगा मजदूर इसके लिए कितने कारगर होंगे यह अभी कहना मुश्किल है। इन मजदूरों को मिलने वाला मेहनताना किसान और कारोबारियों को ही देना होगा। ऐसे में राज्य का दावा बहुत पुख्ता नहीं रह जाता है।

हरियाणा सरकार 20 अप्रैल से सरकारी खरीद की बात कर रही है। देरी से गेहूं लाने वाले किसानों को 50 से 100 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने की बात राज्य सरकार ने कही है ताकि मंडियों में ज्यादा भीड़ न हो। इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों को गेहूं बिक्री के लिए पंजीकरण कराने के लिए कहा है। हरियाणा सरकार का कहना है कि वह केवल राज्य के किसानों का ही गेहूं खरीदेगी। असल में लॉकडाउन लागू होने के बाद जिस तरह से हरियाणा और पंजाब से मजदूरों का पलायन हुआ है उसके चलते गेहूं की कटाई और मार्केटिंग दोनों स्तरों पर मजदूरों के संकट का सामना करना पड़ेगा। इस परिस्थिति के चलते किसानों के ऊपर खर्च का बोझ बढ़ने वाला है।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो वहां इस समय किसान दोहरे संकट से जूझ रहा है। वहां चीनी मिलों द्वारा गन्ने का इंडेंट बढ़ा देने से किसानों का काम काफी बढ़ गया है और अगले करीब एक माह तक किसानों के लिए अतिरिक्त श्रमिकों की भारी जरूरत रहने वाली है। जहां एक ओर गन्ना की कटाई चल रही है, अब गेहूं की कटाई शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में अधिकांश कटाई हाथ से होती है क्योंकि यहां किसानों की जोत का आकार छोटा है और बहुत कम संख्या में ही किसान कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही गेहूं की कटाई के बाद तुरंत किसान गन्ने की बुवाई करते हैं जिसमें काफी ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसानों को काफी खर्च की जरूरत होती है। देश में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाले उत्तर प्रदेश में पहली बार चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य भुगतान का बकाया 15 हजार करोड़ रुपये को पार कर गया है। ऐसे में, समझा जा सकता है कि किसानों को पैसे की कितनी किल्लत से गुजरना पड़ रहा है और वह भी ऐसे समय में जब महामारी का संकट है। उत्तर प्रदेश गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है लेकिन यहां केवल चार हजार खरीद केंद्र बनाने की अभी सिर्फ बात हो रही है। पिछले साल जहां पंजाब में 129.12 लाख टन और हरियाणा में 93.20 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी, वहीं केवल 37 लाख टन की सरकारी खरीद के साथ उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर रहा था। उससे कहीं कम उत्पादन वाले मध्य प्रदेश में पिछले साल 67.25 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। उत्तर प्रदेश में इस मुश्किल घड़ी में किसानों को अतिरिक्त मजदूर कैसे मिलेंगे इसको लेकर राज्य सरकार के पास कोई पुख्ता योजना अभी नहीं है।

लॉकडाउन से सारी फसले बर्बाद हो रही हैं, सरकार को राहत पैकेज देने की जरूरत है, मैंने प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से 4,000 करोड़ रुपये का पैकेज देने की मांग की है

राजू शेट्टी

अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संगठन

सरकारी मदद कितनी

हमें सरकार के किसानों के लिए घोषित सहायता पर भी चर्चा करने की जरूरत है। अभी तक किसानों को कोई प्रत्यक्ष मदद नहीं मिली है। प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि की पहली किस्त का 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान अप्रैल में करीब सात करोड़ किसानों को हो चुका है। लेकिन यह तो पहले से लागू योजना है और उनकी पहली किस्त मिलने का समय हो गया था, इसलिए इसे कोई नया पैकेज नहीं माना जा सकता है। वहां किसानों के लिए फसली ऋण को चुकाने की अवधि 31 मई की गई, जिसमें समय से भुगतान पर लागू होने वाली चार फीसदी ब्याज की रियायती दर लागू रहेगी। लेकिन जब किसानों का उत्पादन ही बाजार में एक माह देर से पहुंचेगा तो वह भुगतान कहां से करेगा। इसके साथ ही कोविड महामारी के चलते जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोगों के बेरोजगार होने की आशंका पैदा हो गई है उसके चलते कृषि उत्पादों की मांग में गिरावट तय है। यानी आने वाले दिनों में इनकी कीमतें गिर सकती हैं और किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के अध्यक्ष राजू शेट्टी ने कहा, "महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर किसान फल-सब्जियां, फूलों और दूध के कारोबार में हैं। लॉकडाउन की वजह से सारी फसल बर्बाद हो रही है। सरकार को राहत पैकेज देने की जरूरत है। मैंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों को पत्र लिखकर 4,000 करोड़ रुपये के पैकेज की मांग की है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।"

जहां तक फसलों की मार्केटिंग की बात है तो उसके लिए कृषि मंत्रालय लगातार जोर दे रहा है कि फार्मर्स प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (एफपीओ) को सीधे किसानों से खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वैसे तो पांच हजार से ज्यादा एफपीओ पंजीकृत हैं लेकिन इनमें अधिकांश का कारोबार कुछ लाख ही है और इनका दायरा भी सीमित है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम के तहत खरीद में छूट दी गई है। साथ ही, राज्यों से कहा गया है कि वह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी (एपीएमसी)

कितना सहें: निर्यात नहीं हो पाने से महाराष्ट्र के अंगूर किसानों को नुकसान

कैसे हो सप्लाई: **ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में उत्तर प्रदेश में मंडियों तक आलू भेजना हुआ मुश्किल**

एक्ट में बदलाव कर किसानों से सीधे खरीद की छूट कारोबारियों को दे। लेकिन जिस एपीएमसी कानून को राज्य सरकारें बड़े राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं क्या वह उसे बदल देंगी। अगर यह संभव है तो पहले केंद्र सरकार को भाजपा शासित राज्यों में इस बदलाव की शुरुआत के लिए वहां के मुख्यमंत्रियों को तैयार करना चाहिए। आढ़तियों की मजबूत लॉबी और दूसरे राजनीतिक मकसद इसमें संशोधन नहीं होने देते हैं। जहां तक ई-नाम का सवाल है तो वह बहुत कारगर नहीं क्योंकि ज्यादातर बड़े कृषि उत्पादों को राज्य सरकारों ने उसके तहत कारोबार के लिए अधिसूचित ही नहीं किया है। केंद्र सरकार ने कृषि उत्पादों के लिए ट्रकों के एग्रीगेशन का प्लेटफार्म बनाने की बात कही है, लेकिन जिस तरह से किसानों और कृषि उत्पादों के परिवहन को लेकर पुलिस का रवैया है वह इन सब प्रयासों पर पानी फेर रहा है।

तमाम किसान संगठन और कृषि मामलों के जानकर कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़े पैकेज की वकालत कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन हो या राष्ट्रीय किसान संघर्ष कोआर्डिनेशन कमेटी या दूसरे संगठन, सभी ने इस संकट के दौर में किसानों के लिए वित्तीय पैकेज लाने के लिए प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है लेकिन अभी इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। जहां गेहूं की कटाई के लिए किसानों को सस्ता डीजल या सब्सिडी देने की मांग की जा रही है, वहीं अगले एक साल तक किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की मांग भी उठ रही है। असाधारण समय में असाधारण फैसला लेने की जरूरत है। प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्री और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. टी हक कहते हैं कि सरकार को प्रधानमंत्री किसान कल्याण निधि की सालाना राशि छह हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार कर देनी चाहिए।

एक बड़ी समस्या उन किसानों की है जो ठेके पर खेती करते हैं। किसान सम्मान निधि जैसी कोई सरकारी वित्तीय मदद उन्हें नहीं मिलती है क्योंकि वह कहीं पंजीकृत नहीं हैं। अलग-अलग राज्यों में ऐसे किसानों की तादाद 20 फीसदी से लेकर 40 फीसदी तक है। इस संकट में इनको कैसे मदद मिले यह एक बड़ा सवाल है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने *आउटलुक* को बताया कि किसानों के लिए वित्तीय राहत पैकेज पर काम चल रहा है। कर्ज की राहत के साथ हार्टिकल्चर उत्पादों के किसानों, कट फ्लावर की खेती करने वाले किसानों को भी कुछ राहत मिल सकती है। वहीं, फसली ऋण के अलावा टर्म लोन के लिए कुछ राहत का फैसला हो सकता है। हालांकि जब तक पैकेज घोषित नहीं हो जाता है, वास्तविकता का पता नहीं चलेगा।

लॉकडाउन के दौरान सरकार ने किसानों, खेती के संयंत्रों और मजदूरों की आवाजाही तथा खाद, बीज, पेस्टीसाइड की दुकानें खुली रखने की छूट देने जैसे कदम उठाए लेकिन यह कदम दिक्कतें सामने आने के बाद ही उठाए गए। वहीं, इसके बावजूद ग्रामीण इलाकों में पुलिस और प्रशासन का रवैया दिक्कतें पैदा करने वाला रहा है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा है। प्रशासन की सख्ती के कारण स्थानीय स्तर पर काफी दिक्कतें आ रही हैं। दिल्ली में भी किसानों को मंडियों में जाने में परेशानी हो रही है, जिससे खाने-पीने की चीजों की सप्लाई बाधित हो रही है।

केंद्रीय पूल में 550 लाख टन से ज्यादा का खाद्यान्न भंडार है जो तय मानकों के दोगुना से भी अधिक है। गेहूं की बंपर फसल को देखते हुए 300 लाख टन से अधिक की सरकारी खरीद होने का अनुमान है। यही वह ताकत है जिसके चलते सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए उठाए गए कदमों के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन करने का फैसला लिया। इसी के चलते एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि सरकार को खाद्यान्नों के भंडार गरीबों के लिए खोल देने चाहिए। इसके साथ ही एक बड़ी ताकत देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का तंत्र है जिसके जरिए खाद्यान्न जरूरतमंदों को मुहैया कराए जा रहे हैं। वैसे तमाम उदारीकरण समर्थकों की राय रही है कि हमें खाद्यान्न के वितरण की सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्था और खाद्यान्नों की सरकारी खरीद व्यवस्था को समाप्त कर गरीबों को फूड कूपन देने की प्रणाली लागू कर देनी चाहिए। इससे वह अपनी मर्जी के मुताबिक बाजार से भोजन खरीद सकेंगे। इस तरह के आर्थिक सुधार देश में अभी तक लागू नहीं हो सके, उसी के चलते आज हम कोविड-19 जैसी महामारी के दौर में देश के हर व्यक्ति के भोजन को लेकर आश्वस्त हैं और यह आश्वासन मिला है देश के उन करोड़ों किसान की बदौलत जो इस महामारी के संकट के समय में भी अपने जीवन पर खेलकर देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए अगर कोरोना योद्धा की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले पायदान पर खड़े होने वालों में देश का किसान है। जो भले ही देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में हिस्सेदारी के मामले में 15 फीसदी से नीचे आ गया है लेकिन अभी भी देश की आधे से ज्यादा आबादी की रोजी-रोटी कृषि क्षेत्र से ही चलती है। यही वजह है कि शहरों से पलायन करने वाले करीब चार करोड़ लोग जब कोई विकल्प ढूंढ रहे थे तो उनके सामने गांव जाने का ही विकल्प सबसे ऊपर था, जहां अभी भी उन्हें जीवनयापन की कुछ उम्मीद दिखती है।

दूध, फल-सब्जी, पोल्ट्री किसानों को बहुत नुकसान हुआ, सरकार ने समय रहते इन्हें मदद नहीं दी तो बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर होंगे

राकेश टिकैत

राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन

किसान को मिले मदद

सप्लाई चेन प्रभावित हुई तो कृषि क्षेत्र का संकट दुश्चक्र बन जाएगा, जिससे निकलना होगा कठिन

डॉ. टी. हक

कृषि क्षेत्र पिछले कई साल से संकट का सामना कर रहा है और कृषि से होने वाली कमाई में लगातार गिरावट आई है। ऐसे में कृषि पर निर्भर परिवारों की बचत भी घटी है। लिहाजा, कृषि क्षेत्र में निवेश घटा है और कृषि क्षेत्र की विकास दर भी गिरी है। आंकड़ों से समझें तो 2009 से 2013 की अवधि में कृषि क्षेत्र की सालाना विकास दर 4.9 फीसदी थी, जो अब गिरकर 2.7 फीसदी पर आ गई है। ऐसे में, कोविड-19 का संकट कृषि क्षेत्र के लिए नई चुनौती लेकर आया है, इसलिए सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो स्थिति बदतर हो सकती है।

कृषि निर्यात और औद्योगिक विकास दर में गिरावट से बेरोजगारी भी बढ़ी है। नतीजतन, खाद्यान्न और कृषि से संबंधित दूसरे उत्पादों की कीमतों में गिरावट आई है। इससे कृषि आय नकारात्मक स्तर पर पहुंच गई है। निर्यात होने वाले बासमती चावल, कपास, भैंस के मांस और दूसरे उत्पादों की मांग में भारी गिरावट है और आपूर्ति में भी दिक्कतें हैं।

इसके अतिरिक्त कृषि श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर में भी कमी आई है। छोटे और सीमांत किसानों की भी करीब 34 फीसदी आमदनी कृषि मजदूरी पर ही निर्भर है। ऐसे में, कोविड-19 की वजह से लागू हुए लॉकडाउन ने कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल असर डाला है। इससे कृषि कारोबार ठप हो गया है जो कृषि क्षेत्र का संकट बढ़ा रहा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) के अनुसार अनौपचारिक क्षेत्र की तकरीबन 40 करोड़ आबादी ग्रामीण इलाकों में काम करती है। कोरोना की वजह से इस बड़ी आबादी के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है और ये लोग गरीबी के कुचक्र में फंस सकते हैं। लिहाजा, कृषि क्षेत्र पर बड़े स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके कई अहम कारण हैं। एक तो यही है कि लंबे लॉकडाउन से रबी की फसल की कटाई में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि इस समय श्रमिकों का संकट है। हरियाणा और पंजाब की सरकारों ने जिस तरह समय पर कदम उठाकर रबी पैदावार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के कदम उठाए हैं, वैसी तत्परता दूसरे राज्यों ने नहीं दिखाई। यही नहीं, अगर रबी पैदावार की खरीद में देरी की गई तो इस बात की भी आशंका है कि बारिश या तूफान से फसल खेतों में रहने से बर्बाद हो सकती है। दूसरी अहम बात यह है कि कर्नाटक और अन्य जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि मजदूरों की कमी और ढुलाई-व्यवस्था न हो पाने से फसल की कटाई नहीं हो पा रही है और किसान जल्द खराब होने वाली फसलों को बाजार तक भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मंडियां भी कई जगह बंद हैं। ऐसा तब है जब सरकार ने लॉकडाउन में भी कृषि गतिविधियों को चालू रखने और मंडियों को खोलने की बात कही है। जल्द खराब होने वाली फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता भी काफी कम है।

तीसरी बड़ी समस्या यह है कि सीमांत किसान और भूमिहीन मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। वे अमूमन अनाज और जरूरी खाद्य वस्तुओं की हर रोज खरीदारी करते हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपूर्ति प्रभावित हुई है। ऐसे में, उनके सामने खाने-पीने का संकट खड़ा हो गया है। इस समय भारतीय खाद्य निगम के पास करीब 5.6 करोड़ टन अनाज का स्टॉक है। सरकार इस स्टॉक को गरीबों के लिए वितरण में उपयोग कर सकती है, जिसका वित्त मंत्री ने पहले ही ऐलान कर दिया है। लेकिन यह कदम तभी सार्थक होगा जब इसे बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। लॉकडाउन से मत्स्य और पोल्ट्री उत्पादों पर भी भारी असर हुआ है। इससे छोटे किसानों के जीवन पर संकट बढ़ गया है। चौथी अहम बात यह है लॉकडाउन से हजारों प्रवासी मजदूर अचानक फंस गए हैं। बिना किसी तैयारी के अचानक लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं। राज्यों और शहरों के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। ऐसे में जो जहां है वहीं फंस गया है। प्रवासी मजदूर कई सीमांत किसानों की जरूरतें पूरी करते हैं और कृषि क्षेत्र की सप्लाई चेन को बनाए रखते हैं। उनके फंसे होने से यह चेन पूरी तरह से टूट गई है।

पांचवी चिंता यह है कि रबी फसलों की कटाई में देरी से खरीफ की बुवाई भी देर से हो पाएगी। इससे कई क्षेत्रों में उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा बीज और उर्वरक की कमी भी समस्या खड़ी करेगी। खरीफ सीजन में करीब 25 करोड़ क्विंटल बीज की जरूरत पड़ती है जिसका मार्च से मई के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से यह प्रक्रिया ठप हो गई है। भले ही केंद्र और राज्य सरकारों ने कृषि गतिविधियों को लॉकडाउन से अलग रखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन लोगों को स्थानीय पुलिस और प्रशासन से उत्पीड़न भी झेलना पड़ रहा है। कई स्थानों पर पुलिस ने कृषि के लिए जरूरी उत्पाद उपलब्ध कराने वाली दुकानें भी बंद करा दी हैं।

इसमें कोई दो राय नहीं कि कोविड-19 के संकट को देखते हुए लॉकडाउन बेहद जरूरी है। लॉकडाउन से वायरस का संक्रमण कम से कम हो सकेगा। लेकिन यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि इस कवायद में सप्लाई चेन प्रभावित न हो, क्योंकि ऐसा होने से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।

इसके अतिरिक्त भारतीय खाद्य निगम, नेफेड और राज्य सरकारों को बेहतर तालमेल के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी फसलों के लिए जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई पारदर्शी तरीके से किसानों को तुरंत करनी चाहिए। इससे किसान को इस संकट से उबरने में मदद मिलेगी और खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने में वह सक्षम होगा। इसके साथ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सलाह देनी चाहिए कि वे खरीफ फसलों के लिए किसानों को कम अवधि के ब्याज-मुक्त कर्ज उपलब्ध कराएं, ताकि वे फसल के लिए इनपुट खरीद सकें। साथ ही, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि भी दोगुनी कर देनी चाहिए। इसमें बंटाईदार और भूमिहीन मजदूरों को भी शामिल करना चाहिए।

आने वाले दिनों में कोविड-19 से लड़ने में किसान और मजदूरों की अहम भूमिका रहने वाली है इसलिए उन्हें प्रोत्साहन और सम्मान दिए जाने की जरूरत

अंत में, हमें यह समझना होगा कि कोविड-19 भयंकर बीमारी है। इससे बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गई हैं और आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति भी रुक गई है। हमें इससे मिलकर लड़ने की आवश्यकता है और यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी भूखा न मरे। आने वाले दिनों में कोविड-19 से लड़ने में किसान और मजदूरों की अहम भूमिका रहने वाली है, इसलिए उन्हें प्रोत्साहन और सम्मान दिए जाने की जरूरत है।

(लेखक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व चेयरमैन और प्रमुख अर्थशास्त्री हैं)

अफवाहों और लॉकडाउन से बेहाल पोल्ट्री-डेयरी सेक्टर

देश को खाद्य सुरक्षा के साथ रोजगार की भी जरूरत, यह कृषि और पशुधन पर ध्यान देकर ही संभव

विजय सरदाना

कोविड-19 महामारी जैसे-जैसे नए इलाकों में फैल रही है, लोगों की आमदनी, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। यह महामारी समूची दुनिया और भारत के लिए भी अब तक की सबसे मुश्किल चुनौती है। इसके प्रकोप से बचाव के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे उपायों से विशाल आबादी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता से मुश्किलें आ रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारें इस समस्या पर काम कर रही हैं। शुरू में कुछ भ्रम की स्थिति थी लेकिन फीडबैक के आधार पर उपाय किए जा रहे हैं। लॉकडाउन समस्या की शुरुआत भर है। इसका असर समाज के हर पहलू पर दिखेगा। भारत को योजनाएं बनाने में काफी सावधानी की जरूरत है। सीमित संसाधन होने के कारण लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की रिकवरी एक चुनौती भरा काम है।

खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन केंद्रों से उपभोग केंद्रों तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक है कि खाद्य आपूर्ति की श्रृंखला ठीक ढंग से काम करे। लॉकडाउन के चलते कृषि और सप्लाई चेन के बहुत से काम बाधित हो रहे हैं। प्रवासी और कुशल मजदूरों की अनुपलब्धता के चलते फसल की कटाई, ढुलाई जैसे काम नहीं हो पा रहे हैं। एक तरफ किसान फसल की कटाई और ढुलाई नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को खाने-पीने की चीजों की कमी का सामना करना पड़ रहा है या उन्हें ये वस्तुएं अधिक कीमत पर खरीदनी पड़ रही हैं। किसानों के लिए तो मांस, अंडा, दूध, गेहूं, सब्जियां और अन्य फसलों की कीमत घट गई है, फिर भी उपभोक्ता इन्हें महंगे दाम पर पा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते होटल, रेस्तरां, मिठाई की दुकानें और चाय की दुकानें बंद होने के चलते दूध, चिकन, अंडे, खाद्य तेल आदि की बिक्री घट गई है।

लॉकडाउन के अलावा सोशल मीडिया पर चलने वाली नकारात्मक खबरों से भी किसानों को नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया पर यह गलत खबर फैल गई कि चिकन खाने से कोविड-19 बीमारी हो सकती है। इस अफवाह ने दो करोड़ लोगों की आजीविका को न सिर्फ प्रभावित किया, बल्कि 1.25 लाख करोड़ रुपये के पोल्ट्री सेक्टर को बर्बाद कर दिया। इसका असर मक्का, मोटे अनाज और तिलहन पर भी पड़ेगा। खाद्य सुरक्षा की सफलता लोगों को खाद्य पदार्थों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अगर घर में खाना नहीं होगा तो लोग उसकी तलाश में सड़कों पर निकलेंगे। इस तरह भीड़ बढ़ने से कोविड-19 को फैलने से रोकने की कोशिशें बेकार चली जाएंगी।

कृषि उपज और पशुधन सप्लाई चेन की दिक्कतें

भारत में कृषि और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं। लाखों छोटे किसानों को बुवाई, कटाई, छंटाई, ढुलाई, पैकेजिंग और वेयरहाउसिंग जैसे कामों के लिए श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। श्रमिकों के अभाव में ये सारे काम रुक गए हैं। हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की बात तो करते हैं लेकिन पशुधन को अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं मानते। उनके लिए चारे का इंतजाम कैसे होगा, इसकी कोई योजना नहीं होती। इससे लगभग हर किसान परिवार प्रभावित होगा क्योंकि मिश्रित खेती ग्रामीण जीवन का आधार है। फसलों से किसानों को एक बार आय होती है जबकि पशुधन से हर परिस्थिति में उन्हें आय होती रहती है। लॉकडाउन से पोल्ट्री, दुग्ध, फल एवं सब्जियां जैसे जल्दी नष्ट होने वाले सेक्टर ज्यादा प्रभावित हुए हैं। एक तरफ किसान उपज रोक नहीं सकते, तो दूसरी तरफ परिवहन व्यवस्था ठप होने और होटल-रेस्तरां आदि न खुलने के चलते इन्हें बेच नहीं सकते। इन उपजों को संरक्षित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सौभाग्यवश, हमारे भंडारों में अनाज भरे हैं, सरकार लोगों के खाने के लिए उन्हें जारी कर सकती है। लेकिन पशुधन का क्या होगा? पोल्ट्री, डेयरी और फिशरीज जैसे सेक्टर के लिए हमारे पास कोई चारा नीति नहीं है।

किसानों की उचित आमदनी सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादों की मार्केटिंग महत्वपूर्ण है। एपीएमसी मंडियां संक्रमण फैलने की जगह बन गई हैं। इस बात का कोई मतलब नहीं कि शहर के दो करोड़ लोग उन दो या तीन कृषि मंडियों पर निर्भर करें जो काफी पुराने कानूनों के तहत चल रही हैं। जब भारत में खाद्य पदार्थों की कमी थी और शहर छोटे थे तब मंडियां ठीक थीं। लेकिन अब इन मंडियों में काफी भीड़ होने लगी है। इन मंडियों की वजह से कीमतों का कर्टेलाइजेशन होता है, किसानों को उचित कीमत नहीं मिलती और मांग तथा आपूर्ति के बीच असंतुलन पैदा होता है। यही समय है कि किसानों के लिए उचित मार्केटिंग व्यवस्था बने और बाजार तक उनकी पहुंच हो। लॉकडाउन के समय चिंता की एक और बात यह रही कि खाद्य पदार्थों की मांग और आपूर्ति को लेकर तरह-तरह की गलत सूचनाएं फैलाई गईं, इससे अनेक जगहों पर कालाबाजारी हुई।

लॉकडाउन से पोल्ट्री और दूध जैसे जल्दी नष्ट होने वाली चीजों के सेक्टर ज्यादा मुश्किल में, किसान न तो उपज रोक सकते हैं, न बेच सकते हैं

डेयरी सेक्टर पर असर

देश में रोजाना लगभग 50 करोड़ लीटर दूध पैदा होता है। इसका करीब 50 फीसदी हिस्सा कोऑपरेटिव और निजी डेयरियां खरीदती हैं। बाकी 50 फीसदी दूध रेस्तरां, मिठाई की दुकानों, हाइवे के किनारे के ढाबे ढाबों और चाय की दुकानों पर इस्तेमाल होता है। लॉकडाउन के चलते सभी दुकानें बंद हैं। इससे दूध की खपत 40 फीसदी घट गई है। किसानों के सामने इसे लंबे समय तक स्टोर करने की भी गुंजाइश नहीं है। कोऑपरेटिव और निजी डेयरी ने दूध की खरीद बढ़ाई है लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी स्थापित क्षमता इतनी नहीं है कि पूरे सरप्लस दूध का इस्तेमाल किया जा सके। बहुत से इलाकों में खरीद केंद्र न होने से वहां दूध की खरीद ही नहीं हो पा रही है। दुग्ध पाउडर बनाने वाली बहुत सी कंपनियां दूध खरीदना चाहती हैं लेकिन उनके पास इतनी कार्यशील पूंजी नहीं कि अतिरिक्त दूध खरीद सकें। इससे दूध के दाम पांच से दस रुपये प्रति लीटर घट गए हैं, यानी रोजाना 150 से 300 करोड़ रुपये का नुकसान है। पशुधन के लिए लॉकडाउन एक और तरीके से नुकसानदायक है। किसानों के पास नकद पैसे नहीं हैं, इसलिए वे मवेशियों को चारा नहीं खिला पा रहे हैं। चारे की उपलब्धता की भी समस्या है। ट्रकों का आवागमन बाधित होने और मजदूर न मिलने से देश के अनेक हिस्सों में चारे की कमी है। इससे चारा महंगा और दूध के दाम कम हो गए हैं। इस सेक्टर को तत्काल मदद की जरूरत है। यह मदद कार्यशील पूंजी और नुकसान की भरपाई दोनों रूप में होनी चाहिए।

लॉकडाउन का पोल्ट्री सेक्टर पर असर

भारत की 70 फीसदी आबादी मांसाहारी है और करीब दो करोड़ लोग पशु प्रोटीन सेगमेंट में कार्यरत हैं। मांसाहारियों के लिए पशु प्रोटीन इम्युनिटी बढ़ाने का एक जरिया भी है। लॉकडाउन के चलते पोल्ट्री सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पोल्ट्री किसान हर महीने दो किलो वजन वाले 50 करोड़ चिकन तैयार करते हैं। लॉकडाउन से पहले चिकन से कोरोनावायरस का संक्रमण फैलने की अफवाह के चलते इसकी बिक्री लगभग बंद हो गई। किसानों के लिए उत्पादन लागत लगभग 80 रुपये प्रति किलो है, जबकि चिकन के दाम 10 रुपये किलो तक गिर गए। नतीजा यह हुआ कि बहुत से पोल्ट्री फार्म दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गए हैं। लॉकडाउन के चलते एक तरफ किसान चिकन बेच नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पास मुर्गियों को खिलाने के लिए चारा खरीदने के पैसे नहीं हैं। कुछ हताश किसान मुफ्त में मुर्गियां बांटने लगे, तो कुछ ने उन्हें जिंदा दफन कर देने जैसा कदम भी उठा लिया। लॉकडाउन की अवधि में पोल्ट्री किसानों को 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होने का अंदेशा है। अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने के लिए किसानों को आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पोल्ट्री सेक्टर 70 फीसदी मक्का किसानों और 60 फीसदी तिलहन किसानों को बाजार उपलब्ध कराता है। पोल्ट्री सेक्टर में गिरावट से मक्का और सोयाबीन की कीमतें 10,000 रुपये प्रति टन घट गईं। इसका मतलब है कि पोल्ट्री संकट के चलते अनाज और तिलहन सेक्टर की वैल्यू 35 हजार करोड़ रुपये घट गई। जब तक पोल्ट्री सेक्टर खड़ा नहीं होता तब तक इन फसलों के दाम में भी तेजी की उम्मीद नहीं है। दोबारा काम शुरू करने के लिए पोल्ट्री किसानों को कार्यशील पूंजी की जरूरत है। उन्हें जो नुकसान हुआ है उसके चलते वे कर्ज लौटाने की स्थिति में भी नहीं हैं, उनके लिए कर्ज में राहत की कोई स्कीम लानी पड़ेगी।

50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन होता है देश में रोजाना

40 फीसदी घट गई है खपत होटल-दुकानें बंद होने से

150-300 करोड़ रुपये का नुकसान डेयरी सेक्टर को रोजाना

80 रुपये प्रति किलो किसानों की उत्पादन लागत, लॉकडाउन में चिकन के दाम 10 रुपये तक गिर गए

8,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अंदेशा पोल्ट्री सेक्टर को लॉकडाउन से

1.25 लाख करोड़ रुपये का है भारत का पोल्ट्री उद्योग

भारत का पोल्ट्री उद्योग 1.25 लाख करोड़ रुपये का है। इसके बावजूद आज तक कोई पोल्ट्री पॉलिसी नहीं बनी है। हमें तत्काल पोल्ट्री विकास की नीति लानी चाहिए। फल और सब्जियों की तरह सरकार को पोल्ट्री प्रोसेसिंग चेन विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए पांच वर्षों में करीब 20,000 करोड़ रुपये निवेश की जरूरत पड़ेगी। पोल्ट्री प्रोडक्ट का आधुनिक सप्लाई चेन विकसित करने के लिए सरकार को मौजूदा पंचवर्षीय योजना में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करना चाहिए। इससे पोल्ट्री किसानों और उपभोक्ताओं के साथ निर्यात में भी फायदा मिलेगा। सरकार यह रकम शून्य ब्याज वाले ग्रांट के रूप में दे सकती है, बाकी पैसा निजी निवेशक लगाएं। भारत में निर्यात हब बनने की क्षमता है। हमें इस संकट का सदुपयोग पोल्ट्री सेक्टर के आधुनिकीकरण, किसानों के कल्याण और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य पहुंचाने में करना चाहिए। पोल्ट्री सेक्टर को फिर से खड़ा करना सिर्फ अनाज और तिलहन सेक्टर के लिए जरूरी नहीं, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के लिए भी जरूरी है, क्योंकि इस पूरी वैल्यू चेन से करीब दो करोड़ लोग जुड़े हैं।

लॉकडाउन काफी जल्दबाजी में लागू किया गया, जिससे इसे लागू करने वाली एजेंसियों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। अत्यधिक बल प्रयोग से सप्लाई चेन जितनी प्रभावित हुई, उतनी तो कोरोनावायरस से भी नहीं हुई। ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों में अफरा-तफरी सी मच गई। सरकार को एक केंद्रीकृत पोर्टल और मोबाइल ऐप लाना चाहिए, जिसे सभी सरकारी अधिकारी अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और जरूरत पड़ने पर तथ्यों की सत्यता जांच कर सकें। फील्ड अफसरों को अपनी तरफ से नियमों की व्याख्या बंद करनी चाहिए क्योंकि इससे भ्रम और फैलता है। क्या करना है और क्या नहीं, यह लिखित में होना चाहिए।

कृषि और खाद्य सुरक्षा किस हद तक प्रवासी मजदूरों पर निर्भर है, यह बात भी अब जाहिर हो चुकी है। यही उचित समय है कि कृषि मजदूरों के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए। इसमें उनके अधिकारों और कर्तव्यों को भी परिभाषित किया जाए। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के साथ-साथ वृद्धावस्था पेंशन और उनके रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था हो। इस तरह प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। कृषि विपणन व्यवस्था पर भी गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत है। मौजूदा एपीएमसी बाजार पुराने पड़ चुके हैं। शहरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए इनका कोई मतलब नहीं रह गया है। बिचौलियों को कानूनी समर्थन देना और उसे आवश्यक बनाना एक तरह से भ्रष्टाचार को कानूनी रूप देने के समान है, जिससे किसानों का शोषण होता है। लॉकडाउन ने हमारी नीतिगत कमजोरियों को भी उजागर किया है। कृषि विपणन कानून में वैकल्पिक बाजारों की व्यवस्था होनी चाहिए। सुधारों के विरोधी एपीएमसी व्यापारी बाजार बंद करने की धमकी देकर नीति-निर्माताओं को ब्लैकमेल करते हैं।

कोविड-19 सभी विकल्पों को खंगालने और कृषि विपणन को सक्षम बनाने का मौका है। किसानों द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए। किसानों और उपभोक्ताओं के बीच लेन-देन की लागत को कम करने की कोशिश होनी चाहिए। पोल्ट्री, मछलियां, अंडे, फल और सब्जी जैसे जल्दी नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थों के लिए वेयरहाउसिंग और प्रोसेसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। इनमें निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। सरकार ने हाल ही पशुपालन मंत्रालय बनाया है। किसानों के फायदे और रोजगार सृजन के लिए सरकार को पशुधन विकास नीति बनानी चाहिए। इसमें मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, वेयरहाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन के साथ उपभोक्ताओं को शिक्षित करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

कृषि और पशुधन सेक्टर सबको खाद्य सामग्री मुहैया कराने के साथ 60 फीसदी आबादी को रोजगार भी देता है। 138 करोड़ आबादी वाले देश को खाद्य सुरक्षा के साथ रोजगार की भी जरूरत है। यह कृषि, पशुधन और इनसे जुड़ी गतिविधियों पर ध्यान देकर ही संभव है। कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन ने भारत के लिए कृषि के महत्व को पुनः रेखांकित किया है, क्योंकि कोई भी वैश्विक बाजार भारत को खिला नहीं सकता है। भारत की सार्वभौमिकता की रक्षा में कृषि क्षेत्र अहम भूमिका निभाएगा। सरकार को कृषि, किसान और खाद्य पदार्थों की सप्लाई चेन सुधारने पर तत्काल ध्यान देना चाहिए ताकि इनमें तेज रिकवरी हो सके।

(लेखक एग्रीबिजनेस और उपभोक्ता वस्तु उद्योग के लिए टेक्नो लीगल और रिस्क मैनेजमेंट विशेषज्ञ हैं)

'संकट में भी दूध की सप्लाई रखी बरकरार'

लॉकडाउन के दौरान दूध और इसके उत्पादों की सप्लाई को सुचारु रखना बड़ी चुनौती है। दूध की बड़ी मात्रा खपाने वाले हलवाई, आइसक्रीम निर्माता और अन्य उत्पाद बनाने वाले गायब हैं। इससे दूध उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। कुछ उत्पाद हॉट केक बन गए तो कुछ गायब हो गए हैं। डेयरी क्षेत्र पर कोरोना महामारी के असर पर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लि. (अमूल) के मैनेजिंग डायरेक्टर **आर.एस. सोढ़ी** *से आउटलुक के संपादक* **हरवीर सिंह** *ने बात की। प्रमुख अंश:*

लॉकडाउन में अमूल की दूध की खरीद की क्या स्थिति है। क्या इसमें वृद्धि हुई है?

हम रोजाना औसतन 260 लाख लीटर दूध खरीद रहे हैं। इसमें से 210 लाख लीटर दूध गुजरात और 50 लाख लीटर बाकी राज्यों से खरीदा जा रहा है। इस समय आइसक्रीम निर्माताओं और हलवाइयों की खरीद बंद होने के कारण हमारी खरीद करीब आठ फीसदी बढ़ गई है। इसमें से 140 लाख लीटर ताजे दूध की बिक्री हो रही है। थैलियों और टेट्रा पैक में दूध की बिक्री भी बढ़ी है। दही, मक्खन, देसी घी, चीज और पनीर की बिक्री बढ़ी है लेकिन आइसक्रीम की 95 फीसदी घट गई है। बेवरेज और क्रीम की भी बिक्री लगभग खत्म हो गई है।

अगर कई उत्पादों की बिक्री लगभग खत्म हो गई है, तो बाकी दूध कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं?

ज्यादा बिक्री वाले उत्पादों का उत्पादन बढ़ा दिया है। बेबी फूड का उत्पादन किया जा रहा है। बाकी दूध से हम मिल्क पाउडर बना रहे हैं। गर्मियों में मिल्क पाउडर की मांग बढ़ेगी। लॉकडाउन के कारण घरों में दुग्ध उत्पादों की मांग बढ़ी है।

लॉकडाउन से दूध के संग्रह और अन्य गतिविधियों में कोई दिक्कत आ रही है?

दूध आवश्यक वस्तुओं में आता है, इसलिए इसके परिवहन और दूसरी गतिविधियों में दिक्कत नहीं है। बिक्री पर भी असर नहीं है। पिछले साल अप्रैल में जितनी बिक्री थी, इस साल भी उतनी बिक्री हो रही है। अब भी लोग घबराहट में ज्यादा खरीद कर रहे हैं। इससे कुछ उत्पादों की उपलब्धता में दिक्कतें हैं।

अमूल ने तो किसानों के लिए मूल्य में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन क्या प्राइवेट डेयरियों ने दूध की खरीद कीमत घटाई है?

महाराष्ट्र में दूध की खरीद कीमत छह से आठ रुपये प्रति लीटर तक कम हुई है। पूर्वोत्तर में भी खरीद मूल्य घटा है। सभी जगह मूल्य घटा है। लेकिन यह अस्थायी दौर है। निजी कंपनियों के मिल्क पाउडर और घी वगैरह बनाने का काम प्रभावित होने से कीमत में कमी आई है। लेकिन यह समस्या दस दिन से ज्यादा नहीं रहेगी। हालात रोजाना सुधर रहे हैं। प्राइवेट डेयरियों ने पूंजी फंसने से बचाने के लिए उत्पादन घटा दिया है।

क्या कोऑपरेटिव और प्राइवेट डेयरियों ने दूध की खरीद घटाई है?

इस समय सभी कोऑपरेटिव डेयरियों के पास 15 से 20 फीसदी ज्यादा दूध है, लेकिन निजी डेयरियों ने खरीद और कारोबार घटाया है। प्राइवेट डेयरियां जब अच्छा मुनाफा देखती हैं तो पूरी तरह सक्रिय हो जाती हैं लेकिन ऐसे मौके पर पीछे हट जाती हैं।

क्या आपको श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है?

ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे भी आइसक्रीम प्लांट बंद हैं। ऐसे में हमने श्रमिकों और कर्मचारियों को मिल्क प्रोसेसिंग-पैकेजिंग और पनीर वगैरह के प्लांटों में लगा दिया है। मुंबई और दिल्ली में कुछ समस्या आई थी लेकिन हम श्रमिकों को खाने-पीने की पूरी सुविधा दे रहे हैं, इसलिए हमने जल्दी ही दिक्कत दूर कर ली।

मौजूदा चुनौतीपूर्ण दौर में आपने दूध सप्लाई दुरुस्त करने के लिए कैसी रणनीति बनाई?

हमारी प्रक्रिया शुरू होती है 36 लाख किसानों से और खत्म होती है दस लाख दुकानों पर। हमें स्थानीय प्रशासन से लेकर गृह मंत्रालय तक हर स्तर पर सहयोग मिला और हमें कहा गया कि दूध सप्लाई सुचारु रखी जाए। हमारे 5,000 दूध संग्रह केंद्रों से सप्लाई टैंकरों के जरिए खरीद करने और प्रोसेसिंग के बाद वितरण करने में एक घंटे की भी देरी नहीं हुई। कर्मचारियों, श्रमिकों और ड्राइवरों को प्रशासन से पास जारी करवाए गए। पैकेजिंग मैटेरियल के लिए हमने प्रशासन से आग्रह करके फैक्ट्रियां खुलवाईं और आवश्यक मेटीरियल की व्यवस्था की। हमारे लिए यह नई चुनौती नहीं है। नब्बे के दशक में गुजरात में दंगे हुए थे, तब हमें अपना कामकाज सुचारु रखने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना होता था।

आपने कोरोना वायरस के संक्रमण से अपनी सप्लाई चेन को कैसे बचाकर रखा?

हमने स्वास्थ्य विभाग से मदद ली। किसानों को जागरूक करने के लिए गांवों में बैनर लगाए, उन्हें बताया कि क्या करना है और क्या नहीं। दूध संग्रह के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं।

क्या अमूल ने अपनी मार्केटिंग और प्रचार रणनीति में भी बदलाव किया है?

कोरोना वायरस के चलते लोग समाचारों में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इसलिए हमने प्रचार रणनीति में बदलाव किया। जैसे ही रामायण और महाभारत के पुराने सीरियलों का प्रसारण शुरू हुआ, हम सामान्य मनोरंजन चैनलों की जगह न्यूज चैनलों पर विज्ञापन देने लगे। हमने प्रचार पर खर्च भी बढ़ा दिया, क्योंकि लोग घरों में बैठे हैं। दर्शकों का पूरा ध्यान टीवी कंटेंट, खासकर समाचारों पर है।

बीमारी की फिक्र कहां: जब लोग घरों में हैं, किसान खेत में जुटा

किसान को क्या चाहिए

कोरोना संकट के दौर में सरकार को वाकई किसानों की फिक्र है तो वह फौरन कुछ जरूरी कदम उठाए

वी.एम. सिंह

कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। हर व्यक्ति भविष्य को लेकर डरा हुआ है पर एक बात से पूरा देश निश्चिंत है कि हमारे पास खाने के लिए भरपूर अनाज है। दो महीने पहले ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ और अब समय गेहूं, सरसों आदि काटकर भंडारण का है। अगर किसान भी कोरोना के कारण घर बैठ जाएगा और अपनी फसल नहीं काटेगा या नई फसल नहीं लगाएगा तो अगले साल देशवासियों को अनाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। हमें यह देखना है कि एक तरफ आगे देश का भंडार भरा रहे इसलिए रबी की फसलों की कटाई भी हो और दूसरी तरफ किसान महामारी से भी बचे रहें। इसलिए सवाल उठता है कि क्या कोरोना से बचने के लिए सरकार ने किसान को कुछ सुविधाएं दी हैं? कुछ ऐसा किया है जिससे किसान की मदद हो या हर साल की तरह इन हालात में भी किसान को अपने आर्थिक रूप से कमजोर कंधों पर देश को खिलाने की जिम्मेदारी लेनी होगी?

विडंबना देखिए, एक तरफ जो देशवासी घरों में बैठे हैं उनके पास मास्क एवं सैनिटाइजर हैं और जो महामारी से लड़ते हुए फसल काट रहे हैं, उनके पास अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं है। गेहूं की हाथ से कटाई से लेकर थ्रेशर में गहाई करने तक, घट्टे के कारण दमे की बीमारी फैलती है। थ्रेशर में पुली डालने वाला व्यक्ति 10 मिनट भी गमछा लगाए बिना खड़ा नहीं रह सकता। भले छोटे किसान पशुओं के लिए भूसे के लालच में हाथ से गेहूं कटाई करते हैं पर वहीं हाथ से काटने के साथ-साथ गहाई करते वक्त एवं भूसा इकट्ठा करते वक्त सांस की बीमारी होने का खतरा रहता है। कोरोना के प्रकोप में यह बड़ा संकट हो सकता है। इसलिए सरकार को किसानों को कंबाइन हार्वेस्टर से कटवाने के लिए प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए। इस बारे में मेरे कुछ और सुझाव हैं –

(i) अगर किसान कंबाइन हार्वेस्टर से फसल काटेगा तो ही उसे 100 रुपये क्विंटल की प्रोत्साहन राशि मिले।

(ii) भूसे के लालच में न पड़े, इसलिए अगले एक साल के लिए दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर दिया जाए, जिससे किसान हरे चारे की व्यवस्था कर पाए क्योंकि दूध से ही ग्रामीणों की जीविका चलती है। आज जब लॉकडाउन में हलवाई, चाय वाले, ढाबे और होटल आदि बंद होने के कारण दूध के भाव गिर गए हैं, वहीं पशुओं के चारे का दाम बढ़ गया है। इस स्थिति में किसान को प्रोत्साहन देना और भी जरूरी है। यह सही है कि छोटा मजदूर कटाई की तरफ देखता है लेकिन हमें इस समय सांस की बीमारी या कोरोना के संक्रमण से भी बचाना है।

(iii) कंबाइन हार्वेस्टर में ब्रेकडाउन होता रहता है इसलिए हर ब्लॉक में मिस्त्री, स्पेयर पार्ट, वेल्डिंग एवं पंचर की एक या दो दुकानें खुली रहना जरूरी है।

(iv) सरकार खरीद केंद्रों को खेत या गांव से गेहूं खरीदने का निर्देश दे। पूर्व में भी सेंटर इंचार्ज खेतों से 100-200 रुपये प्रति क्विंटल नाजायज रूप से लेकर खरीदते थे।

(v) सब्जी गांव से मंडी तक नहीं पहुंच पा रही है। शहरों में सब्जियों के दाम चार गुना तक बढ़ गए हैं। इसलिए सब्जी मंडियां भी खोली जाएं और किसान को अपनी सब्जी मंडी तक लाने की अनुमति दी जाए। इससे किसान को फसल का दाम भी मिलेगा और शहर वालों को सब्जी सस्ते दाम पर भी उपलब्ध हो पाएगी।

(vi) जहां गन्ने के भुगतान के लिए किसान मारा-मारा फिर रहा है, वहीं कुछ जगहों पर सट्टे वाले गन्ने की पेराई किए बिना मिलें बंद हो गईं हैं। पिछले 25 वर्षों में जब भी मिलें निर्धारित सट्टे की पेराई के बिना बंद हुईं तो हाइकोर्ट ने आदेश दिए कि गन्ने के निर्धारित सट्टे की पेराई के बिना मिल बंद नहीं हो सकती, वर्ना खड़े गन्ने का भुगतान मिलों को करना होगा। 1996 में तो कोर्ट के आदेश के तहत बंद मिलों ने भी अगस्त तक मिलों ने गन्ने की पेराई की। गन्ने की बुवाई का समय निकल रहा है और निर्धारित सट्टे से अलग भी गन्ना खड़ा है। इसलिए सरकार को अतिरिक्त सट्टे बनवाने का निर्देश देना चाहिए, जिससे किसान का खेत खाली हो और वह आगे बुवाई कर पाए।

किसान को अन्न उगाने के लिए प्रोत्साहित करने को रियायतें देना और संक्रमण रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाना आवश्यक

कोरोना के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। किसानों की सुरक्षा के लिए न तो कोई इंतजाम किए गए और न ही कंबाइन से कटवाने वाले को प्रोत्साहन दिया गया। कम से कम गहाई करने वाले मजदूरों और किसानों को तथा खरीद केंद्र के मजदूरों को डॉक्टर वाले एन95 मास्क देना चाहिए ताकि कोरोना ओर दमे का प्रकोप कम हो।

सरकार ने लॉकडाउन से किसानों के लिए सहूलियतों की घोषणा की है, लेकिन कुछ अधिकारी आज भी किसानों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जो मजदूर सैंकड़ों मील चलकर अपने गांव कटाई करने पहुंचे, उन्हें रोका जा रहा है। कंबाइन, ट्रैक्टर ट्राली और लेबर को रोका जा रहा है। रिश्वत देने पर सब सही है, वरना लॉकडाउन का वास्ता देते हुए चालान काट देते हैं।

इन परिस्थितियों में किसान अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए फसल की कटाई करने बाहर निकल रहा है, तो उसे प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। लेकिन उसे तो अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी नहीं मिल रहा। देश की सेवा करने का उन्हें यह सिला मिल रहा है कि जहां गेहूं कट गया है वहां 1,925 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय किसानों को 1,400 से 1,700 रुपये प्रति क्विंटल मिल रहा है। किसानों की फसलों का पहले ही ओलावृष्टि से काफी नुकसान हो चुका है, इसलिए जरूरी है कि आदेश दिए जाएं कि किसान की पूरी फसल खेत से सरकारी भाव (एमएसपी) पर खरीदी जाएगी। अगर सरकार आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सारी फसल नहीं खरीद सकती, तो उसे आदेश देने चाहिए कि बाजार में कोई भी एमएसपी से कम मूल्य पर नहीं खरीदेगा, वरना उसके खिलाफ फौजदारी का मुकदमा चलेगा। आखिर पेट्रोल, डीजल, खाद, बिजली आदि सरकारी रेट से कम पर खरीदना जुर्म है ना। सब्जियां खराब हो रही हैं, फलों का भी बुरा हाल है। केला 2 से 4 रुपये किलो बिक रहा है। जहां किसान का नुकसान हो रहा है, वहीं उपभोक्ता को 4-5 गुना महंगा मिल रहा है क्योंकि कोरोना वायरस से मुकाबला करने के लिए इम्युनिटी बढ़ाना जरूरी है जो सब्जी और फल से मिलती है। इसलिए सब्जी और फलों का एमएसपी निर्धारित किया जाए जिससे एक तरफ किसान लुटने से बचेगा, वहीं उपभोक्ता को सस्ता मिलेगा। इसके साथ-साथ दूध का दाम हलवाई, रेस्तरां, ढाबा एवं चाय की दुकानें बंद होने से एकदम गिर गया है, इसलिए कुछ समय के लिए दूध का एमएसपी भी घोषित किया जाए। इस प्रयास से किसान और उपभोक्ता उजड़ती हुई अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं खड़ा रह पाएगा।

किसान हर बुरी घड़ी में देश के साथ खड़े रहते हैं। वे अपने बुरे हाल या नुकसान की किसी से शिकायत नहीं करते। वे खुदगर्ज हैं, लेकिन मांगते हैं तो केवल भगवान से। पिछले 20 सालों में 3.5 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं, पर देश का दिल उनके लिए नहीं पसीजा। इस आपदा के बाद तो देश को उसका सम्मान करना चाहिए, उसका हक देना चाहिए। देश में लगभग पांच करोड़ किसान, मजदूर गन्ने की खेती पर निर्भर हैं। उन्हें 2-2 साल तक अपनी फसल का पैसा नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि मिलें घाटे में हैं, पर कहीं न कहीं उन्हें सरकार से शह मिलती है। पिछले 15 साल में एक मिल मालिक ने दो से 16 मिलें बना लीं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में निजी मिलों की संख्या 35 से 95 हो चुकी है। किसान को गन्ना लगाने के लिए बैंक या सोसायटी से ऋण पर ब्याज लेना पड़ता है, वहीं हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी किसानों को मिल मालिकों ने ब्याज नहीं दिया। मिल मालिकों को 11-12% ब्याज दर पर बैंक लोन देते हैं। ऐसे में, जब मिल पर 15% ब्याज किसानों को देने का दबाव होगा, तो वे किसानों को तत्काल पैसे देंगे। कोरोना की महामारी में अगर सरकार किसान को गन्ने का पैसा ही दिलवा दे, तो एक तरफ गन्ने की बुवाई में और दूसरी तरफ उन्हें रहन-सहन में मदद मिलेगी। अगर सरकार ब्याज भी दिलवा दें, तो सोने पर सोहागा होगा।

पिछले कुछ साल में देहात के 90 फीसदी नौजवान खेती से अलग हो गए हैं। उनको नौकरी नहीं मिल रही। जो नौकरी में थे, उनकी नोटबंदी के बाद छूट गई। रियल एस्टेट बाजार में गिरावट होने से मजदूर गांव में वापस चले गए। नौजवान मायूस हैं, कुछ नशे में चले गए और कुछ क्राइम में। हम सबको मिलकर खेती को जिंदा कर नौजवानों को जीविका देने का काम करना है। लेकिन पहले कोरोना महामारी को रोकना है। शहर में इतनी तेजी से कोरोना नहीं फैलेगा, पर देहात में यह तेजी पकड़ सकता है। इसलिए हमें कोशिश करके एहतियात बरतना है। मुझे पूरा विश्वास है कि पहले हम कोरोना पर जीत हासिल करेंगे, उसके बाद खेती को जिंदा करेंगे और नौजवानों को जीविका देंगे।

(लेखक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक हैं)

कैसे चलेगा उद्योग का पहिया

क्लस्टर में करीब आधे प्रवासी श्रमिक, लॉकडाउन के बाद ज्यादातर लौट गए, उनके बिना काम शुरू करने में मुश्किलें

एस.के. सिंह, कुमार भवेश चंद्र, हरीश मानव

कोविड-19 महामारी के चलते लगा लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ने के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के छोटे-मझोले उपक्रमों (एसएमई) का संकट भी बढ़ गया है। पिछले महीने लॉकडाउन की घोषणा के बाद पूरे देश के लगभग चार करोड़ प्रवासी श्रमिक अपने गांव-घर के लिए प्रस्थान कर गए थे। अब जब सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू करने की अनुमति दी है, तो श्रमिकों की किल्लत उनके लिए सबसे बड़ा संकट होगा।

श्रमिकों की समस्या को लेकर सभी इकाइयां आशंकित हैं। उन्हें लग रहा है कि पता नहीं कितने कर्मचारी कब तक वापस आएंगे, क्योंकि जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक उनका लौटना मुश्किल है। एक और डर है कि लॉकडाउन के चलते जो मजदूर फंसे हैं, वे भी साधन मिलते ही चले जाएंगे। कुछ कंपनियों ने बेशक अपने कर्मचारियों को रखा हुआ है, लेकिन ऐसी कंपनियों की संख्या कम ही है। कच्चे माल और तैयार माल बेचने की सप्लाई चेन भी टूट गई है। उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि हालात समान्य होने में चार से छह महीने लग सकते हैं। ऐसे में, बहुत सी कंपनियों के सामने सर्वाइवल का संकट आ सकता है।

सरकार ने जो नए दिशानिर्देश जारी किए हैं, उनके मुताबिक मजदूर 3 मई तक एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकेंगे। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, हॉटस्पॉट को छोड़कर बाकी जगहों पर 20 अप्रैल से औद्योगिक टाउनशिप, ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयां, दवा और चिकित्सा उपकरण की इकाइयां, एसईजेड और निर्यातोन्मुखी इकाइयां खुल सकेंगी। लेकिन इनमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के पालन के साथ कंपनी को कर्मचारियों के रहने का बंदोबस्त भी करना पड़ेगा और उनके आने-जाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। उन्हें कर्मचारियों का बीमा भी करवाना पड़ेगा। हाइवे पर चलने वाले ढाबे और ट्रक रिपेयर की दुकानें, इलेक्ट्रिशियन, आइटी रिपेयर, प्लंबर, मोटर मेकैनिक, कारपेंटर की दुकानें भी खुल सकेंगी।

एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन और एमएसएमई चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट रजनीश गोयनका ने *आउटलुक* से कहा, "फैक्ट्रियों में काम करने वाले ज्यादा मजदूरों ने पलायन नहीं किया है। बात उन्हें फैक्ट्री लाने-ले जाने की है, तो कंपनियां इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि इस पर आने वाले खर्च की तुलना में फैक्ट्री बंद रखने पर

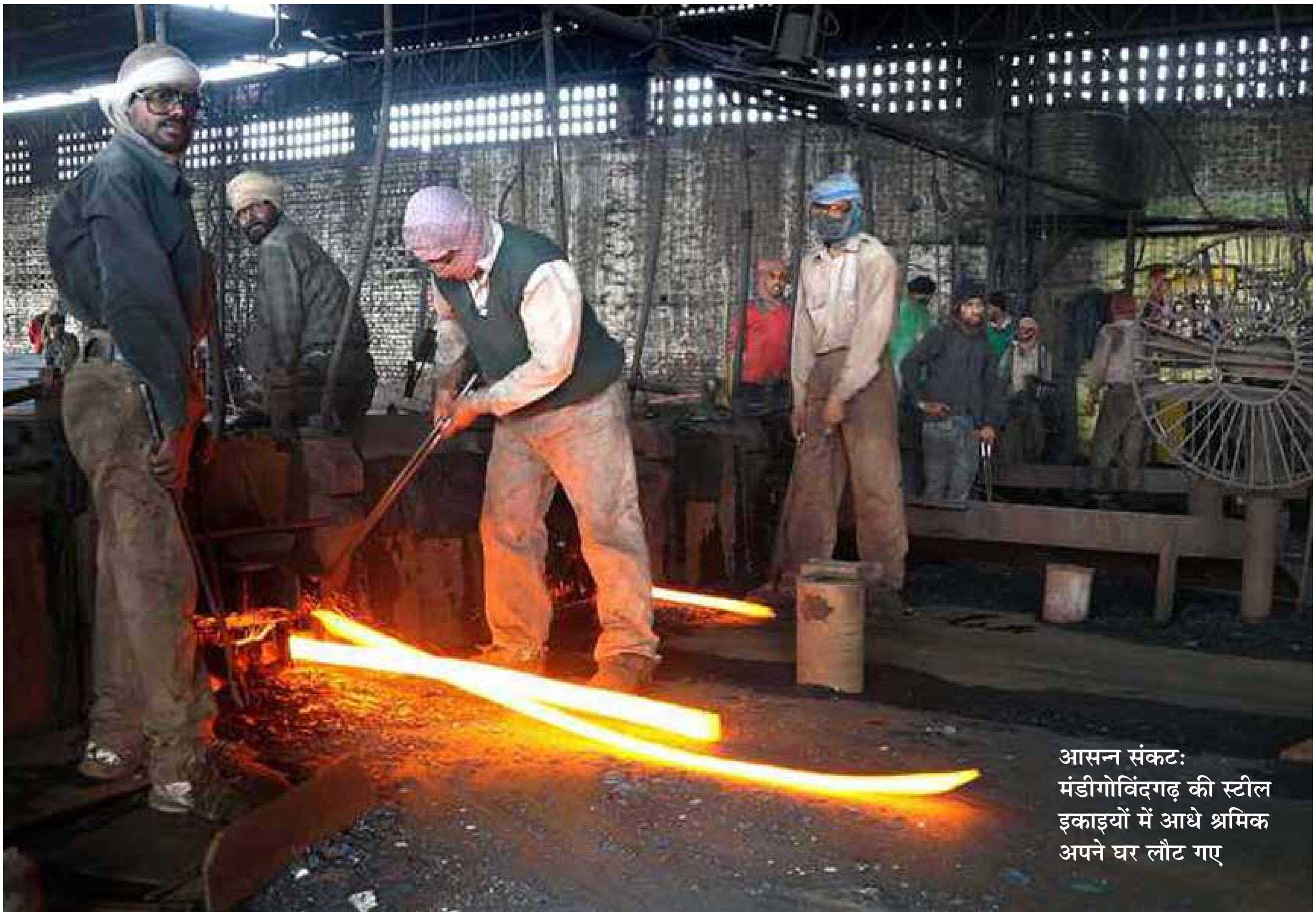

आसन्न संकट: मंडीगोविंदगढ़ की स्टील इकाइयों में आधे श्रमिक अपने घर लौट गए

पैकिंग की दिक्कतः बद्दी में दवा उत्पादन की तो अनुमति, लेकिन पैकेजिंग मेटीरियल की कमी

नुकसान ज्यादा होगा।" कैट के राष्ट्रीय सचिव और सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रेसिडेंट सुरेश सोंथालिया ने भी कहा कि आस-पास के मजदूर तो खुद आ जाते हैं, दूर रहने वालों के लिए बस का इंतजाम करने को सभी इकाइयां तैयार हैं।

चंडीगढ़, पंजाब के लुधियाना, जालंधर, मंडीगोबिंदगढ़, खन्ना, हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर और हिमाचल प्रदेश के बद्दी-बरोटीवाला और कालाअंब के उद्योगों में काम करने वाले करीब 30 लाख श्रमिकों के साथ यहां की करीब डेढ़ लाख एसएमई संकट में हैं। मंडीगोबिंदगढ़ स्टील फर्नेस एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने बताया, "यहां काम करने वाले करीब 30,000 श्रमिकों में से आधे अपने मूल राज्य लौट गए हैं। लॉकडाउन के चलते तमाम इन्फ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ठप हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद भी स्थिति सामान्य होने में छह महीने का समय लग सकता है।"

हैंडलूम मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पानीपत के अध्यक्ष रमेश वर्मा ने कहा कि यहां के करीब 18,000 छोटे बड़े उद्योगों में काम करने वाले करीब 80 हजार दिहाड़ी मजदूरों में से 60 फीसदी काम बंद होने की वजह से अपने मूल राज्य जा चुके हैं। वर्मा ने आशंका जताई कि लॉकडाउन के बाद कई महीने तक उत्पादन सामान्य नहीं हो पाएगा। हिमाचल के बद्दी-बरोटीवाला और नालागढ़ फार्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संगठन सचिव मुकेश जैन ने कहा, "पैकेजिंग मेटीरियल गैर-जरूरी वस्तुओं की श्रेणी में है। इसकी किल्लत से दवाओं की पैकेजिंग में मुश्किल हो रही है। उत्पादन पहले की तुलना में घटकर 20 फीसदी रह गया है। कर्फ्यू में गैर-जरूरी वस्तुओं की आवाजाही के लिए डीएम की मंजूरी लेना ट्रांसपोर्टर्स और उद्यमियों के लिए बड़ी सिरदर्दी है।"

उम्मीद है सरकार एमएसएमई के लिए 75,000 करोड़ रुपये का पैकेज जारी करेगी। इन्हें जल्दी मदद नहीं मिली तो छह महीने में 50 फीसदी एमएसएमई खत्म हो जाएंगे

रजनीश गोयनका, प्रेसिडेंट
एमएसएमई चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्रीज

जहां प्रशासन की तरफ से मंजूरी है, वहां भी श्रमिकों की कमी के कारण उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ऑल इंडिया सॉलवेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और राइसिला ग्रुप के चेयरमैन ए.आर. शर्मा ने बताया कि सरकार ने राइस ब्रान ऑयल के उत्पादन के लिए लिखा, पर श्रमिकों के काम पर न लौटने से काम ही शुरू नहीं हो सका। ऑल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और किट्टी फूड्स लिमिटेड के सीएमडी रमेश मागो ने कहा कि ब्रेड उत्पादन और वितरण में 40 फीसदी कमी आई है। ब्रांडेड कंपनियों के लिए आटा तैयार करने वाले पंचकूला स्थित कुमार फ्लोर मिल्स के सीएमडी विनोद मित्तल के मुताबिक, पैकेजिंग की किल्लत के चलते ब्रांडेड कंपनियों को आपूर्ति 80 फीसद घट गई है।

गोयनका के अनुसार, ज्यादातर इकाइयों में 40-50 फीसदी श्रमिक ही प्रवासी हैं। इसलिए उत्पादन शुरू करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। लुधियाना, मंडीगोबिंदगढ़ और जालंधर में तो पांच-छह दशक से उद्योग-धंधे हैं। इसलिए 60 फीसदी से अधिक श्रमिक तीसरी-चौथी पीढ़ी के हैं, जो यहां के स्थायी निवासी हो गए हैं। लुधियाना के श्रमिक बहुल इलाके आत्मनगर विधानसभा क्षेत्र से लोक इंसाफ पार्टी के विधायक और उद्यमी सिमरजीत सिंह बैंस ने बताया कि दिहाड़ीदार श्रमिकों को छोड़ दें तो 60 फीसदी से अधिक श्रमिक तीन-चार दशकों से यहीं रह रहे हैं।

मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के सामने श्रमिकों की किल्लत के अलावा कच्चे माल की उपलब्धता और तैयार माल की सप्लाई की भी समस्याएं हैं। गोयनका मानते हैं कि इनके सामान्य होने में तीन से चार महीने लग जाएंगे। समस्या मांग की भी आएगी। होशियारपुर के सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स ग्रुप के वाइस चेयरमैन ए.एस. मित्तल ने बताया कि उनके प्लांट में कार्यरत 8,000 श्रमिकों और 350 एंसिलरीज में काम करने वाले करीब 20,000 श्रमिकों में से 80 फीसदी स्थानीय हैं। इसलिए संकट श्रमिकों का नहीं, बल्कि कृषि उपकरणों की मांग को कायम रखने का है। एवन साइकिल के सीएमडी ओंकार पाहवा भी मानते हैं कि लुधियाना के साइकिल उद्योग में लॉकडाउन खुलने के बाद समस्या बिक्री की रहेगी।

बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां निर्यात पर निर्भर हैं। इनमें उत्पादन शुरू हो भी गया तो सामान भेजने की दिक्कत है। जालंधर स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरर्स ऐंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रघुनाथ राणा के मुताबिक, उत्पादन ठप होने से जालंधर के खेल उद्योग का सालाना 800 करोड़ रुपये का निर्यात कारोबार ठप हो गया है। 70 फीसदी निर्यात यूरोप और अमेरिका को होना था, जहां महामारी के चलते खेल गतिविधियां ठप हैं। टोक्यो ओलंपिक और भारत में आइपीएल समेत तमाम खेलों का आयोजन टलने से यहां के उद्योगों के करीब 150 करोड़ रुपये के ऑर्डर रद्द हुए हैं।

उद्योग जो सामान बनाते हैं, उनकी आपूर्ति दूसरे राज्यों में भी होती है जो लॉकडाउन में संभव नहीं लगती। इंडियन इंडस्ट्री एसोसिशन की एमएसएमई स्टडी ऐंड रिसर्च कमेटी के अध्यक्ष रजत मेहरा कहते हैं, "हमें अपना काम करने के लिए कच्चा माल से लेकर पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन तक की जरूरतों को देखना है। अभी ट्रांसपोर्टेशन लगभग शून्य है।

पीटीआइ

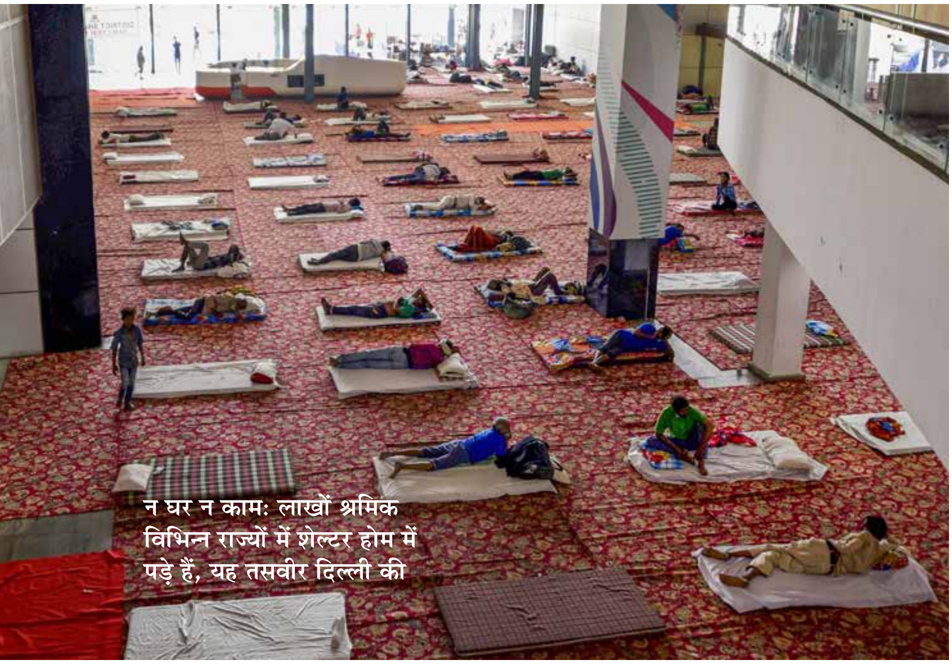

न घर न कामः लाखों श्रमिक विभिन्न राज्यों में शेल्टर होम में पड़े हैं, यह तसवीर दिल्ली की

हमारे और हमारी एंसिलरी इकाइयों के कुल 20 हजार श्रमिकों में से 80 फीसदी स्थानीय, इसलिए संकट श्रमिकों का नहीं, बल्कि कृषि उपकरणों की मांग को कायम रखने का

ए.एस. मित्तल

वाइस चेयरमैन, सोनालिका इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स

जरूरी सामान से जुड़े उद्योग में उत्पादन के लिए जरूरी है कि उनके सामने कच्चे माल की समस्या न आए। इसके लिए ट्रांसपोर्ट की दिक्कतों को खत्म करना जरूरी

सचिन अग्रवाल

पूर्व अध्यक्ष, सीआइआइ, लखनऊ

एक ही प्रदेश में आवागमन आसान नहीं है। दूसरे प्रदेश से आने वाले सामान के बारे में तो अभी सोच भी नहीं सकते।" सोंथालिया भी कहते हैं कि जब तक आवागमन पूरी तरह शुरू नहीं होता, तब तक हम उत्पादन करके भी क्या करेंगे। मेहरा के अनुसार, लॉकडाउन से पहले ही जरूरी उद्योगों के बारे में सोच लिया जाता तो समस्या इतनी बड़ी नहीं होती। सीआइआइ, लखनऊ के पूर्व अध्यक्ष सचिन अग्रवाल कहते हैं, "जरूरी सामान से जुड़े उद्योगों में उत्पादन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उनके सामने कच्चे माल की समस्या न आए। कच्चा माल लाने से लेकर तैयार माल वेंडर तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट की दिक्कतों को समाप्त किए बगैर हालात नहीं सुधर सकते।"

फैक्टरी मालिकों की एक और शिकायत है कि वेतन नहीं रोकने के सरकारी निर्देश से कर्मचारियों में गलत मैसेज गया है। बहुत से कर्मचारी फैक्ट्री आकर भी काम करना जरूरी नहीं समझ रहे। इस स्थिति को समझने के लिए कानपुर अपर श्रम आयुक्त कानपुर का आदेश काफी है। उन्होंने सरकारी अधिसूचना का हवाला देते हुए 5 अप्रैल को सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया कि कोविड-19 महामारी के चलते अस्थायी रूप से बंदी के दौरान सभी नियोक्ताओं को अपने मजदूरों को मजदूरी सहित अवकाश दिया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी।

एक तरफ उद्योगों के सामने काम शुरू करने को लेकर व्यवस्थागत दिक्कतें हैं, तो दूसरी ओर विभागीय तालमेल का अभाव और प्रशासनिक अड़चनें उनकी मुश्किलें और बढ़ा रही हैं। साहिबाबाद-गाजियाबाद क्षेत्र के उद्यमियों में गाजियाबाद के उद्योग उपायुक्त वीरेंद्र कुमार का कथित ऑडियो मैसेज खौफ का कारण बन गया। इस ऑडियो में कुछ उद्यमों को कहा गया कि उन्हें अगले दिन से काम शुरू कर देना है। संबंधित मजिस्ट्रेट उनके काम शुरू करने की सत्यता की जांच करेंगे। ऐसा नहीं करने वाले उद्योगों का लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है। एक उद्योगपति ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, इस आपातकालीन परिस्थिति में उद्योगों के साथ संवेदनशील व्यवहार की जरूरत थी। लेकिन अफसरों ने बेहद रुखाई और सख्ती से काम लिया। सुविधाएं मुहैया कराने के बजाय कानून के नाम पर मुश्किलें पैदा की जा रही हैं।

इन हालात में उद्यमी सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि लॉकडाउन के तीन हफ्ते बीत जाने के बावजूद अभी तक उद्योग जगत के लिए किसी पैकेज की घोषणा नहीं की गई है। गोयनका ने कहा, "लॉकडाउन खत्म होने के बाद लिक्विडिटी की बड़ी समस्या आने वाली है। उम्मीद है कि सरकार जल्दी ही एमएसएमई के लिए 75,000 करोड़ रुपये का पैकेज जारी करेगी। अगर इन्हें मदद नहीं मिली तो छह महीने में 50 फीसदी एमएसएमई खत्म हो जाएंगे।" सोंथालिया के मुताबिक सरकार को छोटे कारोबारियों के लिए पैकेज लाना चाहिए, कर्ज पर ब्याज फिलहाल माफ कर देना चाहिए, आगे भी एक साल के लिए ब्याज की दर आधी रखी जानी चाहिए।

हालांकि, मौजूदा परिस्थितियों में भी कुछ लोगों को अवसर नजर आ रहा है। गोयनका ने बताया कि बहुत से निर्माता चीन से निकलना चाहते हैं। भारत के ही कुछ निर्माता जो पहले चीन में मैन्युफैक्चरिंग करवा कर सामान मंगवाते थे, अब वे यहां बनवाने के लिए हमसे संपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर पांच फीसदी ज्यादा कीमत भी देनी पड़े तो वे भारत में सामान बनवाना पसंद करेंगे। निर्यातकों के संगठन फिओ के अध्यक्ष एस. सराफ ने भी सरकार से कहा है कि यह विदेशी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत आकर्षित करने का बढ़िया मौका है।

प्रशांत श्रीवास्तव

अजीब स्थिति है, एक बड़े निजी बैंक में नौकरी मिलने के बाद भी ऐसा होगा, सोचा नहीं था।" उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले यतीश श्रीवास्तव यह कहते हुए काफी परेशान दिखते हैं। वह कहते हैं, अलीगढ़ में बैंक ज्वाइन करना है लेकिन लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में फंस गया हूं। अब तो यह डर है कि कहीं ज्वाइनिंग में कोई बखेड़ा न हो जाए? सैलरी कैसे मिलेगी? लोग कह रहे हैं, कटौती भी हो सकती है। कुछ पता नहीं है, यह सब डर मुझे सताए जा रहा है। लॉकडाउन में यतीश जैसी स्थिति इस समय करोड़ों लोगों की है। कर्मचारी से लेकर कंपनियों के सीईओ तक बढ़ते संकट से परेशान हैं। उद्योग जगत के संगठन सीआइआइ (कॉन्फिडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) के सर्वे के अनुसार देश के 52 फीसदी सीईओ का मानना है कि लॉकडाउन के बाद 15-30 फीसदी नौकरियों में कटौती हो सकती है। हालात इतने खराब हो गए हैं, नौकरियों की स्थिति पर सर्वे करने वाली कंपनी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऐंड इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के अनुसार, "लॉकडाउन के 15 दिनों में बेरोजगारी दर 7-8 फीसदी से बढ़कर 23 फीसदी पर पहुंच गई है।" सीधा सा मतलब है कि इसके जरिए करीब 11-12 करोड़ लोगों की नौकरियों पर संकट एक झटके में आ गया है। ऐसी ही डरावनी स्थिति अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) की रिपोर्ट बयां करती है। उसके अनुसार, लॉकडाउन की वजह से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली करीब 40 करोड़ आबादी गरीबी के कुचक्र में फंस सकती है।

असल में सीएमआइई की रिपोर्ट लॉकडाउन में बेरोजगारी की भयावह स्थिति बताती है। सीएमआइई के सीईओ महेश व्यास का कहना है, "24 फरवरी

कोविड-19 की वजह से बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने का खतरा, सरकार को त्वरित कदम उठाने की जरूरत

12 करोड़ लोगों के रोजगार पर सीधी मार

पीटीआइ

प्रवासियों में फैला डरः उद्योग जगत की चिंता काम पर आसानी से नहीं लौटेंगे श्रमिक

त्रिभुवन तिवारी

बड़ी मार

- लॉकडाउन के 15 दिनों में बेरोजगारी दर 8 फीसदी से बढ़कर 23 फीसदी पहुंची
- 12 करोड़ लोगों पर एक झटके में रोजगार का संकट
- 40 करोड़ लोग गरीबी के कुचक्र में फंस सकते हैं
- बाजार में श्रमिक बल की संख्या में 6 फीसदी की गिरावट
- शहरी इलाकों में 31 फीसदी पहुंची बेरोजगारी दर, ग्रामीण इलाकों में 20 फीसदी के स्तर पर
- निर्यात क्षेत्र में 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियों पर संकट
- कई सेक्टर में 10-30 फीसदी तक वेतन में कटौती की आशंका

सब तरफ सन्नाटा: लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ा गाजियाबाद का एक शॉपिंग मॉल

की आधी रात से लॉकडाउन के ऐलान के बाद केवल 15 दिनों में बेरोजगारी दर में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। यह आठ फीसदी से बढ़कर 23 फीसदी के स्तर पर आ गई है। चिंता की बात यह है कि इस दौरान श्रमिक भागीदारी रेट 42-43 फीसदी के स्तर से गिरकर 36 फीसदी पर आ गई है। यानी 6-7 फीसदी लोगों ने रोजगार का मैदान ही छोड़ दिया है। यह बहुत बुरी स्थिति है।"

सीएमआइई सर्वे का विश्लेषण करते हुए स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव कहते हैं, "आंकड़े बहुत भयावह स्थिति पेश कर रहे हैं। श्रम भागीदारी दर 36 फीसदी और बेरोजगारी की दर 23 फीसदी पर पहुंच गई है। इसका सीधा मतलब है 11.9 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसमें अगर लॉकडाउन से पहले के 3.4 करोड़ बेरोजगार लोगों को शामिल कर लिया जाए, तो इस समय देश में 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। एक बात और समझनी होगी कि देश में 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कृषि क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में काम कर जीविका चला रहे हैं। इसके अलावा छह करोड़ लोग स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं, जबकि 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वेतनभोगी हैं, लेकिन उनकी नौकरी स्थायी नहीं है। लॉकडाउन से इन्हीं 19.5 करोड़ लोगों पर असर पड़ा है। सरकार को इनके लिए जल्द कदम उठाने होंगे, नहीं तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। श्रम भागीदारी दर घटने और बेरोजगारी दर बढ़ने से दोहरी मार पड़ी है। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक झटके में 12 करोड़ लोगों पर रोजगार का संकट आ गया है, यह एक ऐतिहासिक दुर्घटना है।"

जैसी चिंता योगेंद्र यादव कर रहे हैं, कुछ उसी तरह की आशंकाएं उद्योग जगत से जुड़े लोगों की भी हैं। चाहे ऑटो कंपनियां हों या फिर 4-5 करोड़ लोगों को नौकरियां देने वाले रिटेलर हों, सभी गहराते संकट से परेशान हैं। रिटेलर्स एसोसिएशन इंडिया द्वारा कोविड-19 के असर पर किए गए सर्वे के अनुसार, रिटेल क्षेत्र में 20 फीसदी नौकरियों पर संकट है। उसके अनुसार छोटे रिटेलर 30 फीसदी, मझोले रिटेलर 12 फीसदी और बड़े रिटेलर पांच फीसदी तक नौकरियों में कटौती कर सकते हैं।

सर्वे एक और गंभीर स्थिति बताता है, उसके अनुसार करीब 95 फीसदी रिटेल शॉप जो गैर खाद्य पदार्थों का कारोबार करते हैं, उनकी कमाई अगले छह महीने में 60 फीसदी तक गिर सकती है। यानी पिछले साल के मुकाबले वह केवल 40 फीसदी ही कमाई कर सकेंगे। इसी तरह खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले रिटेलर की कमाई भी 44 फीसदी तक घटने का अनुमान है। कमाई घटने का सीधा असर नौकरियों पर दिखने की आशंका है।

ऐसी ही आशंका ऑटोमोबाइल डीलर्स भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से शोरूम बंद है। गाड़ियों की बिक्री ठप हो गई है। इसे देखते हुए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस संबंध में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राहत पैकेज की मांग की है। फाडा के अनुसार, पिछले 15 महीने से ऑटो इंडस्ट्री पर संकट छाया हुआ है, इसकी वजह से 275 डीलरशिप बंद हो गई हैं। ऐसे में अगर राहत पैकेज नहीं मिला तो बड़े पैमाने पर नौकरियां खत्म हो सकती हैं।

लॉकडाउन ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को भी पूरी तरह से ठप कर दिया है। इस कारण निर्यात पूरी तरह से बंद है। इसका असर टेक्सटाइल, चमड़ा उद्योग, जेम्स ऐंड ज्वेलरी, अपैरल हैंडीक्रॉफ्ट सहित रोजगार देने वाले प्रमुख सेक्टर में 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां खत्म हो सकती हैं। निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फिओ) के सीईओ एस.के. श्रॉफ का कहना है कि कोविड-19 की वजह से 50-75 फीसदी निर्यात के ऑर्डर निरस्त हो गए हैं। बढ़ते संकट को देखते हुए फिओ ने प्रधानमंत्री

दुनिया में आज तक कहीं भी एक झटके में 12 करोड़ लोगों की नौकरियों पर संकट नहीं आया है। यह एक ऐतिहासिक दुर्घटना है

नरेंद्र मोदी को राहत पैकेज देने के लिए पत्र भी लिख दिया है। उसके अनुसार, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह अभी तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट है। इसे देखते हुए अमेरिका, यूके, जापान यहां तक कि बांग्लादेश ने भी निर्यातकों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। ऐसे में, हमें अभी तक के ऐलान के अलावा दूसरे कदमों की जरूरत है। तभी जाकर निर्यातक संभल पाएंगे।

यह संकट केवल मौजूदा नौकरियों पर ही नहीं है, बल्कि उन युवाओं पर भी है, जिन्हें इस साल पहली नौकरी मिलने वाली है। यानी कैंपस सेलेक्शन के बाद वह नौकरी ज्वाइन करने का इंतजार कर रहे हैं। लखनऊ के शेरवुड कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट हेड डॉ. मीनाक्षी जायसवाल का कहना है, "अभी बहुत अस्पष्टता है। तीन-चार कंपनिया प्लेसमेंट के लिए कॉलेज आ चुकी हैं, उन्होंने सेलेक्शन भी कर लिया है लेकिन दूसरी कंपनियां जो आने वाली थीं, उनको लेकर अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। सबकुछ लॉकडाउन के बाद ही पता चलेगा। इस वजह से छात्र-छात्राओं में भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।"

सब कुछ ठप: लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी एक फैक्ट्री

भविष्य को लेकर जारी अनिश्चितता का असर यह हुआ है कि अब लोग अवसाद में भी जा रहे हैं। मेडिटेशन एक्सपर्ट और कॉरपोरेट ट्रेनर लक्ष्मी नारायण कहते हैं, "लोगों के बीच अवसाद बढ़ रहा है। ज्यादातर लोग आर्थिक परेशानियों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि नौकरी उनकी बचेगी या नहीं, सैलरी कम हो गई तो खर्च कैसे चलेगा। ऐसे सैकड़ों सवाल उनके मन में घर कर गए हैं। इस वजह से फिलहाल मैं सोशल मीडिया और व्यक्तिगत स्तर पर सहयोग देने की कोशिश कर रहा हूं। यह ऐसा संकट है जिसका सामना अभी तक इस पीढ़ी ने नहीं किया था। यह पूरी तरह से अलग है, ऐसे दौर में व्यक्तिगत स्तर से लेकर कॉरपोरेट स्तर पर लोग मदद ले रहे हैं।"

सरकार के पास असंगठित क्षेत्र को सीधे राहत देने का साधन नहीं है

प्रणब सेन
पूर्व चीफ स्टैटेशियन
भारत सरकार

गहराते संकट पर भारत सरकार के पूर्व चीफ स्टैटेशियन प्रणब सेन का कहना है, "लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद है तो जाहिर है कि नौकरियों का संकट रहेगा। चिंता दूसरी है, जब लॉकडाउन खत्म होगा, तब इस संकट से उबरने का क्या प्लान है? उसके बाद कितनी जल्दी 23 फीसदी बेरोजगारी दर घटकर आठ फीसदी पर वापस आएगी। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 का खतरा काफी बड़ा है। सरकार को सबसे ज्यादा चिंता असंगठित क्षेत्र की करनी पड़ेगी। उसके सामने भूख और रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। उन्हें किस तरह इन परिस्थितियों में राहत दी जाए, वह सरकार का एजेंडा होना चाहिए। चिंता की बात यह है कि सरकार के पास असंगठित क्षेत्र के लोगों को सीधे तौर पर राहत पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में, कोशिश यह होनी चाहिए कि चीजें जल्द से जल्द वापस पटरी पर लौटें। इस बीच लॉकडाउन में कृषि क्षेत्र को सहयोग देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि वह कायम रहेगा तो धीरे-धीरे संगठित क्षेत्र पटरी पर लौट आएगा। लेकिन सरकार के ऐलान के बाद भी शिकायतें मिल रही हैं। क्योंकि पूरी सप्लाई चेन रुक गई है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी 90 फीसदी ट्रक खड़े हुए हैं। सरकार को ऐसे एक्शन करने होंगे जिससे जमीन पर कृषि क्षेत्र को बरकार रखा जा सके। रबी की फसलों की खरीद और भंडारण की व्यवस्था सुचारु रूप से हो जाए। अगर ऐसा कर पाए तो बहुत कुछ संभाला जा सकता है।

प्रणब सेन की तरह योगेंद्र यादव का भी कहना है कि सरकार को एक बड़ा पैकेज बनाना होगा, जिसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले उसे मनरेगा के तहत लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर करना चाहिए। इसके अलावा देश के हर नागरिक को 100 दिन के रोजगार की गारंटी का आश्वासन देना चाहिए। जो भी रोजगार मांगे, उसे हर हाल में 100 दिन का रोजगार मिले। तभी असंगठित क्षेत्र को संभाला जा सकता है।

साफ है कि कोविड-19 का संकट बहुत बड़ा है। ऐसी स्थिति का अनुभव इस पीढ़ी ने कभी नहीं किया है। दुनिया भर के लिए यह बड़ी चुनौती है। जहां सरकारों को लोगों की जान भी बचानी है, वहीं उन्हें भुखमरी से भी बचाना है। क्योंकि यह संकट अमीर-गरीब का नहीं रह गया है। इसकी वजह से हर तबका प्रभावित हो रहा है। ऐसे में, सबकी आस अब सरकार पर ही टिकी हुई है। लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने के ऐलान के वक्त कहा कि मुझे सबसे ज्यादा चिंता उस तबके की है, जो रोज कमाता और खाता है। विशेषज्ञ भी यही बात दोहरा रहे हैं कि कैसे उस वर्ग को भुखमरी से बचाया जाए। साथ में मिडिल क्लास और उच्च वर्ग को भी संभालना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक तीनों पटरी पर नहीं आएंगे, स्थिति सामान्य नहीं होने वाली है।

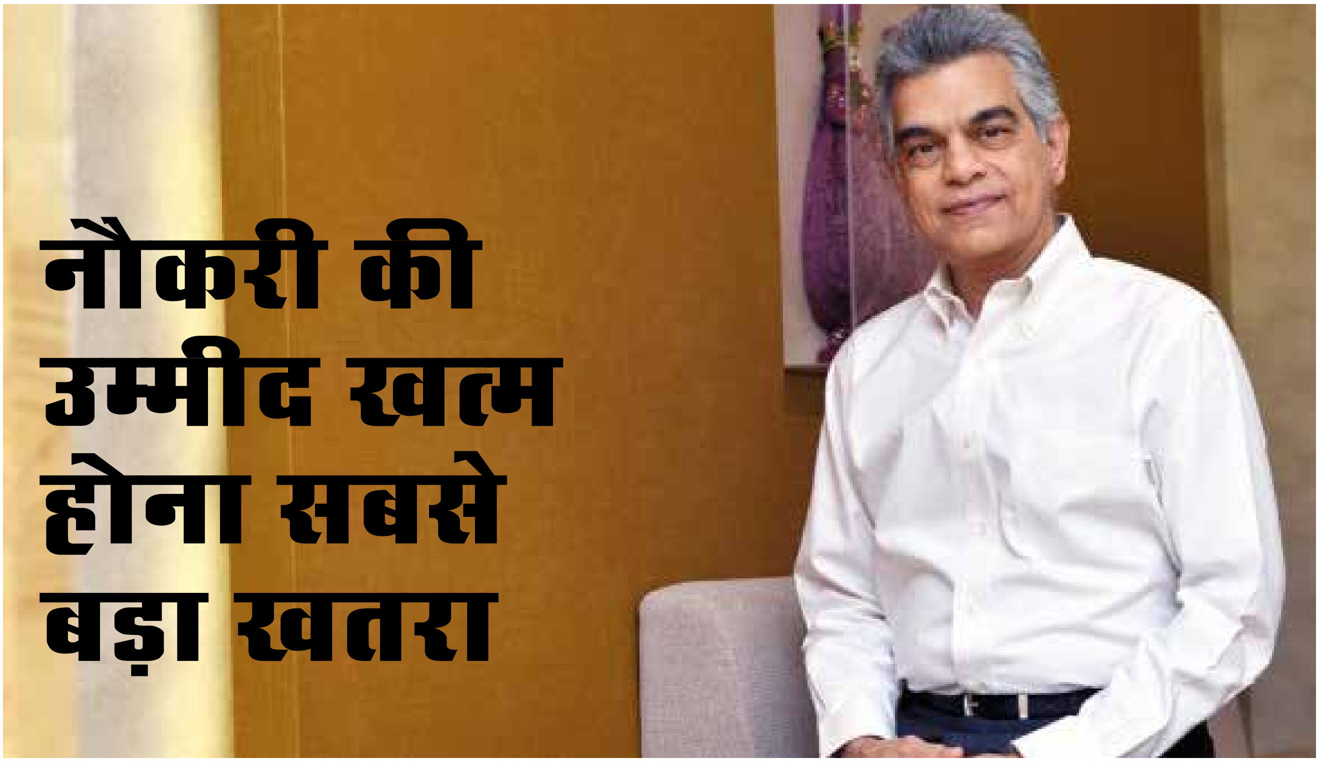

नौकरी की उम्मीद खत्म होना सबसे बड़ा खतरा

लॉकडाउन लागू होने के बाद से देश में आर्थिक गतिविधियां ठप सी हो गई हैं। ऐसे में, बड़ी संख्या में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है। इसी के मद्देनजर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) ने लॉकडाउन की अवधि में एक सर्वे किया है। पांच अप्रैल तक किए गए सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जो गंभीर होती स्थिति को बताते हैं। सर्वे के क्या मायने हैं, इस पर आउटलुक के ***प्रशांत श्रीवास्तव*** *ने सीएमआइई के सीईओ* ***महेश व्यास*** *से विस्तार से बात की। पेश हैं प्रमुख अंश:*

लॉकडाउन की वजह से जॉब मार्केट पर किस तरह का असर हुआ है?

हमने लॉकडाउन के पहले पंद्रह दिन के सर्वे के दौरान तीन चीजों पर असर देखा है। श्रमिक भागीदारी दर (लेबर पार्टिसिपेशन रेट) 42 फीसदी से भी नीचे आ गई है। वह गिरकर 36 फीसदी के स्तर पर आ गई है। वहीं, बेरोजगारी दर में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। वह 23 फीसदी के स्तर पर पहुंच गई है और रोजगार के अवसर कम हो गए हैं।

यह आंकड़े किस ओर इशारा कर रहे हैं?

देखिए, श्रमिक भागीदारी दर जो 42-43 फीसदी के स्तर पर चल रही थी, वह मार्च के आखिरी हफ्ते में गिरकर 39.2 फीसदी और अप्रैल के पहले हफ्ते में 36 फीसदी पर आ गई है। इसका मतलब है कि नौकरी की मांग करने वालों की संख्या में 6-7 फीसदी की गिरावट है। यह बहुत चिंता की बात है। क्योंकि श्रमिक भागीदारी दर में गिरावट का मतलब है कि लोगों में नौकरी मिलने की उम्मीद कम होती जा रही है।

बेरोजगारी दर 23 फीसदी पर पहुंचना कितनी चिंताजनक बात है?

नौकरी की मांग करने वालों में जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, वह बेरोजगारी दर कहलाती है। लॉकडाउन के पहले 43 फीसदी श्रमिक भागीदारी रेट में 6-7 फीसदी को रोजगार नहीं मिलता था। अब लॉकडाउन के दौरान गिर कर 36 फीसदी पर आ चुकी श्रमिक भागीदारी रेट में 23 फीसदी को रोजगार नहीं मिल रहा है। साफ है कि बड़े पैमाने पर लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं।

श्रमिक भागीदारी रेट और बेरोजगारी दर शहरी और ग्रामीण इलाकों में क्या अलग-अलग है?

सामान्य तौर पर शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर ज्यादा होती है, वह हमारे सर्वे में भी दिखता है। लेकिन जिस तरह से शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर बढ़ी है, वह बुरी स्थिति को बताती है। शहरी इलाकों में श्रमिक भागीदारी दर 40-41 फीसदी से गिरकर 32 फीसदी पर आ गई है। जबकि बेरोजगारी दर 31 फीसदी पर पहुंच गई है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों में श्रमिक भागीदारी में भारी गिरावट है और बेरोजगारी दर 6 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी पर पहुंच गई है।

लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ाया गया है, इससे संकट कैसे बढ़ सकता है?

लॉकडाउन का ऐलान अचानक किया गया। इसकी वजह से बड़ी संख्या में श्रमिक पिछले तीन हफ्ते से फंस गए हैं। देश में एक बड़ी आबादी है, तो मेट्रो शहरों में 150-200 किलोमीटर से आकर नौकरी करती है। ऐसे लोग हर हफ्ते घर चले जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। अब लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ गया है। इसकी वजह से वह कम से कम पांच हफ्ते तक अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। यह उनके लिए बड़ा ट्रॉमा है। साथ ही, कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को पैसों की भी दिक्कत बढ़ रही है। क्योंकि उनकी बचत खत्म हो रही है। ऐसे में स्थिति और खराब होगी।

लॉकडाउन के बाद इंडस्ट्री को श्रमिकों की उपलब्धता का डर सता रहा है?

जैसा कि मैंने पहले कहा कि अचानक हुआ लॉकडाउन, श्रमिकों के लिए बड़े आघात से कम नहीं है। सर्वे के दौरान हमने जिन लोगों से बात की है, उनकी पहली इच्छा यही है कि जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा, वह अपने घर जाएंगे। वह अभी नौकरी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। इस माहौल में आने वाली स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। इंडस्ट्री के लिए श्रमिकों को वापस लाना आसान नहीं होगा। खास तौर से शार्ट टर्म काफी दिक्कतें आएंगी।

2020 का महा सदमा

अजय सुकुमारन

वह दिमाग में जैसे लगातार भनभना रहा है, जैसे दूर से आती रेडियो की कोई धीमी आवाज हो या मच्छर की भनभनाहट। यह महामारी की गूंज है, जिसे किसी एकाकीपन की दुश्चिंता या हल्का-फुल्का सिरदर्द जानकर भुलाया नहीं जा सकता। वह दफ्तर की कॉन-कॉल और दोस्तों के साथ वीडियो चैटिंग के वक्त भी दिमाग के किसी कोने में हावी रहती है। उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल है। नितांत जरूरी सामान खरीदने बाहर निकलिए, तब भी जैसे साए की तरह मौजूद रहती है। आखिर सिर झटककर कुछ खाना बनाने उठिए तो पल भर में आपका सोशल मीडिया चैट-लॉग भर उठता है। लोग बात करने को ऐसे पगलाए-से हैं कि पल भर का इंतजार मंजूर नहीं। ऐसा तो कभी नहीं था। अमूमन बातचीत के कोई खास मायने भी नहीं, सही या गलत खबर सब एक भाव, सबमें सिर्फ भविष्य को लेकर घबराहटें ही घबराहटें। हम जो करते हैं, जैसे अचानक सबमें हल्की-सी सनक सवार हो गई है....न चाहते हुए भी यह सवाल बार-बार दिमाग में घूम जाता है, हम ठीक तो हैं?

लेकिन दुनिया में आखिर ठीक क्या है? मौत, महामारी और अचानक आन पड़ी विपदा के दौर में लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे! भगवान हमें बचाओ। फिर जरा दुनिया और...अदृश्य तकदीर का खेल तो देखिए! या कहिए कुदरत का खेल। हमने अपनी जिंदगी सुरक्षित करने के लिए जो कुछ उपाय किए थे, हमारी बीमा पॉलिसी, डाइट प्लान, गेटेड सोसायटी, दवाइयां सभी की जैसे वह खिल्ली उड़ा रहा है। तो, कोरोना नामक दैत्य ने घेरा डाल लिया है, सिर्फ वह वायरस ही नहीं, बल्कि उसके साथ दबे पांव चला आया दिमागी खौफ का साया भी। हम सब पर वह कुछ कमोवेश के साथ छाया हुआ है, खत्म हो जाने की दुश्चिंता, उम्र की घबराहट। यह जैसे दुनिया की मानसिक सेहत की अग्निपरीक्षा है, जो हमारी पीढ़ियों के दौर में ऐसा सामूहिक तनाव कभी नहीं दिखा है। भारतीय मनोचिकित्सक सोसायटी के अध्यक्ष पी.के. दलाल कहते हैं, "हर कोई किसी न किसी तरह चिंतित है। हमने इससे पहले कभी ऐसी महामारी नहीं देखी है। दुनिया ने पिछली महामारी 1918 में देखी थी।"

फिर भी हमें उससे लड़ना है, बुरी खबरों के इस महाप्रलय में हम अकेले हैं। हम ब्रेकफास्ट और डिनर में तन्हा होते हैं, सामान्य समाज जैसे बैठ-सा गया है। गोया, मनहूस-सी गल्प कथा चल रही है? जी, नहीं, यह कड़वी हकीकत है। सो, आश्चर्य नहीं कि मानसिक वेदना और उदासी बेहिसाब है, आत्महत्याओं की भी खबरें हैं और घरेलू हिंसा की घटनाओं में तेजी आई है। यही नहीं, व्यसन और उसे न लेने के दुष्प्रभाव की खबरें भी हैं। तो, क्या भारतीय घरों से निकलने वाली ये अब तक की सबसे बुरी खबरें हैं? लॉकडाउन के महज दस दिनों में ही बाल उत्पीड़न से संबधित मामलों में मदद के लिए करीब एक लाख कॉल दर्ज की गईं। यह भी स्पष्ट कर लें कि मामला सिर्फ विज्ञान और वायरस का ही नहीं, न बाहर जाकर सब्जी खरीदने भर का है। भारत अब सामान्य नहीं है। शायद यह पूरी तरह सामान्य कभी नहीं था, लेकिन तनाव का हर पल अपने नए शिकार पैदा कर रहा है, जब हम यह बात कर रहे हैं तब भी।

हालात बहुत कुछ ऐसे हैं कि शहरों की भरीपूरी आबादी के समुद्र में कोई रॉबिनसन क्रूसो निपट अकेले नाव खे रहा है

इसे कोविड-19 युद्ध का मानसिक संताप कहिए, और यह किसी महामारी से कम नहीं है। यह हमारे सामूहिक विवेक को विशाल चुनौती की तरह है.....

या शायद हमारे दिमाग में पहले से मौजूद खाइयों के अलावा एक और खाई, क्योंकि हम सबके पहले से ही कई तरह के तनावों के अलावा यह एक नया भारी तनाव आ धमका। बेशक, कोई भी सामाजिक-आर्थिक (या मनोवैज्ञानिक) रूप से एकदम सुकून से नहीं है। चाहे वह थम चुकी खाद्य शृंखला के दोनों तरफ के किसान और मध्यवर्ग के रिटायर व्यक्ति हों, या सड़क नापने वाला डिलीवरी ब्वॉय, शीशों के मकानों में सूटधारी एक्जीक्यूटिव, अपने दायरे में दुबका नेता, साइबर जगत में खोए नाबालिग, या फिर अत्याधुनिक लैब में बैठा वायरोलॉजिस्ट। हम पूछ सकते हैं कि क्या साधु, गुरु और तमाम पंथों के स्वामी भी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं? इससे तो कोई भी वैक्सीन हमें छुटकारा नहीं दिला सकता, सिर्फ हमारा मानसिक संतुलन और हर स्थिति में समभाव रहने का धैर्य तथा लचीलापन ही इससे निजात दिला सकता है।

लेकिन इस महामारी को किस पैमाने पर माप सकते हैं, इसके प्रकोप का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं और इस पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? देश भर में शुरू की गईं हेल्पलाइनें बेहिसाब हैं। दलाल कहते हैं, "अधिकांश राज्यों के प्रमुख जिलों में हेल्पलाइन शुरू की गई हैं।" देश भर की हेल्पलाइनों में कार्यरत परामर्शदाता रोजाना कोविड-19 से संबंधित सवालों से जूझ रहे हैं। ये शिकायतें "सामान्य" या दुश्चिंता की आम उत्तेजनाएं हैं। लेकिन गहरी उत्तेजनाओं का क्या? जैसे, आत्महत्या की कुछ वारदातें? अमृतसर में एक बुजुर्ग पति-पत्नी एक पत्र छोड़ गए, जिससे पुलिस को उनके संक्रमित होने का अंदेशा हुआ। दिल्ली में टेस्ट के लिए प्रतीक्षा कर रहे एक मरीज ने अस्पताल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। सौभाग्यवश उसकी सिर्फ एक टांग टूटी। या फिर लगभग एक लाख बच्चों का मामला देखिए, उन्होंने कोई परेशानी होने पर ही हेल्पलाइन पर कॉल किया था। ये बच्चे अभी भी अपने उत्पीड़नकर्ताओं के साथ हो सकते हैं। यानी यह हकीकत है, वास्तविक है।

स्वास्थ्य कर्मचारी भी इस भय के माहौल से बच नहीं सकते हैं। उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। चीन के तमाम अस्पतालों में हाल में 1,257 स्वास्थ्यकर्मियों के बीच सर्वे किए गए। इससे पता चला कि बड़ी संख्या में कर्मी अवसाद, दुश्चिंता और तनाव से ग्रस्त हैं। भारतीय मनोचिकित्सक सोसायटी ने भी इस सप्ताह स्वास्थ्यकर्मियों के बीच ऑनलाइन सर्वे शुरू किया है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां दलाल काम करते हैं, में स्टाफ को कोविड-19 वार्ड में भेजने से पहले ट्रेनिंग सेशन में भेजा गया। दलाल ने कहा, "हम टीम को इससे निपटने के लिए 30 मिनट का कोर्स देते हैं क्योंकि वे सात दिनों तक वार्ड में ड्यूटी पर रहेंगे। इसके बाद उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में भेजा जाएगा।" इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस सप्ताह डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए टेली-काउंसिलिंग शुरू की है।

हम इससे किस तरह निपटते हैं? दलाल तथ्यों और दोहरे लक्ष्य की बात करते हैं। वे कहते हैं, कोरोना संबंधित समस्याओं में मुख्य तौर पर लोगों को परामर्श की आवश्यकता है। हम भी उन्हें बता रहे हैं कि सूचनाओं के दबाव में निराश होने की जरूरत नहीं है। फोर्टिस हेल्थकेयर, दिल्ली के मेंटल हेल्थ विभाग के डायरेक्टर समीर पारिख इसके पहलुओं पर बात करते हैं। पहली चिंता अधिकांश लोगों को होती है कि अगर मेरे या मेरे परिवार के साथ कुछ हो गया तो क्या होगा। इसके बाद जीवन जीने के बिलकुल नए तरीके के साथ तालमेल बिठाने की चुनौती होती है। तीसरी चिंता कोरोना संकट के बाद की स्थिति को लेकर है। जैसे, हालात सामान्य होने पर मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरी वित्तीय स्थिति कैसे रहेगी। इस तरह के सवाल आम हैं।

शायद ये आम सवाल हैं लेकिन स्थितियां असामान्य हैं। भूकंप और सुनामी जैसी आपदा के संभावित क्षेत्रों में रहने वाले कम से कम भाग्य के भरोसे बचने की उम्मीद कर सकते हैं लेकिन दुनिया में इस समय जो प्रकोप है, उसमें निराशा ही दिखाई देती है। स्थिरता के साथ सटीक अनुमान इस प्रकोप में बेमानी हो चुका है। यही वजह है कि मनोवैज्ञानिक कुशलता से ही सवालों के जवाब निकल सकते हैं, जबकि खतरे का एहसास सबको है। उन समागमों पर गौर कीजिए, बालकनी में खड़े होकर पादरी लोगों को संबोधित करता है। हम भी इसी तरह खड़े हैं या फिर डिजिटल वर्ल्ड में घिरे हैं। हम सभी अपने घरों पर सुरक्षित लेकिन अनिश्चित हैं। जैसे भरेपूरे शहरों के समुद्र में एक निर्जन द्वीप पर रॉबिनसन क्रूज की तरह अकेले ही तैर रहे हैं।

लेकिन हम एक-दूसरे को डिजिटल सिग्नल भेजते हैं। इस तरह से हम काफी हद तक संभलने में कामयाब हो जाते हैं। इससे अलग तरह की दुनिया

उभर रही है। सोचिए, टचस्क्रीन पर कैसे अंगुलियां घूम रही हैं। कई पर तो जैसे भावनाओं की बारिश होने लगती है। अनेक लोग फॉरवर्ड करने के मोह से बच नहीं पाते हैं क्योंकि यह भी नया धर्मकार्य जैसा हो गया है, मानो वर्चुअल स्ट्रीट में उम्मीद की लौ जगाकर निराशा दूर करना कोई पुण्य का काम हो। कई लोग चुटकुले साझा करने के अपने पुराने शगल से भी उदासीन हो गए हैं। अप्रैल फूल आया और निकल गया क्योंकि दुनिया चुटकुलेबाजी के मूड में नहीं थी। लेकिन यह न समझिए कि चुटकुलेबाजी का शगल शांत है। व्हाट्सएप और ट्विटर पर तो इसकी भरमार है जो तनाव के दौर में सेफ्टी वाल्व का काम कर रहे हैं और बोरियत दूर कर रहे हैं।

इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऐंड एलाइड साइंसेज, दिल्ली के डायरेक्टर डॉ. निमेष जी. देसाई कहते हैं, "आज के दौर का गोल्डन रूल है कि हर किसी को अनिश्चितता स्वीकार करनी होगी। दूसरा नियम है कि लॉकडाउन को हमें सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर मानना होगा। दरअसल, इससे हमें खुद के भीतर से निकलकर समाज के बारे में सोचने में मदद मिलती है।" मौजूदा हालात में लोगों की निराशा से उबरने के लिए अलग-अलग आवश्यकताएं हैं। कुछ लोग अकेले रहते हैं तो कुछ अपने घरों से दूर फंस गए हैं। सभी की स्थितियां अलग-अलग हैं। इसलिए सबके उबरने का तरीका अलग-अलग होगा। देसाई कहते हैं कि हमें वर्ग श्रेणियों को भी ध्यान में रखना होगा। एक नए अपार्टमेंट में अकेले रहने वाले तलाकशुदा के लिए निराशा का पैमाना अलग होगा जबकि उसी फ्लैट को बनाने वाले प्रवासी मजदूर के लिए पैमाना कुछ और होगा।

लेकिन इसमें संदेह नहीं कि समस्या हर जगह है। देसाई को शराब की लत से जुड़े अवसाद के मामलों में वृद्धि दिख रही है। उन्होंने *आउटलुक* को बताया, "अवसाद के मामले हमेशा ही ज्यादा आते हैं लेकिन इस समय इनमें काफी बढोतरी दिख रही है। हताशा और कुंठा में व्यवहार बदल जा सकता है, घरेलू हिंसा भी बढ़ सकती है।" घर पर बैठे रहने का एक और साइड इफेक्ट है कि कुछ रिपोर्ट के मुताबिक कंडोम की बिक्री बढ़ गई है। तो, क्या लोग और ज्यादा सेक्स करने लगे हैं? यह कोई काल्पनिक अनुमान नहीं है। यह आपदा के क्षण में मानवीय व्यवहार का प्रमाणित सच है। लेकिन क्या उस समय सेक्स के बारे में सोचा भी जा सकता है, जब शरीर खुद ही आशंकाओं से घिरा हुआ हो?

लॉकडाउन के पहले दस दिनों में ही बाल उत्पीड़न के एक लाख से अधिक कॉल दर्ज किए गए हैं

संभवत: इस मामले में वर्ग विभाजन का फर्क दिख सकता है। प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट प्रकाश कोठारी कहते हैं, "इस तरह के माहौल में सेक्स की बारंबारता बढ़ सकती है। गरीबों के पास जगह की कमी होती है, इसलिए उनकी सेक्स लाइफ प्रभावित होती है। चिंता का दौर छोड़ दीजिए, उनके पास प्राइवेसी होती ही नहीं है।" इसलिए कोरोना के बाद दुनिया में बेबी बूम आने की अटकलें एक अलग बात है। कोठारी इसका शुष्क जवाब देते हैं, "भारत में सामान्य समय में भी लोगों के पास तनाव दूर करने का यही एक माध्यम है। लोग मूवी टिकट के लिए कुछ सौ रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं।"

अगर हालात सामान्य हो जाएं तो मनोवैज्ञानिक समस्याएं ज्यादा गंभीर साबित होंगी। सरकार की ओर से एक एनजीओ संकट में घिरे बच्चों के लिए हेल्पलाइन चाइल्डलाइन 1098 संचालित

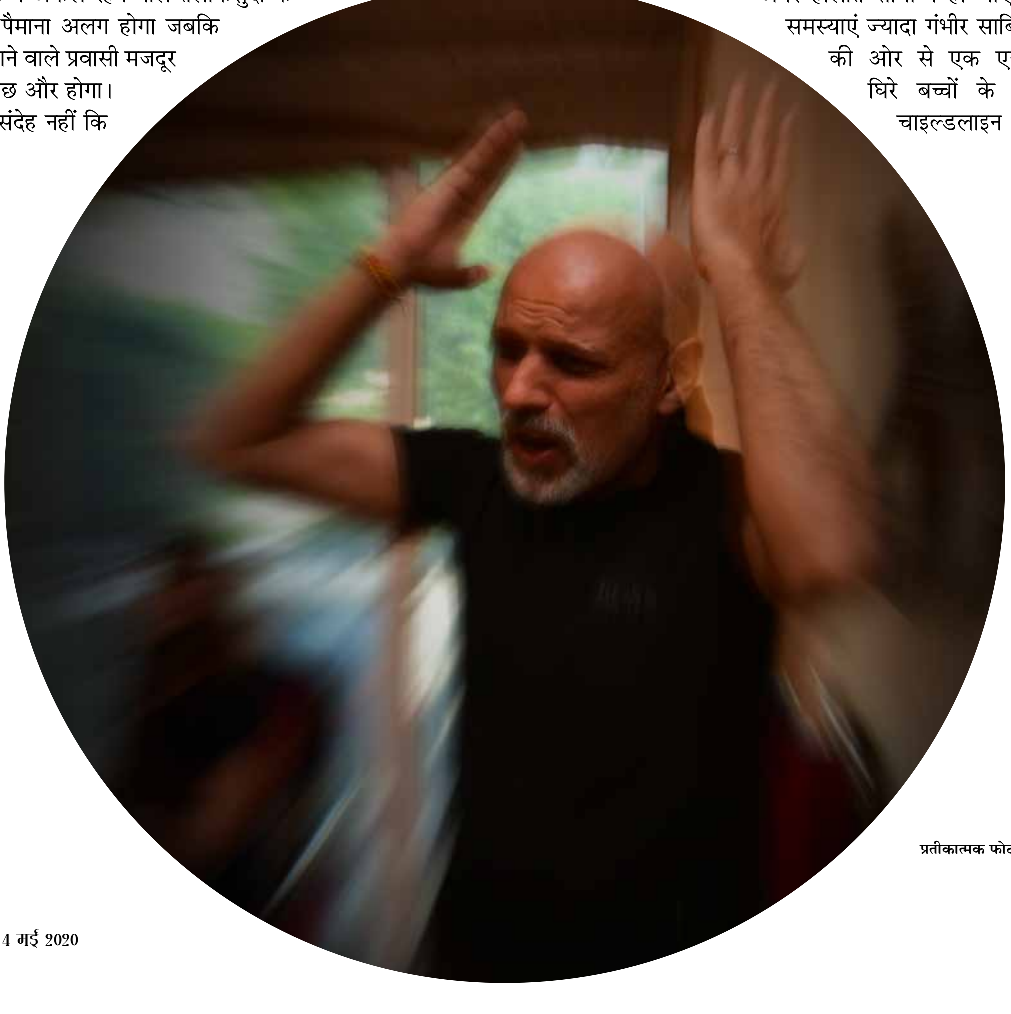

प्रतीकात्मक फोटो: त्रिभुवन तिवारी

करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा की थी, तबसे पूरे देश में इस हेल्पलाइन पर कॉल 50 फीसदी बढ़ गईं। ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि उत्पीड़न और हिंसा से बचाने की गुहार लगाने वाले 92,000 से ज्यादा बच्चों की कॉल शुरुआती 11 दिनों में ही आई। चाइल्डलाइन इंडिया की डिप्टी डायरेक्टर हरलीन वालिया कहती हैं, "3.07 लाख कॉल में से करीब 30 फीसदी कॉल 20-31 मार्च के बीच प्राप्त हुईं। लॉकडाउन का पहला सप्ताह इसी बीच पड़ा था।"

शराब से संबंधित मामले तुलनात्मक रूप से कम गंभीर दिखाई देते हैं। फिर भी लॉकडाउन के दौर में शराब न पीने से बेचैनी के लक्षण उभर सकते हैं, यह मृत्यु का कारण भी बन सकता है...

पिछले महीने ही नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर ने पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को इसके लिए तैयार रहने का सुझाव भेजा था। इसके बाद केरल ने तो उन लोगों को डॉक्टर की सलाह पर शराब मुहैया कराने की अनुमति दे दी जिनमें शराब न पीने से समस्याएं उभरने लगी हैं। हालांकि पिछले सप्ताह हाइकोर्ट ने सरकार के इस कदम को स्टे कर दिया। राज्य सरकार ने आत्महत्याओं (पहले सप्ताह में छह मामले) का हवाला दिया। हालांकि कई विशेषज्ञों का तर्क है कि डॉक्टर की सलाह पर भी शराब की अनुमति देना कोई हल नहीं है। मेघालय ने भी स्वास्थ्य आवश्यकता के आधार पर शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है। उसने भी डॉक्टर की सलाह पर इसकी अनुमति देने का फैसला किया है।

केरल के शराब संबंधी आदेश का विरोध करने वाले एनजीओ अल्कोहल ऐंड ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर-इंडिया के जॉनसन जे. इडयारनमूला मानते हैं कि 1967 के बाद पहली बार ऐसा हुआ, जब राज्य में पूरी तरह शराबबंदी-सी हो गई है, अलबत्ता परोक्ष तरीके से। उन्होंने कहा, "2014 की शराब नीति आने के बाद खपत के लिहाज से कमी (राजस्व के लिहाज से वृद्धि) आई है। इससे मुझमें विश्वास पैदा हुआ। ट्रेनिंग के जरिए स्वास्थ्य मशीनरी भी इसके लिए तैयार हो गई।" पिछले दो सप्ताह के दौरान अत्यधिक लत वाले 400 से ज्यादा लोगों को केरल के तमाम अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

बकौल एक मनोचिकित्सक, लॉकडाउन जारी रहा तो लोगों की मानसिक सेहत से जूझने की चुनौती बड़ी हो सकती है

केरल के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में पिछले एक महीने के दौरान एक लाख से ज्यादा लोगों को काउंसिलिंग दी गई। इनमें वे मरीज भी शामिल हैं जो क्वारंटाइन किए गए हैं। तिरुअनंतपुरम के मानसिक चिकित्सक अरुण बी. नायर कहते हैं कि केरल की शराब दुकानें बंद होने के बाद पहले तीन-चार दिनों में प्राप्त हुई अधिकांश कॉल शराब की लत के लक्षणों को लेकर थीं। सामान्य मामले निकटवर्ती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर कर दिए गए या फिर जरूरत होने पर हर जिले में चलने वाले आबकारी विभाग के नशा छुड़ाने वाले केंद्र विमुक्ति में भेज दिए गए। अगर मरीज शराब के नशे में बहुत ज्यादा फंसा है तो उन्हें मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ की देखरेख में भेजा गया है। रोजाना व्हाट्सएप पर कम से कम 30 मैसेज का जवाब देने वाले नायर कहते हैं, शराब न पीने की बेचैनी आमतौर पर तीन से पांच दिनों तक रहती है। अब यह अवधि निकल चुकी है। इसलिए शराब संबंधी कॉल आनी कम हो गई हैं।

कुछ संक्रमित लोग दूसरों में बीमारी फैलाने के अपराधबोध से भी परेशान हैं। घरेलू तनाव और नींद न आने से भी लोग परेशान हैं। नींद न आने की समस्या मोबाइल फोन की लत से भी जुड़ी है जो एक अन्य बीमारी का लक्षण है और इसका भी इलाज जरूरी है।

बेंगलूरू के एक मनोचिकित्सक बताते हैं कि भय किस कदर पैठ बना चुका है। वे एक ठीक-ठाक परिवार की एक मरीज का हवाला देते हैं, जो उनके पास पहुंची। उसमें पहले से चिंता और अवसाद के कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन उसमें हाथ धोने की जैसे सनक सवार थी। गले में खराश होने के कारण वह अस्पताल पहुंची थी। उसे चिंता थी कि कहीं उसे कोविड-19 तो नहीं है। काउंसिलिंग के बाद वह बेहतर महसूस कर रही थी। चिकित्सक का कहना है कि लोगों को बताओ कि चिंता करना ठीक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मानसिक रूप से बीमार हैं। कभी-कभी नींद न आना भी सामान्य है। इसका प्रभाव आप पर हावी नहीं होना चाहिए।

पहले से ही मानसिक विकार झेल रहे लोग बड़ी चिंता में हैं क्योंकि उनका नियमित इलाज और परामर्श प्रभावित हो रहा है। एम्स दिल्ली के मानसिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. नंद कुमार कहते हैं, मौजूदा मरीजों के लिए दवाइयां उपलब्ध कराना हमारे सामने बड़ी समस्या है। कुछ दवाइयां शिड्यूल एक्ट के तहत आती हैं जिनके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूरी है। वे कहते हैं कि हमारी ओपीडी बंद हैं और मरीज डॉक्टरों से परामर्श नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से उन्हें प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल पा रहा है। बीमारी दोबारा उभरने के केस सुनने में आ रहे हैं। यह स्थिति मरीजों और उनकी देखभाल करने वाले लोगों के लिए खतरनाक है। डॉ. कुमार के अनुसार अगर सरकार लॉकडाउन बढ़ाती है तो उसे अपनी नीतियों में मानसिक स्वास्थ्य को आगे रखना होगा और प्राथमिकता देनी होगी। यह किसी भी महामारी का बड़ा प्रभाव होता है।

प्रख्यात लेखक विवेक शानबाग के अनुसार, लोगों का विश्वास और भरोसा भी डगमगा सकता है। इसका असर लिखने-पढ़ने में भी दिख सकता है। उन्होंने *आउटलुक* को बताया, "इसका असर साहित्य लेखन में भी दिख सकता है। इसके असर से जीवन का हर पहलू, फिर चाहे ट्रैवल हो या फिर काम करना, सबकुछ बदलने जा रहा है।"

यकीनन, यह लगने लगा है कि मौजूदा दौर की स्थितियों से आए बदलाव जिंदगी हमेशा के लिए बदल देंगे। शानबाग कहते हैं, "कोरोना बीमारी के पहले के सामान्य दिन लौटने में लंबा समय लगने वाला है।" अभी तक जो चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती थीं, वे अब अहम हो सकती हैं। हम जिस तरह से कला और पुस्तकों की सराहना करते हैं, वह भी बदलने वाला है। अनिवार्य रूप से हमें एक बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि संभावित बदलाव आगे भी बना रहेगा। कोरोना से पहले की तरह हालात सामान्य होने पर भी ये चीजें लंबे समय तक पहले जैसी नहीं होंगी।

1918 के स्पैनिश फ्लू का बदलाव विचारों में भी दिखाई दिया। देखिए, फ्लू से लाखों लोगों की जिंदगी जाने पर व्यथित महात्मा गांधी ने क्या कहा था। *पेल राइडर: स्पैनिश फ्लू ऑफ 1918 ऐंड हाउ इट चेंज्ड द वर्ल्ड* में लेखिका लौरा स्पिनी ने गांधी के बारे में लिखा, डॉक्टरों की सलाह गांधी जी को माननी पड़ी और उन्हें दूध पीना शुरू करना पड़ा। उससे पहले तक वे दूध लेने से बचते थे। गांधी जी ने लिखा, "इस लंबी बीमारी ने मुझे अपने सिद्धांतों का परीक्षण करने का अनूठा अवसर दिया।" अब शायद लाखों लाख लोगों के लिए नई चीजें अपनाने का वैसा ही मौका आन पड़ा है।

कोविड-19/सामाजिक बेरुखी

लखवंत सिंह

कोरोना का डरः मोहाली में एक अंत्येष्टि में गिने-चुने लोग ही पहुंचे

अपनों को भी कंधा देने से गुरेज

कोरोना संक्रमित लोगों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार से इनकार कर रहे अपने रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी

चंडीगढ़ से **हरीश मानव**

महामारी कई तरह की सामाजिक विद्रूपताएं भी लेकर आती है। यह भी सही हो सकता है कि हर महामारी के दौरान सामाजिक व्यवहार अलग-अलग-सा होता रहा हो, लेकिन ऐसी असंवेदनशीलता और बेरुखी की मिसाल इतिहास के किसी कालखंड में बमुश्किल ही मिली कि लोग अपनों को भी कंधा देने से कतराने लगें और अंतिम संस्कार लावारिश की तरह हो। दुनिया के दूसरे देशों से भी कई शवों को एक साथ दफनाने की तसवीरें सामने आई हैं, लेकिन रिश्तों की पक्की गांठ पर इतराने वाले भारत में ऐसे नजारे दिल दहलाने वाले हैं।

पिछले 20 दिनों में कोरोना विषाणु से खौफजदा समाज में अलगाव की ऐसी तस्वीरें तेजी से उभरी हैं। इंदौर में मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू बुजुर्ग महिला की अर्थी को कंधा दिए जाने के अपवाद को छोड़ दें तो कोरोना पीड़ितों के संस्कार में ही नहीं, बल्कि 24 मार्च को हुए देशव्यापी लॉकडाउन के बाद घरों में दुबके लोग किसी करीबी रिश्तेदार, मित्र और पड़ोसी की सामान्य मौत होने पर भी अंतिम संस्कार में जाने से गुरेज कर रहे हैं। कर्फ्यू में सीलबंद शहरों की सीमाओं ने दूसरे शहरों से आने वाले रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार में शामिल होने से भले ही रोक दिया है, पर कड़ी बंदिश न होने के बावजूद स्थानीय रिश्तेदार भी अंतिम संस्कार में जाने से बच रहे हैं। अंतिम संस्कार के समय आने वाले स्थानीय रिश्तेदारों, मित्रों, पड़ोसियों की संख्या दर्जनभर से भी कम रह गई है। पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आए जब अर्थी उठाने के लिए चार कंधे भी मौके पर नहीं थे।

ताकि डर छंटे: **एक कोरोना पीड़ित के अंतिम संस्कार में पंजाब के मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और बलबीर सिंह सिद्धू भी शामिल हुए**

अमृतसर: गुरबानी से पूरी दुनिया को निहाल करने वाले पद्मश्री निर्मल सिंह कोरोना के कहर से सदा के लिए खामोश हो गए। अमृतसर के गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) के प्रमुख रागी निर्मल सिंह, जिनकी हाजिरी में लोगों का हुजूम उमड़ता था, को आखिरी वक्त में अपने पैतृक गांव वेरका की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। कोरोना फैलने से खौफजदा निर्मल सिंह के अपने ही गांववालों ने उनका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया, तो साथ लगते दूसरे गांवों के लोगों ने भी साफ इनकार कर दिया। अंतिम संस्कार के लिए 21 घंटे दर-बदर भटकते लाचार बेटे को अपने पिता का अंतिम संस्कार रात आठ बजे एक खेत में करना पड़ा। जैसा रागी निर्मल सिंह का कद था, उसे देखते हुए कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि सामान्य हालात होते तो श्रद्धांजलि के लिए दो दिन तक लोगों की कतारें नहीं टूटतीं।

अमृतसर: 8 अप्रैल को ही नगर निगम के पूर्व अतिरिक्त कमिश्नर जसविंदर सिंह की एक निजी अस्पताल में कोरोना उपचार के दौरान मौत हो गई। उनके परिजनों ने शव लेने से इनकार किया तो प्रशासन ने अंतिम संस्कार कराया। जसविंदर सिंह की अर्थी को कंधा देने से लेकर मुखाग्नि देने वालों में नगर निगम के कर्मचारी ही थे। परिवार का कोई सदस्य अंतिम संस्कार के लिए श्मशानघाट नहीं पहुंचा। अंतिम अरदास के लिए ग्रंथी का प्रबंध भी तहसीलदार अर्चना ने किया। जसविंदर की बेटी अमृतसर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की छात्रा है।

लुधियाना: यहां शिमलापुरी की 70 वर्षीय महिला कमला की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। चार घंटे तक अस्पताल प्रबंधन परेशान था कि घरवाले लाश ले जाएं, तो इस आइसोलेशन वार्ड में और मरीजों को लाया जाए। कोई नहीं आया तो कमला की लाश मुर्दाघर भेज दी गई। इस बीच बेटे को कई दफा सूचना दी गई कि मुर्दाघर से मां की लाश ले जाएं। 22 घंटे तक मुर्दाघर में पड़ी लाश को उठाने से बेटे ने आखिर इनकार कर दिया तो अस्पताल ने अंतिम संस्कार के लिए नगर निगम कर्मियों को बुलाया। अंतिम संस्कार के वक्त कमला का पूरा परिवार श्मशानघाट के बाहर अपनी गाड़ी में बैठा रहा।

कोरोना संक्रमित लोगों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी राख या अस्थियों से वायरस नहीं फैलता, इससे डर बेवजह

मोहाली: मोहाली के नया गांव के 65 वर्षीय रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओमप्रकाश की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए पिता की पार्थिव देह को पीजीआइ से अकेला बेटा एंबुलेंस में मोहाली के श्मशानघाट लेकर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि एंबुलेंस के पीछे कुछ रिश्तेदार, पड़ोसी और पिता के दोस्त पहुंचेंगे। आखिरकार पिता के शव को एंबुलेंस से उतारने के लिए चार कंधे नहीं मिल पाए। मौके से एंबुलेंस का ड्राइवर भी चला गया। फोन करने पर नगर निगम कमिश्नर द्वारा जबरन भेजे गए दो सफाईकर्मी पहुंचे, एंबुलेंस और ओमप्रकाश के पार्थिव शरीर को सेनेटाइज़ किया पर कंधा देने से उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। आखिर अकेले बेटे ने ही पिता को कंधे पर लाद कर इलेक्ट्रिक भट्ठी में रखा।

8 अप्रैल को जालंधर में कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार का विरोध करने वाले 60 लोगों के

पीटीआइ

सामूहिक कब्रः अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना संक्रमण के शिकार लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार

खिलाफ आइपीसी की धारा 188, 269, 270, 271, 353, 186, 149 एपीडेमिक डिजीज एक्ट 1893 की धारा 3 और डिजॉस्टर मैनेजमेंट एक्ट 1996 की धारा 51 के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया।

लुधियाना के डीएमसी अस्पताल और कुंदन विद्या मंदिर स्कूल के पीछे स्थित श्मशानघाट मुक्ति धाम के केयर-टेकर रमेश कपूर के मुताबिक यहां एक मार्च से छह अप्रैल तक हुए 171 अंतिम संस्कारों में शामिल होने वालों की संख्या में 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद से तेजी से गिरावट आई है। कपूर ने *आउटलुक* को बताया कि कोरोना और कर्फ्यू के बीच प्रशासन की सख्ती के चलते कई संस्कारों में शामिल होने वालों की संख्या एक दर्जन से भी कम थी, जबकि पहले अमूमन एक अंतिम संस्कार में 100 से 150 लोग शामिल हुआ करते थे। पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव सरवेश कौशल के मुताबिक खासकर कोरोना पीड़ितों की मृत्यु के बाद बेटों और करीबियों द्वारा अंतिम संस्कार से इनकार करने से समाज की ऐसी भयावह तसवीर सामने आई है जिससे पूरी इनसानियत शर्मसार है। कोरोना से जिंदगी की जंग हारने वाली लुधियाना की शिमलापुरी की 70 वर्षीय बुजुर्ग कमला की मौत के बाद सगा बेटा और अन्य परिजन ही आगे नहीं आए। उनके अंतिम संस्कार से लेकर श्रद्धांजलि तक का जिम्मा उठाने वाले लुधियाना के एडीसी इकबाल सिंह संधू ने गहरा दुख जाहिर करते हुए कहा कि जिस मां ने जन्म दिया उसके पार्थिव शरीर को कंधा न देने और संस्कार तक से दूरी बनाने की घटना बेहद शर्मसार करने वाली है। महिला का अंतिम संस्कार तो प्रशासन ने किया ही, उनकी आत्मा की शांति के लिए गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह में अखंड पाठ भी प्रशासन ने कराया।

लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में लायंस क्लब से जुड़े ट्रैफिक मार्शल अंतिम संस्कार के लिए आगे आए हैं। पंजाब के दो कैबिनेट मंत्रियों ने भी कोरोना से मरने वालों के संस्कार में शामिल होने की पहल की है। ऐसे दो संस्कारों में शामिल हुए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने *आउटलुक* को बताया, "कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार स्थानीय प्रशासन की देख-रेख में कराए जा रहे हैं, संस्कार में शामिल होने से कोरोना संक्रमित होने की आशंका बेवजह है। रसायन लेप लगी कोरोना मरीज की देह का अंतिम संस्कार स्थानीय निकाय और श्मशानघाट के कर्मचारी पीपीई किट पहन कर करते हैं। संस्कार के बाद इनकी राख और अस्थि से कोरोना विषाणु फैलने का डर नहीं है। ऐसे मौकों पर शामिल होने वाले सामाजिक दूरी बनाए रखें तो यह बहुत सुरक्षित है। यही साबित करने मैं और मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी चरणजीत चन्नी ऐसे कुछ संस्कारों में शामिल हुए।" सिद्धू का कहना है कि जो औलादें अपने मां-बाप के अंतिम संस्कार से पीछे हटी हैं, उनका मां-बाप की संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं है।

कोरोना से एकाएक हजारों मौतों के चलते इटली में कॉफिन में बंद लाशों के ढेर कब्रिस्तानों में ऐसे निपटाए जाने की तसवीरें सामने आईं जैसे डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा निपटाया जा रहा हो। पर भारतीय संस्कृति में परिजनों द्वारा अपनों के ही अंतिम संस्कार से मुंह फेरने की घटनाएं खून के रिश्तों पर सवाल खड़े करती हैं। कोरोना तो देर-सबेर चला जाएगा पर कोरोना के दंश से दम तोड़ने वालों के अंतिम संस्कार से खून के जो रिश्ते तार-तार हुए हैं, वह कैसे जुड़ेंगे।

कोरोना ने तोड़ा विदेशी बाजार

कोविड-19 महामारी से चीन सहित समूचा विदेशी बाजार थमा तो बॉलीवुड की कमाई के दायरे सिकुड़े

विदेश में धूमः ***दंगल*** **का चायनीज पोस्टर, शाहरुख खान विदेश में प्रशंसकों के बीच (नीचे)**

मुंबई से **गिरिधर झा**

इस वक्त तो रितिक रोशन को चीन में होना चाहिए था, जिन्हें अपने देश में हिंदी सिनेमा के दीवाने 'ग्रीक गॉड' यानी यूनानी देवताओं जैसे खूबसूरत बताते हैं। बीते साल की सुपर हिट फिल्म *वार* के बाद 46 वर्षीय अभिनेता रितिक रोशन की बिहार के गणित शिक्षक आनंद कुमार पर 2019 में बनी बॉयोपिक *सुपर 30* अप्रैल में रिलीज होनी थी। सो, रिलीज से पहले प्रमोशन के लिए रितिक को पिछले महीने के आखिर में चीन जाना

गैटी इमेजेज

था। लेकिन कोरोना वायरस के संकट ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उनके चीनी प्रशंसकों को अब अपने दा शुइ (बेहद खूबसूरत सितारा) की झलक पाने के लिए लंबा इंतजार करना होगा।

कोविड-19 महामारी से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। सबसे ताकतवर देशों की अर्थव्यवस्था भी घुटनों के बल बैठ गई है। ऐसे में किसी को नहीं पता कि *सुपर 30* चीन के परदों पर कब दिखेगी? कथित तौर पर इस वायरस के संक्रमण की शुरुआत वाले वुहान शहर 76 दिनों के लॉकडाउन के बाद खुल तो गया है, लेकिन हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं। मौजूदा परिस्थितियों में यह अनुमान लगाना कठिन है कि चीन में सिनेमा का बाजार कब आम दिनों जैसे खुल जाएगा। तो, क्या यह माना जाए कि बॉलीवुड के लिए चीन का बाजार बंद हो जाएगा, जिसे ट्रेड एनालिस्ट भारतीय अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के लिए सोने की खान बताते रहे हैं? रितिक के लिए चीन के मुख्य भूभाग में *सुपर 30* की रिलीज को लेकर काफी कुछ दांव पर है। बिहार के गरीब परिवारों के बच्चों को आइआइटी सरीखे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला दिलाने के लिए जीवन खपा देने वाले एक गरीब शिक्षक पर बनी इस बॉयोपिक को पिछले साल भारत में काफी सराहा गया था और कमाई भी अच्छी-खासी हुई थी। लेकिन बॉक्स ऑफिस पंडित मानते हैं कि सभी को शिक्षा का संदेश देने वाली इस फिल्म की पटकथा की सर्वव्यापी अपील के कारण चीन में इसे जबदस्त सफलता मिल सकती है। कई विश्लेषकों का तो यहां तक मानना है कि चीनी दर्शकों को लुभाकर यह खूब कमाई कर सकती है, जैसा कमाल कुछ वर्ष पहले आमिर खान की *दंगल* (2016) ने दिखाया था। *सुपर 30* के संस्थापक आनंद कुमार ने *आउटलुक* को बताया, "यह फिल्म चीन में इस महीने (अप्रैल) रिलीज होनी थी। रितिक और मुझे फिल्म के प्रमोशन के लिए मार्च के आखिर में चीन जाना था लेकिन

विदेश में दस सबसे सफल भारतीय फिल्में*

दंगल 2016
$22.8 करोड़

सीक्रेट सुपरस्टार 2017
$14 करोड़

बजरंगी भाईजान 2015
$8.04 करोड़

डिस्को डांसर 1982
$7.58 करोड़

बाहुबली 2 2017
$5.85 करोड़

पीके 2014
$5.34 करोड़

अंधाधुन 2018
$4.88 करोड़

हिंदी मीडियम 2017
$3.65 करोड़

धूम 3 2013
$3.56 करोड़

3 इडियट 2009
$3.05 करोड़

*स्रोत: ट्रेड मैगजीन

कोरोना वायरस के चलते सब कुछ थम गया।"

अपने गृह नगर पटना में समाज के कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए पहला कोचिंग सेंटर शुरू करके प्रसिद्धि पाने वाले 47 वर्षीय आनंद मानते हैं कि पूरी दुनिया में जो स्थिति पैदा हुई है, "उसे देखते हुए इस समय चीन में *सुपर 30* के रिलीज के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता है। वे कहते हैं, इस महामारी ने हर किसी व्यक्ति और उद्योग को प्रभावित किया है और लोगों की जिंदगी संकट में डाल दी है। घर पर सुरक्षित रहना समय की सबसे बड़ी मांग है।"

हालांकि आनंद को उम्मीद है कि अगले महीने हालात सुधरेंगे। उनका कहना है, चीन में हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं। लेकिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गतिविधियां शुरू होने में अभी पांच-छह महीने और लगेंगे।

निस्संदेह इस महामारी ने न सिर्फ रितिक की फिल्म की कारोबारी संभावनाओं को, बल्कि समूचे बॉलीवुड को बड़ा झटका दिया है। बॉलीवुड कई बड़ी फिल्मों की नाकामी के दौर से गुजर रहा है, अब इस साल वह कोविड-19 के संकट में फंस गया है। भारतीय फिल्मों के लिए चीन कितना बड़ा बाजार है, खासकर पिछले चार-पांच वर्षों में विकसित हुआ है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ *दंगल* फिल्म ने 2017 में वहां 1,357 करोड़ रुपये का कारोबार किया। आमिर खान की फिल्म *सीक्रेट सुपरस्टार* का चीन में 800 करोड़ रुपये का कारोबार भारत में उसके कारोबार से नौ गुना ज्यादा रहा था।

हालांकि चीन फिल्मों के पारंपरिक विदेशी बाजारों में शामिल नहीं है और वहां के कठोर सेंसरशिप नियमों के चलते भारत की चुनिंदा फिल्मों को ही रिलीज की अनुमति मिल पाती है। भारतीय फिल्मों के विदेशी कारोबार में से 75

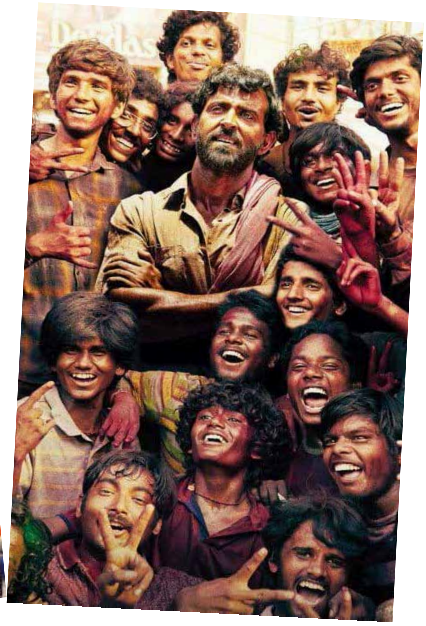

सफल फिल्में: (ऊपर से) ***हिंदी मीडियम, बजरंगी भाईजान, बाहुबली, अंधाधुन* और *सुपर 30***

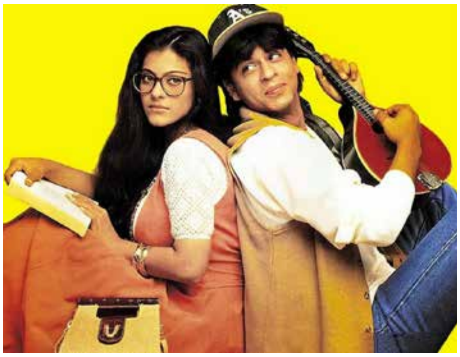

पुरानी यादें: (बाएं से) *आवारा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे* और (नीचे) *डिस्को डांसर*

फीसदी अमेरिका (30 फीसदी), ब्रिटेन (20 फीसदी) और अरब जगत (25 फीसदी) से मिलता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बाकी यूरोप और दक्षिण-पूर्वी एशिया प्रमुख बाजार हैं, जहां भारतीय समुदाय हर हफ्ते भारतीय फिल्में रिलीज होने का इंतजार करता है।

फिक्की और अर्स ऐंड यंग की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में हिंदी फिल्मों के 4,950 करोड़ रुपये के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ भारतीय घरेलू फिल्मों का कुल राजस्व 11,500 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में फिल्मों का विदेशों में कारोबार 10 फीसदी गिरकर 2,700 करोड़ रुपये रह गया जबकि ज्यादा फिल्में विदेशों में रिलीज हो रही हैं।

विदेशी राजस्व में गिरावट मुख्य तौर पर पिछले साल सुपरस्टारों की कुछ बड़ी फिल्में फ्लॉप होने के कारण दर्ज की गई लेकिन इसे भारतीय सिनेमा में विदेशी दर्शकों की दिलचस्पी घटने के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। इससे हटकर इन्हीं एजेंसियों ने अपनी पिछली रिपोर्ट में कहा था कि भारतीय फिल्म कारोबार 2021 तक 11.6 फीसदी की सालाना रफ्तार से बढ़ेगा। 2018 में इसका कारोबार 23.9 अरब डॉलर था जो 2017 के मुकाबले 13.4 फीसदी बढ़ा था। इन सभी वर्षों में भारतीय फिल्मों का विदेशी बाजार तेजी से बढ़ा और इसके कारण राजस्व वृद्धि में उनका योगदान और बढ़ गया। लेकिन अब समूचे विदेशी बाजार के सभी आशावादी अनुमान कोरोना वायरस के खतरे के कारण बेमानी साबित हो सकते हैं। देश-विदेश में सभी सिनेमा हॉल बंद होने के कारण भारतीय फिल्म उद्योग के लिए इस साल निराशाजनक स्थिति दिखाई दे रही है।

मूवी ट्रेड जर्नल *कंप्लीट सिनेमा* के संपादक अतुल मोहन कहते हैं कि इस साल अगस्त-सितंबर से पहले हालात सुधरने की कोई उम्मीद नहीं है। उनका कहना है, "इस समय भय का माहौल है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद शुरुआती हफ्तों में अधिकांश दर्शक थिएटरों से दूर ही रहेंगे। थिएटर खुलने के बाद जनता का मूड समझने के लिए पहले से ही रिलीज फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। बड़ी फिल्में निश्चित ही कुछ और महीने रोकी जाएंगी।"

मोहन ने बताया, "इससे फिल्म निर्माताओं को, खासकर बॉलीवुड को हर तरफ भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बॉलीवुड की फिल्में विदेशों में अपनी लोकप्रियता के चलते अपने कुल कारोबार का 30 से 50 फीसदी विदेशी बाजारों से पाने की उम्मीद करती हैं। इस लोकप्रियता ने शाहरुख खान को बॉलीवुड का किंग बनाया और फिल्म निर्माताओं को उसकी वास्तविक संभावनाओं का एहसास कराया।"

ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने अनायास नई सदी में विदेशी बाजार के गुप्त खजाने को खोजा है। 1949 में के.ए. अब्बास की *धरती के लाल* (1946) तत्कालीन सोविय संघ में रिलीज हुई थी। तीन साल बाद, मेहबूब खान की दिलीप कुमार अभिनीत *आन* (1952) को 28 देशों में रिलीज करने से पहले 17 भाषाओं में उसकी डबिंग की गई। राज कपूर की मशहूर फिल्म *आवारा* (1951) सोवियत संघ और चीन जैसे देशों में 1954 में रिलीज होने के बाद यादगार फिल्म बन गई और विदेश में 10 करोड़ से ज्यादा टिकट बिक्री वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। कुछ दशकों तक *कारवां* (1971) या *बॉबी* (1973) को छोड़कर विदेश में रिलीज हुई फिल्में कम ही चल पाईं लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की *डिस्को डांसर* (1982) सोवियत संघ और चीन में जबर्दस्त हिट हुई। 1991 में सोवियत संघ के विघटन से बॉलीवुड का तब का सबसे बड़ा विदेशी बाजार बिखर गया।

दिलचस्प तथ्य यह है कि सोवियत मार्केट के विघटन से ही उदारीकरण के दौर के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, बाकी यूरोप और यहां तक कि मध्य-पूर्व में बॉलीवुड फिल्मों के विदेशी कलेक्शन में भारी बढ़ोतरी हुई। बड़ी संख्या में दक्षिण एशियाई कर्मचारियों, खासकर आइटी सेक्टर में भारतीयों के विदेशों में जाने के कारण ही न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि तमिल, तेलुगु और पंजाबी जैसे क्षेत्रीय फिल्म उद्योगों के लिए नई सदी के ये अत्यंत आकर्षक बाजार बन गए। वास्तव में विदेशी बाजार इतने अच्छे बाजार बन गए कि अधिसंख्य फिल्में भारतीय समुदाय की रुचियों के अनुसार अप्रवासी भारतीयों के इर्द-गिर्द बनने लगीं। शाहरुख खान की *दिलवाले दुल्हनिया ले*

कोरोना संकट के चलते सिनेमा हॉल बंद, फिल्म उद्योग के लिए इस साल निराशा ही निराशा

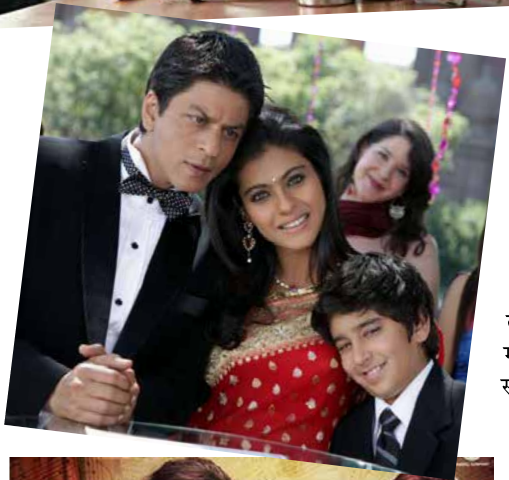

कुछ और हिट्स: (ऊपर से) *द लंचबॉक्स, माय नेम इज खान* और *सीक्रेट सुपरस्टार*

जाएंगे (1995) ने पश्चिमी देशों में बसे अप्रवासी भारतीय दर्शकों को ऐसे लुभाया जैसा पिछली किसी फिल्म ने नहीं किया था। जबकि उनकी *दिल से* (1998) ब्रिटेन के बॉक्स ऑफिस की शीर्ष दस फिल्मों में स्थान पाने वाली पहली फिल्म बन गई। इसके बाद शाहरुख खान की *माय नेम इज खान* (2010) ने विदेशी बाजार में 100 करोड़ रुपये जुटाने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी। कोई आश्चर्य नहीं कि वितरक आने वाले वर्षों में एसआरके को विदेशी बाजार के भगवान की तरह पूजने लगें।

शाहरुख खान की तरह दो अन्य खान सुपरस्टार आमिर और सलमान भी इस दौरान समूचे विदेशी बाजार में लोकप्रियता पाने लगे। *दंगल* और *सीक्रेट सुपरस्टार* ने आमिर को चीन के दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया जबकि सलमान को पश्चिम एशियाई देशों में भारी लोकप्रियता मिली। उनकी *बजरंगी भाईजान* (2015) को चीन के बाजार में भी अच्छी सफलता मिली। लेकिन इन कलाकरों को विदेशी बाजार में कभी एकाधिकार नहीं मिला। अगर कोई भले ही छोटी हो, लेकिन फिल्म अच्छी है तो कलाकार मायने नहीं रखता है। यह बात इरफान खान की फिल्म *द लंचबॉक्स* (2013) की असाधारण सफलता से साबित हो गई। दिलचस्प है कि जब बॉलीवुड अमेरिका और दूसरे बाजारों में कारोबारी सफलता हासिल कर रहा था, उस समय हिंदी फिल्म निर्माताओं को नई सहस्राब्दी में उभरते चायनीज बाजार के बारे में कोई एहसास नहीं था। चायनीज दर्शकों की बॉलीवुड फिल्मों में दिलचस्पी एक दशक पहले उस समय पैदा हुई जब *3 इडियट्स* के पायरेटेड प्रिंट ने चीन के बाजार में प्रवेश किया, तब वहां के दर्शकों के बारे में एहसास हुआ। इसके बाद आमिर खान की यह फिल्म आधिकारिक तौर पर रिलीज हुई लेकिन सही मायने में भारतीय फिल्मों का प्रवेश आमिर की अगली फिल्म *पीके* (2014) से हुआ। इसने चीन के बाजार से 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई की। इसके साथ ही इस बाजार की व्यापक संभावनाओं का एहसास हुआ। तब तक *दंगल* और *सीक्रेट सुपरस्टार* भी रिलीज हुईं। उसने आमिर को इतना बड़ा स्टार बना दिया कि उनकी दोनों फिल्मों ने उसी समय रिलीज होकर हॉलीवुड की बड़े बजट की फिल्मों से भी ज्यादा कारोबार किया और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाल के वर्षों में छोटे बजट की फिल्में जैसे इरफान खान की *हिंदी मीडियम* (2017), रानी मुखर्जी की *हिचकी* (2018) और आयुष्मान खुराना की *अंधाधुन* (2018) ने अच्छा कारोबार किया। सभी की नजरें अब आने वाली बड़ी फिल्मों जैसे अक्षय कुमार की *सूर्यवंशी* और रणवीर सिंह की *83* पर टिकी थीं, जो रिलीज होने वाली थीं लेकिन लॉकडाउन के कारण रोक दी गईं। फिल्म आलोचक मुर्तजा अली खान कहते हैं कि दुनिया के मौजूदा दौर का सबसे बुरा प्रभाव फिल्म कारोबार पर पड़ा है। वह कहते हैं, "सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन ने सिनेमा हॉलों और मल्टीप्लेक्सों को बंद कर दिया है। शूटिंग अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई हैं। कई नई फिल्में महीनों के लिए टाल दी गई हैं। बॉलीवुड को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है।"

हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के साथ सीधी टक्कर टालने के लिए भारतीय निर्माताओं को विदेशी बाजारों में रिलीज के लिए और लंबा इंतजार करना होगा

खान कहते हैं कि यूरोप, चीन, अरब जगत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पारंपरिक रूप से बॉलीवुड के लिए फायदेमंद बाजार हैं लेकिन कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर लंबे अरसे तक व्यापक प्रभाव पड़ने की आशंका है। इस बात की क्षीण संभावना दिखती है कि जल्दी ही हालात सामान्य हो पाएंगे। उन्होंने कहा, "वैश्विक स्तर पर महामारी कितने समय में काबू हो पाती है, इसी से तय होगा कि बॉलीवुड अपना विदेशी बाजार छह महीने में दोबारा हासिल कर पाएगा या फिर कई साल लग जाएंगे।"

फिल्म कारोबार विश्लेषक गिरीश जोहर इससे सहमत हैं। उनका कहना है कि बॉलीवुड के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। जोहर कहते हैं, "भय और मनोरंजन एक साथ नहीं चलते हैं। जब आम लोग कोरोना के खतरे से भयभीत हैं तो वे थिएटर जाने की कैसे सोच सकते हैं। फिल्में उनके दिमाग में आखिरी विचार के तौर पर होंगी।" जोहर के अनुसार, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड के बड़े स्टूडियो जैसे सोनी, पैरामाउंट और मार्वेल को भी अपनी आगामी बड़ी फिल्मों की रिलीज कुछ महीनों के लिए या फिर एक साल के लिए टालनी पड़ी है। जोहर ने कहा, "जैसे ही हालात सुधरेंगे, वे अपनी फिल्में रिलीज करने लगेंगे। लेकिन भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए ज्यादा समस्या होगी, क्योंकि उसी समय विदेशी बाजार में रिलीज होने पर हॉलीवुड के साथ सीधा टकराव होगा।"

वे कहते हैं कि बॉलीवुड में बड़ी फिल्मों के निर्माता, जो रिलीज के लिए तैयार हैं, उन्हें खासतौर पर सबसे ज्यादा नुकसान है। वह अगर लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद रिलीज करने का फैसला करते हैं तो उन्हें विदेशी बाजार का मोह छोड़ना होगा, क्योंकि वहां हालात जल्दी सामान्य होने वाले नहीं हैं। अगर वे परिस्थितियां सुधरने का इंतजार करते हैं तो उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना होगा, क्योंकि फिल्म बनाने के लिए उधार लिए गए पैसे पर भारी ब्याज भरना होगा। उनके लिए यह दोधारी तलवार से कम नहीं है।

राजनीतिक मुठभेड़ की कविताएं

प्रियदर्शन

सत्तर के दशक में नक्सलबाड़ी आंदोलन की रोशनी और वाम विश्वासों की छाया में जब मंगलेश डबराल ने अपनी कविता यात्रा प्रारंभ की तो दुनिया शीतयुद्ध में घिरी थी, जिसमें अपने पक्ष की पहचान भी आसान थी और शत्रुओं की शिनाख्त भी। साथ ही हिंदी में जनवादी कविता का मुहावरा इतना प्रखर था और उसकी आलोचकीय घेरेबंदी इतनी प्रबल, कि उन दिनों जब उनका पहला कविता संग्रह *पहाड़ पर लालटेन* आया तो उसकी नव्यता से अभिभूत होने के बावजूद हिंदी आलोचक उसे जनवादी कविता की कसौटी पर कसते रहे।

मंगलेश डबराल का छठा कविता संग्रह *स्मृति एक दूसरा समय है* अपनी मद्धिम मगर स्पष्ट आवाज में इस नितांत जटिल यथार्थ को पहचानने और तार-तार करने का उपक्रम है, जिसे मालूम है कि उसे बाजार-सत्ता और संस्कृति के घात-प्रतिघात से बचते हुए मनुष्यता की मूल वर्णमाला को बचाना है। शब्दों के बदलते अभ्यास और अर्थ पर कवि की बारीक नजर है- 'आततायी छीन लेते हैं हमारी पूरी वर्णमाला / वे भाषा की हिंसा को बना देते हैं / एक समाज की हिंसा / ह को हत्या के लिए सुरक्षित कर दिया गया है / हम कितना ही हल और हिरन लिखते रहें / वे हत्या ही लिखते हैं हर समय।'

कवि के लिए इसका प्रतिरोध स्मृति है। वे कहते हैं, "याद रखने पर हमला है और भूल जाने की छूट है' और अंत में जोड़ते हैं- 'बाजार कहता है याद मत करो / अपनी पिछली चीजों को पिछले घर को / पीछे मुड़ कर देखना भूल जाओ / जगह-जगह खोले जा रहे हैं नए दफ्तर / याद रखने पर हमले की योजना बनाने के लिए / हमारे समय का एक दरिंदा कहता है / मेरा दरिंदा होना भूल जाओ।'

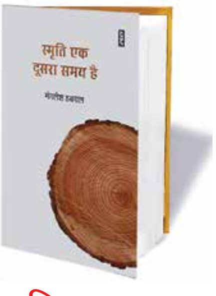

स्मृति एक दूसरा समय है
मंगलेश डबराल
प्रकाशक | सेतु प्रकाशन
मूल्यः 125 रुपये | पृष्ठः 112

इन कविताओं को ठेठ राजनैतिक कविताओं की तरह पढ़ा जाए, जो कि वे हैं भी। कुछ इतनी स्पष्ट हैं कि उसमें हमारे समय के राजनैतिक किरदार दिखते हैं। अनायास धर्म और परंपरा की ओट में सांप्रदायिकता का नंगा नाच कर रही राजनीति के प्रति कवि की मानवीय वितृष्णा बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। 'जो डराता है', 'हिटलर', 'तानाशाह' 'हत्यारों का घोषणापत्र', 'पुराना अपराधी' जैसी कविताएं इसका प्रमाण हैं। तीन पंक्तियों की एक कविता 'भाईचारा' भी इसी की कड़ी है- 'हत्यारे से मिलो / तो वह कहता है किसने कहा मैं हूं हत्यारा / मैं सदा चाहता हूं सबमें भाईचारा।' ये आततायियों से आंख मिलाती, उनको शर्मिंदा करती कविता है।

कविता के जरिए की जा रही यह राजनीतिक मुठभेड़ इस संग्रह का बस एक पक्ष है। इसका बड़ा पक्ष वह मानवीय ऊष्मा और ऊर्जा है जो इन कविताओं को सत्ता और बाजार द्वारा बनाए जा रहे इस सांस्कृतिक ग्रह के फरेबी गुरुत्वाकर्षण से एक झटके में बाहर ले जाती है और स्मृति, पहचान और प्रतिरोध का अपना संसार बसाती है। पिछले संग्रह *नये युग में शत्रु* में डबराल ने बाजार के जिस मायावी संसार को अचूक ढंग से पहचाना था, उसके प्रतिनिधियों की शिनाख्त यहां भी है- 'वे गले में सोने की मोटी जंजीर पहनते हैं / कमर में चौड़ी बेल्ट लगाते हैं / और मोबाइलों पर बात करते हैं / वे एक आधे अंधेरे और आधे उजाले रेस्तरां में घुसते हैं / और खाने और पीने का ऑर्डर देते हैं / वे आपस में जाम टकराते हैं / और मोबाइलों पर बात करते हैं'।

बहुत अच्छी और अचूक राजनैतिक कविताओं के बीच बहुत सूक्ष्मता के साथ बुनी गई एक उदात्त मानवीयता इन कविताओं का वास्तविक प्राप्य है, जो मंगलेश डबराल को हमारे समकालीन विश्व का एक बड़ा कवि बनाती है। अपनी रूह को बचाने की सारी जुगत कर रहे एक मनुष्य की धीमी आवाज हैं ये कविताएं- 'इतने सारे लोग इतना बड़ा मुल्क / लेकिन कहीं कोई रूह नहीं।'

विसंगतियों का दस्तावेज

संदीप सरस

राजेश मलिक का उपन्यास *आधा आदमी* किन्नर समाज की विसंगतियों का दस्तावेज है। राजेश मलिक ऐसा प्रयास करने में काफी हद तक कामयाब रहे। थर्ड जेंडर के अभिशप्त जीवन की मुखर व्यथा-कथा में अभागे दीपक के दीपिका माई बनने के सफर की दर्दनाक कहानी पढ़ते हुए गिजगिजा-सा एहसास जेहन में पैवस्त हो जाता है। जितनी घृणा थर्ड जेंडर की जीवनशैली से होती है, उससे कहीं ज्यादा घृणा उसके प्रति समाज के घटिया रवैए से होती है।

उपन्यास में दीपिका माई की डायरी के माध्यम से समलैंगिकता के आगाज से किन्नरत्व के अंजाम तक का वीभत्स सफर धीरे-धीरे आगे बढ़ता है। आर्थिक विपन्नता में दीपक का संघर्ष, समाज के विभिन्न तबकों द्वारा उसका दैहिक शोषण, पारिवारिक दबाव में उसका विवाह और अंततः परिस्थितिजन्य किन्नरत्व की स्वीकार्यता। उपन्यास आपको विद्रूपताओं और विसंगतियों के बीहड़ जंगलों में विचरण हेतु विवश कर देता है। अंतिम दिनों में दीपिका माई का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उसके पूर्व प्रेमी, चेले उसे छोड़कर चले जाते हैं। जिस दीपिका माई ने पहले अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए अपना जीवन होम कर दिया, अंतिम क्षणों में वह अकेली रह गयी और बहुत ही दुखद अंत हुआ।

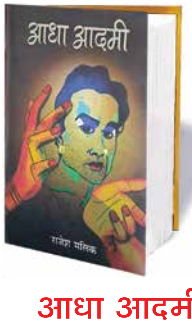

आधा आदमी
राजेश मलिक
प्रकाशक | मनीष पब्लिकेशन
मूल्यः 650 रुपये | पृष्ठः 300

एक बात तय है, संविधान में भले ही थर्ड जेंडर के लिए कोई प्रावधान बना दिया जाए, लेकिन इस वर्ग को भारतीय समाज की स्वीकार्यता प्राप्त करने में अभी समय लगेगा। समाज के अवचेतन मस्तिष्क में बैठा गहरा उपेक्षा, हेयता का भाव किसी कानूनी बैसाखी के सहारे किन्नर समाज के साथ न्याय नहीं कर सकता।

फुटबॉल नहीं व्यायाम

प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टिनो रोनाल्डो ने आइसोलेशन का नया तरीका निकाल लिया है। उन्होंने अपने गैराज में एक अस्थायी जिम बना लिया है। रोनाल्डो ने अपने बच्चों के साथ एक तसवीर साझा कर लिखा है, 'बच्चों, पापा को अपना काम करने दो।' इसे कहते हैं, काम नहीं, व्यायाम का जज्बा।

शर्ट पर सवाल

अथिया शेट्टी की शर्ट उनके नाप से बड़ी है तो क्या हुआ क्रिकेटर केएल राहुल को शर्ट 'अच्छी' लगी। फोटो पर कमेंट डाल कर उन्होंने दोनों के बीच चल रहे रोमांस की पुष्टि भी कर दी।

घर भला

मिलिंद सोमण की पत्नी अंकिता इस बार बिहू पर अपने घर गुवाहाटी नहीं जा पाईं। मिलिंद ने आनन फानन में मुंबई में ही उनके लिए घर पर ही असम सा माहौल बना दिया। परंपरागत गमोसा डाले मिलिंद ने अंकिता के साथ एग फाइट भी की।